R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 I अंक : 20
16 से 31 जुलाई 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

डॉ. मोहन का मनमोहनी प्रयास

क्या मप्र बन पाएगा बिजनेस का हब?

हर बार लाखों करोड़ रुपए के एमयू साइन, फिर भी क्यों खत्म हो जाते हैं करार?

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से औद्योगिक विकास की क्षेत्रीय असमानता होगी दूर?

Government of Madhya Pradesh

INVEST MADHYA PRADESH

MPIDC
M.P. Industrial Development Corporation Ltd.

REGIONAL INDUSTRY CONCLAVE
20th July 2024 | JABALPUR

Narendra Modi
Prime Minister

Dr. Mohan Yadav
Chief Minister

A Confluence of Industries at ' संस्कार धानी ' !!!

REGIONAL INDUSTRY CONCLAVE – JABALPUR

20th July 2024 | Netaji Subhash Chandra Bose Cultural and Information Centre

Register Now

Scan QR code

Conclave Highlights

- Buyer & Seller Meet
- One-2-One Meet
- Thematic Session

Venue Location

Scan QR code

Key Focus Sectors

- Mining & Minerals
- Agriculture & Food Processing
- Aerospace & Defence
- Textile & Garments

Knowledge Partner

EY
Building a better working world

National Partner

CII
Confederation of Indian Industry

www.invest.mp.gov.in

MPIDC(@MPIDC)/Twitter | MP Industrial Development Corporation (MPIDC) | MPIDC I Facebook | MPIDC (@mpidc_gomp) | MPIDC - YouTube

इस अंक में

डायरी

9 | मेरा दर्द न जाने कोई

सुशासन की राह पर चल रही मोहन सरकार के मंत्री और विधायक भी पूर्ववर्ती सरकारों के मंत्रियों, विधायकों की तरह अफसरों से परेशान हैं। इसका खुलासा गत दिनों तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और...

बिजली

11 | अटल गृह ज्योति योजना का...

मप्र बिजली का अवैध उपयोग बिजली कंपनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। खास बात यह है कि सरकार ने गरीबों के लिए जो अटल गृह ज्योति योजना शुरू की है उसका फायदा उठाने के लिए राजधानी की...

विडम्बना

14 | निगम-मंडलों पर वित्त...

मप्र में अधिकांश निगम और मंडल सरकार के लिए सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। अधिकांश निगम-मंडल किसी काम के नहीं रह गए हैं, लेकिन इन पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अब वित्त विभाग ने इन पर लगाम...

विधानसभा

16-17 | सत्र सिमटे... काम पूरे हुए

मप्र का शासन, प्रशासन और यहां की विधानसभा अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल मानी जाती है, लेकिन पिछले दो दशक से मप्र के माननीयों का मन लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा में नहीं लग रहा है। शायद यही वजह है कि पिछले दो दशक से मप्र विधानसभा का कोई भी सत्र...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र के आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगाएगी। आशा की जा रही है कि डॉ. मोहन के मनमोहनी प्रयास से मप्र बिजनेस का हब बनेगा। ऐसा इसलिए कि मप्र में एक समान औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह फॉर्मूला कारगर साबित होगा?

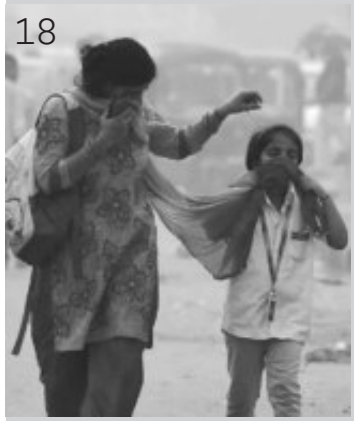

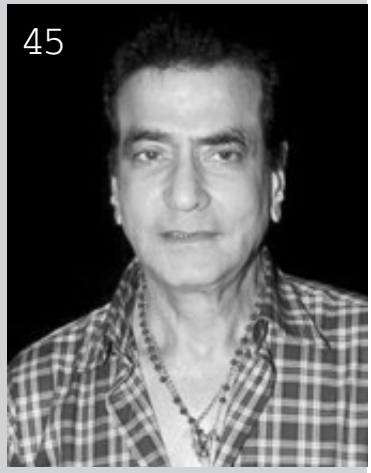

आर्थिकी

30-31 | अबकी बार... सबका ख्याल!

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी। आगामी चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार जनता को कई तरह की सौगात देगी। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। जानकारों का कहना है कि आयुष्मान...

महाराष्ट्र

34 | क्या अजित का साथ...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल ने गत दिनों शरद पवार से मुलाकात की, भुजबल और पवार की इस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाईं जा रही हैं। मुंबई में शरद पवार के आवास...

बिहार

37 | भ्रष्टाचार के पुल

बरसात आने से पहले ही बिहार में पुलों का गिरना सार्वजनिक निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकेदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगाते हैं।

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

जरा तुम दाम तो बोलो...यहां ईमान बिकते हैं...

किसी शायर का एक शेर है...

यहां तहजीब बिकती हैं... यहां फरमान बिकते हैं,
जरा तुम दाम तो बोलो... यहां ईमान बिकते हैं।।

शायर की उपरोक्त पंक्तियां आज सरकारी व्यवस्था में शिष्टाचार बन गई हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हमारी सरकारी व्यवस्था में घुन की तरह चिपक गई है। इन्हें खत्म करने के लिए सरकार जितनी कोशिश करती है, ये उतने ही बढ़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि छोटा भ्रष्टाचार, छोटी रिश्वतखोरी और छोटा अपराध हमेशा शासन-प्रशासन, जांच एजेंसियों, अदालत के निशाने पर आ जाते हैं, जबकि बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर बच जाते हैं या बचा लिए जाते हैं। सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि रिश्वत अकेले नहीं आती... देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, दुख, वेदना, क्रोध, तनाव, चिंता भी नोटों से लिपटी मिलती है। लेकिन विडंबना यह देखिए कि छोटी रिश्वत लेने वालों पर अदालतों का कोप भी जल्दी ही गिरता है। ऐसा ही एक मामला देश के हृदय प्रदेश मप्र की राजधानी में सामने आया है। राजधानी की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी को चार साल कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी लैब अटेंडेंट ने एक प्रकरण की जानकारी भेजने के लिए 600 रुपए की रिश्वत ली थी। 600 रुपए की रिश्वत लेने का मुकदमा 9 साल चला। लोकायुक्त पुलिस ने 600 रुपए की रिश्वत लेने वाले को सजा दिलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रिश्वतखोर ने रिश्वत ली थी, इसलिए उसे अदालत ने सजा दी, सजा होनी भी चाहिए। लेकिन जिस लोकायुक्त ने छोटी सी रिश्वत लेने वाले के खिलाफ जिस संजीदगी से अपना कर्त्तव्य निभाया, अगर वह इसी तरह लोकायुक्त में आईएएस, आईपीएस सहित बड़े-बड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में काम करती तो आज भ्रष्टाचार सरकारी व्यवस्था में शायद ही शिष्टाचार बना होता। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही डॉ. मोहन यादव ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने का निर्देश सभी विभागों को दिया, लेकिन उसके बाद भी 50 आईएएस समेत 274 अधिकारी-कर्मचारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है। दरअसल, जांच एजेंसियां दागी ब्यूरोक्रेट्स पर इस कदर मेहरबान हैं कि उनके खिलाफ वर्षों से जांच चल रही है, लेकिन उन पर आज तक आंच नहीं आई है। उधर मानसून सत्र में विधायक देवेंद्र नारायण सक्सेवार के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे 11 आईएएस, एक डिप्टी कलेक्टर सहित 274 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लोकयुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों में सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में बताया कि विभिन्न विभागों में अभियोजन की अनुमति के 274 मामले पेंडिंग हैं। इनमें जीएडी में 35, राजस्व विभाग में 30, सहकारिता में 8, गृह विभाग में दो, पीडब्ल्यूडी में 8, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 18, फॉरेस्ट में 1, स्वास्थ्य विभाग में 10, नगरीय आवास में 36, जनजातीय कार्य में 3, वाणिज्यिक कर में 5, वित्त विभाग में दो, महिला बाल विकास में 3, कृषि कल्याण में 3, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में दो-दो सहित अन्य नगरीय निकायों में 88 प्रकरण लंबित हैं। सवाल उठता है कि क्या इन अधिकारियों-कर्मचारियों का भ्रष्टाचार 600 रुपया लेने वाले एक कर्मचारी से कम है?

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 20, पृष्ठ-48, 16 से 31 जुलाई, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रमुख संपादकगण
भावना सक्सेना-भोपाल, जय मदानी-भोपाल, देवीराम-इंदौर, हर्ष सक्सेना-भोपाल, दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर, विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा, ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन, टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहगढ़, अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई, इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता
पारस सरावगी (इंदौर) 09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर) 09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर) 098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन) 094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम) 089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा) 075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, , फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

डॉग लायसेंस जरूरी

भोपाल नगर निगम पालतू कुत्तों का लायसेंस बीते 15 साल से बना रहा है। अब तक 1350 से अधिक लायसेंस जारी किए जा चुके हैं। यह पेट डॉग्स की वास्तविक संख्या के मुकाबले काफी कम है। पालतू कुत्ते पालने वालों को बहुत जरूरी है कि वे लायसेंस बनवाएं।

● **लिपिन मिश्रा,** भोपाल (म.प्र.)

स्लम फ्री मप्र

प्रदेश को स्लम फ्री बनाने को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, बावजूद इसके बस्तियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ी है। सबसे ज्यादा झुग्गी वाले टॉप-10 शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ऐसे में जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है उनके लिए चुनौती होगी।

● **राजकुमार साहू,** इंदौर (म.प्र.)

खर्चों पर कैंची

मप्र की एसजीडीपी लगभग 15 लाख करोड़ है, जिसके मुताबिक प्रदेश की कर्ज लिमिट 45,000 करोड़ है। जीएसडीपी में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए ये लिमिट भी लगभग इतनी ही रहेगी। सरकार ने गैरजरूरी खर्चों पर कैंची चलाने वाले मॉडल पर काम शुरू किया है।

● **प्रमोद उपाध्याय,** ग्वालियर (म.प्र.)

छात्रों का भविष्य दांव पर...

नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस नीट परीक्षा की शीर्ष न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। नीट के परिणामों में पहले स्थान पर 67 अभ्यर्थी पाए गए जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र सामने आए जहां से अकेले छह अभ्यर्थी पहले स्थान पर थे। न सिर्फ इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक, बल्कि खुद परीक्षार्थी भी सकते में थे कि ऐसा कैसे हो गया। इसके पीछे अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क) का अजीब खेल सामने आया जो एनटीए ने समय की क्षतिपूर्ति करने के लिए 1563 छात्रों को दे दिया था। इन सबसे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

● **आनंद पाठक,** सीहोर (म.प्र.)

लोकतंत्र का सम्मान जरूरी

लोकतंत्र में शुचिता और पारदर्शिता की मिसाल पेश करने के बजाय नेता और राजनीतिक दल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। सार्वजनिक तौर बिना झिझक माफियाओं से गलबहियां डालना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर नेताओं के संवेदना दिखाकर वोट बटोरने का प्रयास करने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया की जागरूकता के इस दौर में यह प्रवृत्ति कांग्रेस और भाजपा में कम नजर आती है, किंतु अन्य दलों में जरा भी लोकलाज नहीं बची है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को उसका सम्मान करना चाहिए।

● **देवेंद्र सिंह,** नई दिल्ली

56 फीसदी पर कृषि

पेड़ पर्यावरण के साथ-साथ खेतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इनकी निगरानी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते कि वे कहां हैं, इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, या वे जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से कैसे प्रभावित होते हैं। देश का 56 फीसदी हिस्सा कृषि भूमि के रूप में है, वहीं महज 20 फीसदी पर जंगल है। हालांकि, भारत में जंगल और पौधारोपण के बीच अंतर बेहद स्पष्ट नहीं है।

● **संजय जैन,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

गुल खिलाएगी नीतीश-राय की मुलाकात?

कुछ ही महीनों बाद झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल जहां अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं कई पार्टियों के नेता भी चुनाव मैदान में उतरने के पहले राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। इस बीच जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपने बचपन के दोस्त और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा है कि सरयू राय आगामी विधानसभा चुनाव में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में एक ओर जहां नीतीश कुमार से सरयू राय की मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के राज्यपाल रघुवरदास का कार्यकाल अभी बचा है, लेकिन इससे पहले झारखंड की राजनीति में उनके वापस लौटने की चर्चा भी जोरों पर है। रघुवरदास के कई समर्थक उनकी वापसी की तिथि से लेकर राज्य की राजनीति में सक्रिय होने को लेकर कई दावे कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सरयू राय को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का साथ मिल सकता है।

फिर सक्रिय हो सकती हैं वसुंधरा

पिछले साल जबसे राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है तब से सत्ता और संगठन से दूरी बनाकर चल रही वसुंधरा राजे से गत दिनों अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलने पहुंचे। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच प्रदेश के कई सियासी मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी दिनों में वसुंधरा राजे पार्टी की गतिविधियों में एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे सकती हैं। वहीं सबसे ज्यादा इस बात की अटकलें हैं कि क्या वसुंधरा राजे से भजनलाल शर्मा रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं? इस बीच मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद भाजपा सरकार और संगठन में सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बीते कुछ समय से प्रदेश की भाजपा सरकार और संगठन से दूरी देखी जा रही थी, लेकिन विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन वसुंधरा विधानसभा पहुंची थीं। इसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे।

फिर साथ आए इनेलो और बसपा

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नेताओं का दलबदल और दूसरे दलों के आपस में गठबंधन और जोड़तोड़ की खबरों से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले दिनों हुई इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला और बसपा प्रमुख मायावती की मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन होगा। इस बीच अभय चौटाला ने गठबंधन का ऐलान कर कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन तय हो गया है। अब दोनों दल मिलकर आगामी चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के बीच हुए सीटों के बंटवारे के तहत हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 पर चुनाव लड़ेगी जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन स्वार्थी हितों पर आधारित नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि बसपा और इनेलो सोच रही हैं कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा और कमजोर वर्ग कैसे सशक्त होगा। इसलिए हरियाणा में हमने आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि हाल में बसपा सुप्रीमो मायावती और चौटाला ने गठबंधन के सबंध में बैठक की थी।

राठौड़ को मिलेगा मौका!

राजस्थान में भाजपा की नजर अब पांच विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। ऐसे में एक ओर जहां हाल ही में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हरियाणा का पार्टी प्रभारी बनाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी सियासी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अब राठौड़ का राजनीतिक भविष्य और अगली भूमिका तय हो जाएगी और उनका राजनीतिक वनवास भी समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान भाजपा के दोनों दिग्गज नेता सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद दोनों नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर काफी सवाल उठे और कई तरह की राजनीतिक चर्चा भी चली। इस बीच राठौड़ और पूनिया दोनों बीते दिनों दिल्ली में पार्टी आलाकमान के पास अचानक मुलाकात करने पहुंचे। इसको लेकर सियासत में जमकर हलचल मची। राजनीतिक जानकार दोनों की मुलाकात को लेकर उनकी अगली भूमिका के कयास लगाने लग गए।

कौन होगा सियासी वारिस?

उप्र में आए लोकसभा के चुनावी नतीजों ने सपा को एक नई सियासी उम्मीद जगा दी है। सूबे की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतने में कामयाब रही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद लखनऊ के बजाय दिल्ली को सियासी मैदान चुन लिया है। उनके इस्तीफे के बाद करहल विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव का सियासी वारिस कौन होगा? गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने करहल सीट से 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और वे विधायक चुने गए थे, लेकिन अब कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ दी है। उनके इस्तीफे के बाद करहल उपचुनाव में सपा के उम्मीदवारों की दावेदारी भी तेज हो गई है। जातिगत गणित से हर बार करहल की सियासत सपा के अनुकूल रही है।

पति को बना दिया वसूली भाई

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक महिला आईपीएस अधिकारी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। मैडम चर्चा का केंद्र इसलिए बनी हुई हैं कि जबसे ये विंध्य क्षेत्र के एक जिले की कप्तान बनी हैं, तबसे इन पर लक्ष्मी बटोरने का भूत इस कदर सवार हुआ है कि वे किसी भी हद तक जाने में झिझक नहीं करती हैं। गौरतलब है कि मैडम जिस जिले में कप्तानी कर रही हैं, वह जिला कोयला और बिजली के लिए ख्यात है। यहां कई तरह की अनैतिक और अवैध गतिविधियां भी चलती हैं। सूत्रों का कहना है कि मैडम की जबसे यहां पदस्थापना हुई है, उन्होंने अनैतिक और अवैध गतिविधियों को रोकने की बजाय उन्हें कमाई का जरिया बना लिया है। लेकिन अब तो मैडम ने हद ही कद दी है। उनके करीबियों का कहना है कि मैडम ने दलाली के लिए अपने पति को ही काम पर लगा दिया है। बताया जाता है कि मैडम के पति पड़ोस के राज्य में सेल्स टैक्स में नौकरी करते हैं। लेकिन लक्ष्मी बटोरने में मैडम इस तरह अंधी हो गई हैं कि उन्होंने बिना सोचे-समझे ही अपने पति को वहां से बुलाकर दलाली के काम में लगा दिया। सूत्र बताते हैं कि मैडम के पति जहां से गुजरते हैं, वहां लोग कहने लगते हैं कि देखो-देखो वसूली भाई आ रहे हैं। मैडम की ऐसी ही करतूतों ने प्रदेश की नौकरशाही को कलंकित कर रखा है। अब देखना यह है कि मैडम की ऐसी कारगुजारियों पर सरकार का एक्शन क्या होता है?

तोड़ बट्टा में माहिर साहब

उज्जैन संभाग के एक जिले के पुलिस कप्तान साहब ने तोड़ बट्टा कराने का जिम्मा इस कदर संभाला है कि लोग उनसे परेशान हो उठे हैं। दरअसल, साहब बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी के फटे में टांग फंसा देते हैं और उसके बाद जमकर वसूली करते हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब पूर्व मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों में से एक हैं। उन पर पूर्व मुख्यमंत्री का वरदहस्त ऐसा था कि वे जमकर मनमानी करने के आदी हो गए हैं। अब सरकार बदल गई है, फिर भी साहब की आदत वैसी की वैसी ही है। सूत्र बताते हैं कि साहब ने जिले में अपने आधा सैकड़ा मुखबिर छोड़ दिए हैं। ये मुखबिर साहब को सूचित करते हैं कि कहां पर मामला फंसा हुआ है। फिर क्या, साहब उस मामले में अपनी टांग दे देते हैं। फिर शुरू होता है सुलह कराने का सिलसिला। इसके लिए साहब मोटी रकम लेते हैं। मामला भले ही किसी भी विभाग का हो, लेकिन साहब हिचकिचाते नहीं हैं। बताया जा रहा है कि साहब की इस कार्यप्रणाली से कस्टम और नारकोटिक्स के अधिकारी भी परेशान हैं। गौरतलब है कि साहब जिस जिले की कप्तानी कर रहे हैं, वह जिला नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है।

अफसरों की करतूत पर फिरा पानी

महाकौशल क्षेत्र के खनिज संपदा से भरे एक जिले में वन भूमि को राजस्व भूमि बनाने के लिए उच्च स्तर पर बड़ा खेल खेला जा रहा था। लेकिन इस काम में जुटे अफसरों की करतूत पर पानी फिर गया है। सूत्रों का कहना है कि तकरीबन 120 एकड़ की वन भूमि को राजस्व भूमि बनाने के लिए एक खनन कारोबारी के इशारे पर काम किया जा रहा था। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन इसमें तकनीकी पेंच इस कदर फंसा है कि अफसरों के हाथ-पांव सुन्न हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में वन विभाग के अफसरों की भूमिका तो संदिग्ध है ही, साथ ही उच्च स्तर पर इसमें बड़ी लेनदेन भी की गई है, ताकि वन भूमि को राजस्व भूमि बनाया जा सके। यह मामला राज्य सरकार के पास भी पहुंच गया था, लेकिन सरकार ने मंत्रालय से इसे चलता कर दिया। जानकारों का कहना है कि खनन कारोबारी के साथ मिलकर वन विभाग के साथ ही प्रदेश सरकार के कुछ अफसर उक्त वन भूमि को राजस्व भूमि करवाने के लिए वर्षों से हाथ-पांव मार रहे हैं। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में इस दिशा में तेजी से काम हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद मामला लटक गया। सूत्रों का कहना है कि अब वर्तमान सरकार में कुछ लोग खनन कारोबारी से मोटी राशि लेकर वन भूमि को राजस्व भूमि कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन तकनीकी पेंच सामने आने के बाद सबकी करतूतों पर पानी फिर गया है।

अब शिक्षाविद् पिलाएंगे पानी

जिस शिक्षाविद् को सरकार ने प्रदेश में शिक्षा की लौ जलाने के लिए नौकरी पर रखा था, अब वे प्रदेशवासियों को पानी पिलाएंगे। यह आश्चर्य होने का विषय है, लेकिन आप तनिक भी आश्चर्यचकित न हों। मामला प्रदेश के एक बड़े विभाग से संबंधित है। इस विभाग में आने के लिए शिक्षाविद् हाथ-पांव मार रहे थे। वहीं विभागीय मंत्री भी चाहती थीं कि शिक्षाविद् उनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन सरकार के मुखिया की सख्ती आड़े आ रही थी। ऐसे में एक दलाल ने मंत्री और शिक्षाविद् की मंशा को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद कागजी घोड़े दौड़ाने का खेल शुरू हुआ। दलाल ने रात-दिन मेहनत करके शिक्षाविद् को मंत्री के साथ अटैच करवाने के लिए खूब भागदौड़ की। इसका नतीजा यह हुआ कि शिक्षाविद् को पानी पिलाने वाले विभाग में अटैच कर दिया गया है। इस मामले को देखकर प्रशासनिक वीथिका में लोग चटखारे लेकर कह रहे हैं कि लगता है अब शिक्षाविद् पढ़ाई-लिखाई छोड़कर लोगों को पानी पिलाएंगे। लोग कुछ भी कहें, मंत्रीजी ने शिक्षाविद् को अपने यहां नौकरी पर रख ही लिया।

कलेक्टरी का रास्ता

जबसे इस बात की हवा उड़ी है कि प्रदेश में सरकार बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करने जा रही है, इस फेरबदल के तहत कई जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे, तबसे आईएएस अधिकारी कलेक्टर बनने की जुगाड़ में जुट गए हैं। सब इसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ ने भोपाल में तो कुछ ने दिल्ली में जुगाड़ लगानी शुरू कर दी है। वहीं कुछ ऐसे आईएएस भी हैं, जिनकी न तो भोपाल में कोई बड़ी जुगाड़ है, और न ही दिल्ली में राजनीतिक पैठ। ऐसे लोग अब कलेक्टर बनने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला अपना रहे हैं। इसके लिए वे उस माध्यम को ढूंढ रहे हैं, जिसको हार-फूल चढ़ाकर याया लक्ष्मीनारायण देकर अपनी कलेक्टरी पक्की कर सके। सूत्र बताते हैं कि अफसरों की मंशा को भांपते हुए कुछ दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर अफसरों को विश्वास नहीं है। बताया जाता है कि जैसे-जैसे दिन गुजरता जा रहा है, कलेक्टर बनने की आस लगाए बैठे अफसरों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। वहीं जिन अफसरों का जुगाड़ लग गया है, वे चैन की सांस ले रहे हैं और जल्द से जल्द सूची निकलने का इंतजार कर रहे हैं।

आबकारी में खुली भ्रष्टों की कुंडली

मप्र के सबसे कमाऊ विभागों में शामिल आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। इस जांच के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, शराब कंपनी मेसर्स शिवहरे ग्रुप के यहां 10 वर्ष पहले आयकर छापे से मिले दस्तावेजों के आधार पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जांच कर रही है। इस जांच की जद में कुछ आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक अन्य अधिकारी-कर्मचारी सहित 25 से अधिक लोग आ रहे हैं। पुलिस की ओर से आबकारी विभाग से उस दौरान अलग-अलग जिलों में पदस्थ रहे अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी, जो कि विभाग ने मई में पुलिस को सौंप दी है। अब इन अधिकारियों के बयान लिए जाएंगे। इसके बाद इनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान एक कोडेड डायरी बरामद की गई थी, जिसमें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का विवरण था। इस डायरी ने आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को संदेह के घेरे में ला दिया है। इनमें भोपाल में वर्तमान में पदस्थ एक सहायक आयुक्त भी शामिल हैं, जिनकी भूमिकाओं और हितों के टकराव की भी जांच की जा रही है। बता दें कि आयकर विभाग ने शराब कंपनी से जुड़े विभिन्न स्थानों पर यह छापेमारी 10 वर्ष पहले की थी। लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कुछ अधिकारियों का पूरा नाम भी नहीं लिखा। जिनका पूरा नाम लिखा है तो पदनाम नहीं है। बांगड़े साहब, शर्मा जी, विश्वकर्मा साहब, पांडेय साहब लिखा है। ऐसे में जांच उलझ रही थी। इस कारण इनका पूरा नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल और मोबाइल नंबर मांगे थे। बताया जा रहा है कि इस तरह के उपनाम वालों की पदस्थापना उस दौरान बैतूल में थी।

लोकायुक्त टीम ने आयकर विभाग की गोपनीय रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है। वहीं आबकारी विभाग से सख्त लहजे में पूछा है कि शर्मा जी, बांगड़े साहब कौन हैं? उनका ड्राइवर कौन था? विश्वकर्मा साहब, पांडेय बाबू कौन हैं? लोकायुक्त ने ये सवाल आयकर विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट की जांच के बाद पूछे हैं। यह रिपोर्ट 2016 में मप्र और छत्तीसगढ़ में शराब के एक व्यवसायी के यहां तलाशी के दौरान जब्ती से संबंधित हैं। इस जांच के केंद्र में कई गंभीर आरोप और वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने 28 फरवरी 2013 से 3 मई 2013 के दौरान आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ अधिकारी की भी जानकारी मांगी थी। इसके अतिरिक्त अलग-अलग समय डीईओ ग्वालियर, 16 दिसंबर 2015 को राज्य उड़नदस्ता में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी की जानकारी मांगी गई थी। सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों ने अपने-अपने यहां अलग-अलग समय पदस्थ रहे अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी भेज दी है। पूरे मामले की जांच लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना ग्वालियर द्वारा की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान एक कोडेड डायरी बरामद की गई थी, जिसमें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का विवरण था। इस डायरी ने आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को संदेह के घेरे में ला दिया है। इनमें भोपाल में वर्तमान में पदस्थ एक सहायक आयुक्त भी शामिल हैं, जिनकी भूमिकाओं और हितों के टकराव की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अलग-अलग तारीखों पर ग्वालियर, शिवपुरी और अन्य स्थानों पर तैनात अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जिसमें ग्वालियर में शर्मा के बारे में जानकारी मांगी गई है और यह भी पूछा गया है कि किस अधिकारी-कर्मचारी को बांगरे साहब के नाम से जाना जाता था।

7 जनवरी 2016 को मप्र, उप्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान में एक बड़े शराब कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला था। 55 परिसरों पर तलाशी ली गई थी। इस छापे में कई करोड़ नकद, जेवर, जमीन, कॉलेज और कोल्ड स्टोरेज में निवेश के अलावा अन्य संपत्तियां भी बरामद हुईं थीं। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान ने आयकर रिपोर्ट पर जानकारी मांगने के लिए आबकारी विभाग को नोटिस भेजा है, उन्होंने विभाग से 28 फरवरी 2013 और 3 मई 2013 को आबकारी आयुक्त के पद के बारे में जानकारी भी मांगी है।

● **सुनील सिंह**

आखिरकार मिल गया जांच अधिकारी

8 साल पहले इंदौर जिले के शराब ठेकों में 42 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले सहित अन्य फर्जीवाड़ों की जांच करने के लिए आखिरकार जांच अधिकारी भी मिल गया है। गौरतलब है कि पूर्व में स्नेहलता श्रीवास्तव इस मामले की जांच कर रही थीं, लेकिन उनके जाने के बाद सालों तक कोई जांच अधिकारी नियुक्ति नहीं किया गया था। अब एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स रजनीकांत सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सवाल उठता है कि जिन अधिकारियों ने कारोबारियों के साथ मिलकर चपत लगाई है, उनसे वसूली कर वह रकम सरकार को वापस मिल पाएगी। मामला कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मानसून सत्र में 70 प्रतिशत सवाल इसी मुद्दे पर थे। मप्र का आबकारी घोटाला सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि भोपाल, कटनी, रीवा, दमोह समेत आधा दर्जन से अधिक जिलों में भी फैला है। इंदौर में डेढ़ साल पहले हुए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट (एफडीआर) के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच की थी, पर जांच सही नहीं हुई। अब दोबारा जांच की जा रही है। मप्र में फर्जी एफडीआर को लेकर करीब 20 मामलों में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है। 5 मामलों में ही 77 करोड़ का घपला है, पर आज तक कोई बड़ा अफसर या नेता गिरफ्त में नहीं आ सका। इन्हें बचाने में पूरा सिस्टम ही लग गया है। हालांकि, एक मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। जानकारों का कहना है कि ईडी की जांच सही दिशा में हुई तो दिल्ली की तर्ज पर मप्र में भी कई नेता और बड़े अफसर कानून के शिकंजे में आ सकते हैं।

मेरा दर्द न जाने कोई

सुशासन की राह पर चल रही मोहन सरकार के मंत्री और विधायक भी पूर्ववर्ती सरकारों के मंत्रियों, विधायकों की तरह अफसरों से परेशान हैं। इसका खुलासा गत दिनों तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों की क्लास लगाई और सामंजस्य बनाकर काम करने के लिए दोनों को एकसाथ बैठाया। इस बैठक में कई मंत्रियों ने कहा कि विभाग में अफसरों की भरमार है। हमारे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। वहीं विधायकों के साथ एचओडी को बैठाया गया तो विधायकों की भी शिकायत सामने आई कि जिले में अफसर उनकी सुनते नहीं हैं। अफसर के मंत्री की सुनते हैं। स्थिति यह है कि न मंत्री और न ही अफसर हमारे दर्द को समझ पा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ और कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि वे मंत्री और विधायकों को पूरा तवज्जो दें।

बंगला खर्च कैसे चले

सूत्र बताते हैं कि कुछ मंत्री इससे परेशान हैं कि उनके बंगले का खर्च कैसे चले। सूत्र बताते हैं कि इस संदर्भ में कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। दरअसल, विभागों में अफसरशाही ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। पहले विभाग को निगम चलाते थे, लेकिन अब फाइलें मंत्रियों के पास आती ही नहीं हैं। ऐसे में उनका खर्चा कैसे चलेगा। पूर्व में मंत्री निगम-मंडलों से पैसा निकाल लेते थे और उससे बंगले का खर्चा चलाते थे।

अफसरों में खींचतान

एक तरफ जहां मंत्री अफसरों से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अफसरों के बीच भी खींचतान मची हुई है। अफसरों के बीच मची खींचतान के किस्से आए दिन भोपाल से लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि सरकार कम्फर्ट जोन में नहीं है। न मंत्रियों और अफसरों, और न ही अफसरों की आपस में पटरी बैठ पा रही है। उधर, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कई तरह के मामले आ रहे हैं। इससे सरकार की साख गिर रही है। प्रदेश के वर्तमान हालात को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार पटरी पर नहीं बल्कि भटकी हुई है।

दिल्ली की ओर रुख

मप्र कैडर के कुछ अधिकारी दिल्ली की ओर रुख करने वाले हैं। इनमें पहला नाम है 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी का। अभिषेक तिवारी वर्तमान में सागर में एसपी हैं। ये एनटीआरओ (नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च ऑर्गनाइजेशन) दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। वहीं 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह ने केंद्र में जाने के लिए आवेदन किया है। सिंह वर्तमान में जबलपुर के एसपी हैं।

जल्द आएगी तबादले की सूची

प्रदेश में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। इसमें करीब डेढ़ दर्जन जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस सूची में खासतौर पर उन कलेक्टरों को बदला जाएगा, जो प्रमोटी होने के साथ ही दो या उससे अधिक जिलों में बतौर कलेक्टर पदस्थ रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ वो कलेक्टर हैं, जिनके कामकाज से सरकार खुश नहीं है। उनके स्थान पर 2015 बैच के आईएएस अफसरों को जिलों में पदस्थ किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि तबादला सूची के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुख्य सचिव वीरा राणा और अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा से पहले दौर की चर्चा हो चुकी है। मंत्रालय सूत्रों की मानें तो इस फेरबदल में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर शिवपुरी रविंद्र चौधरी, कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर राजगढ़ हर्ष दीक्षित, कलेक्टर सीहोर प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर नीमच दिनेश जैन, कलेक्टर धार प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर खंडवा अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर देवास ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर बुरहानपुर भव्या मित्तल, कलेक्टर नरसिंहपुर शीतला पटले, कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद, कलेक्टर छतरपुर संदीप जीआर, कलेक्टर सागर दीपक आर्य, कलेक्टर डिंडोरी विकास मिश्रा आदि का स्थानांतरण किया जा सकता है।

कलेक्टरों की रैंकिंग

सरकार कलेक्टरों की रैंकिंग कराएगी। जिन अफसरों की परफॉर्मेंस खराब होगी उन्हें जिले से बाहर किया जाएगा। यानी खराब प्रदर्शन वाले कलेक्टरों को दूसरे जिलों की कमान नहीं सौंपी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव वीरा राणा को निर्देशित किया है। सूत्रों का कहना है कि गत दिनों एक समीक्षा बैठक में कुछ कलेक्टरों से जब मुख्यमंत्री ने योजनाओं के संदर्भ में जानना चाहा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसलिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों की फरफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिग कराने का निर्देश दिया है।

प्रस्ताव अधर में

राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में डीपीसी के लिए जाने वाला प्रस्ताव अधर में लटका हुआ है। यह प्रस्ताव मई में केंद्र सरकार के पास जाना था, लेकिन अभी तक उसे नहीं भेजा गया है। इस बार 1997 बैच के 4 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा के लिए डीपीसी होनी है।

अफसरों के अफसाने

प्रदेश में इन दिनों कुछ अफसरों के किस्से-कहानियां चर्चा का विषय बने हुए हैं। ग्वालियर-चंबल अंचल के एक एसपी को गत दिनों सीएम ने जमकर डांट पिलाई। दरअसल, साहब के खिलाफ बिल्डरों ने शिकायत की है कि वे उन पर अड़ी डालते हैं। बकायदा इसके लिए कप्तान साहब ने दलाल भी सक्रिय कर रखा है। वहीं इसी अंचल के आईजी के बारे में कहा जा रहा है कि वे ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं। साहब वॉट्सएप पर ही ऑफिस चला रहे हैं।

गोरखधंधे चरम पर

प्रदेश में इस समय कोयले की दलाली तेजी से चल रही है। एक नामचीन कंपनी ने तो शहडोल में अपना एक लाइजिनिंग अफसर सक्रिय कर रखा है। जिले में अवैध खनन हो रहा है, यह सभी को पता है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शहडोल से अवैध खनन कर ले जाया जा रहा कोयला नागपुर की कोयलरी में एक नंबर में बिक रहा है। उधर, अनूपपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रेलवे की पटरियों सहित अन्य कबाड़ को संस्कारधानी जबलपुर का एक कबाड़ी चोरी करके अवैध रूप से बेच रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन कबाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।

● राजेंद्र आगाल

चैलेंजर 3500 विमान खरीदेगी सरकार

करीब 3 साल बाद मप्र सरकार नया विमान खरीदने जा रही है। मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3500 विमान को खरीदने का फैसला किया है। मप्र सरकार के पास 2021 से कोई विमान नहीं था। तब से ही नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। दो कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए थे। इसमें से चैलेंजर 3500 का प्रस्ताव एल-1 कैटेगरी में चुना गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गत दिनों हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मप्र सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर इंक के चैलेंजर 3500 मॉडल को 233 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। दरअसल, 6 मई 2021 को ग्वालियर मैं लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कंपनी ने उस विमान को बियॉन्ड रिपेयर करार दिया। यानी उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। उसके बाद से राज्य सरकार के पास कोई विमान नहीं था और नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस दौरान कनाडा की कंपनी की बोली सबसे कम रही। साथ ही निविदा शर्तों में जो आवश्यकताएं बताई गई हैं, उसे चैलेंजर 3500 पूरी करता है। नया चैलेंजर 3500 विमान 20 माह में मिलेगा। सरकार की आवश्यकता के अनुसार कंपनी इस विमान को आठ सीटर बना रही है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि डॉ. मोहन यादव को अगले 20 माह किराए के विमान में ही उड़ान भरनी होगी।

चैलेंजर 3500 अपनी श्रेणी में सबसे अधिक एडवांस तकनीक से बना है। इसमें इंडस्ट्री का पहला वॉयस-कंट्रोल्ड केबिन और नए जमाने की सीटें लगी हैं। चैलेंजर 3500 विमान स्थिरता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करता है, जिसके सहारे आप किसी भी मौसम में लंबी उड़ान भर सकते हैं। चैलेंजर 3500 बेहतरीन केबिन अनुभव प्रदान करता है। इसे 2022 रेड डॉट के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यह विमान के इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन होने की पुष्टि करता है। इस विमान की खासियत यह है कि 4,850 की कम से कम ऊंचाई और 41 हजार फीट की अधिकतम ऊंचाई पर भी यह जमीन पर होने का अहसास देता है। एयर सर्कुलेशन की तकनीक ऐसी है कि सिर्फ दो मिनट में यह ताजा हवा से केबिन को भर देता है। इससे यात्रियों के लिए ताजगी भरा अहसास बना रहता है। इसके बाद भी केबिन में कोई शोर सुनाई नहीं देगा। इसे इस सेग्मेंट में उपलब्ध सभी विमानों में सबसे स्मार्ट केबिन कहा गया है, जहां वायरलेस चार्जिंग से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उधर, कांग्रेस ने चार साल पहले दुर्घटनाग्रस्त विमान के मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस विमान से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हवाई सफर करते थे, उसका बीमा आखिर क्यों नहीं कराया गया था। जिससे चार साल से वह विमान ग्वालियर में कबाड़ के रूप में पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा कहते हैं कि वर्ष 2021 से मप्र सरकार विमान विहीन थी। किराए के विमान पर मुख्यमंत्री घूमते थे। कैबिनेट ने विमान खरीदने का फैसला किया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मगर इतना बड़ा विमानन विभाग होने के बाद इतनी बड़ी लापरवाही की गई। विमान का बीमा तक नहीं कराया गया। उस सरकारी विमान में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री घूमते रहे हैं और बगैर मेंटेनेंस वाले विमान में उनकी जान को खतरा था। सरकार को बताना चाहिए कि उस दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा किस अधिकारी ने नहीं कराया था और बीमा नहीं होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने पर विमान भंगार की स्थिति में खड़ा है। विमान सरकार खरीदे अच्छी बात है मगर जो 233 करोड़ रुपए में नया विमान खरीदा जा रहा है, उसका पैसा तो आम आदमी की जेब से ही जाएगा। जो विमान इस समय ग्वालियर में डैमेज पड़ा है, वह कमलनाथ सरकार के दौरान खरीदा गया था। 62 करोड़ में खरीदे गए इस विमान के डैमेज होने के बाद इस प्लेन के डैमेज पार्ट को बेचने के लिए विमानन विभाग तैयारी कर चुका है। पूर्व में इसे अमेरिका की टेक्सट्रान कंपनी को ही बेचने की तैयारी थी जिससे यह विमान खरीदा गया था। कोरोनाकाल में 6 मई 2021 को यह प्लेन गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर आ रहा था जो विमानतल पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के समय यह रनवे से करीब 300 फीट पहले लगे अरेस्टर बैरियर से टकरा गया था। तब से विमान वहीं खड़ा है। विमान के कॉकपिट के आगे का हिस्सा, प्रॉपलर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 2 इंजन वाला किंग एयर बी-250 (टर्बोप्राप) में 9 यात्री तथा दो पायलट की बैठने की क्षमता थी। विमान द्वारा मई 2021 तक 210 घंटा और 2 मिनट की उड़ानें की गईं।

● **रजनीकांत पारे**

3 साल में 438 करोड़ खर्च हो गए किराए में

प्रदेश सरकार के पास अपना विमान न होने के कारण किराए के विमान से काम चलाना पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि 6 मई 2021 को सरकारी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से सरकार ने 4 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर विमान ले रखा है। इस तरह 6 मई 2024 तक सरकार ने विमान के किराए में ही 438 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ने अपना विमान खरीदने में इतनी देर क्यों लगा दी। जबकि उप्र सरकार के पास 3 विमान हैं, जिनमें से 2 सरकार के और 1 किराए पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 विमान है जिसमें से 1 सरकार का और 1 किराए पर है। लेकिन मप्र सरकार का काम किराए के एक ही विमान से चल रहा है। देर से ही सही सरकार ने नया विमान खरीदने की तैयारी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि तय समय पर मप्र सरकार को नया विमान मिल जाएगा और रोजाना 4 रुपए दिए जा रहे किराए से निजात मिलेगी।

अटल गृह ज्योति योजना का दुरुपयोग

मप्र बिजली का अवैध उपयोग बिजली कंपनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। खास बात यह है कि सरकार ने गरीबों के लिए जो अटल गृह ज्योति योजना शुरू की है उसका फायदा उठाने के लिए राजधानी की पॉश कॉलोनियों में बिजली चोरी का खेल चल रहा है। विद्युत वितरण कंपनियों की आशंका इसलिए बढ़ी है कि 2 हजार वर्ग फीट से बड़े भूखंड पर बने मकानों में भी बिजली की खपत 150 यूनिट ही हो रही है। इसलिए बिजली कंपनियां अब पॉश कॉलोनियों के 20 फीसदी कनेक्शन की जांच कराएगी। गौरतलब है कि मप्र में उपयोग से अधिक बिजली का उत्पादन होता है। इसलिए उपयोग से अधिक जो बिजली होती है उसे दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। लेकिन उसके बाद भी मप्र की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में रहती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी और लाइन लॉस है। लाइन लॉस को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बिजली चोरी पर भी लगाम कसी जा रही है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

बिजली चोरी, लाइन लॉस कम करने और बिजली कंपनियों को घाटे से उभारने के लिए अब बिजली कनेक्शनों की जांच अलग तरह से होगी। पहली बार बिजली कंपनी इस तरह का प्रयोग कर रही है। इसके तहत महंगी कलेक्टर गाइडलाइन वाली लोकेशन को चिह्नित किया जा रहा है। हर शहर की महंगी कलेक्टर गाइडलाइन वाली कॉलोनियों के 20 फीसदी कनेक्शन की जांच की जाएगी। इसमें कम बिजली बिल वाले कनेक्शन की जांच होगी। 2026-27 तक के लिए कंपनियों ने लाइन लॉस के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्व क्षेत्र ने 86 फीसदी बिलिंग और 100 फीसदी संग्रहण के साथ 14 फीसदी लाइन लॉस का लक्ष्य बनाया है। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र ने 88 फीसदी बिलिंग 100 फीसदी संग्रहण के साथ 12 फीसदी लाइन लॉस का लक्ष्य बनाया है। वहीं मध्य क्षेत्र में 86 फीसदी बिलिंग 100 फीसदी संग्रहण के साथ 14 फीसदी लाइन लॉस का लक्ष्य बनाया है।

गौरतलब है कि सरकार अटल गृह ज्योति योजना के तहत बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। इसके तहत प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली खपत पर सिर्फ 100 रुपए बिजली बिल देना होगा। इस योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में इस योजना के लागू होने के बाद योजना का फायदा उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए अब बिजली कंपनी ऐसी पॉश कॉलोनियों को चिह्नित कर रही है, जहां 2 हजार वर्ग फीट से अधिक के मकान बने हुए हैं, फिर भी बिजली बिल 150 यूनिट आ रहा है। ऐसी महंगी कलेक्टर गाइडलाइन वाली कॉलोनियों की जांच की जाएगी। बिजली कंपनी का दावा है कि सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत सरकार हर साल बिजली कंपनियों को सब्सिडी जारी करती है। इसके तहत इस साल सरकार ने 5866 करोड़ 26 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की है। सरकार हर साल बिजली कंपनियों को 24 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दे रही है। इसके बाद भी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इसको देखते हुए अब बिजली कंपनियों को अपना लाइन लॉस कम करने और बिजली चोरी रोकने का टारगेट मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने भी दिया है।

सबसे अधिक लाइन लॉस पूर्व क्षेत्र में

प्रदेश में सबसे अधिक लाइन लॉस पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में होता है। पूर्व क्षेत्र में 27.40 फीसदी लाइन लॉस होता है। उसके बाद मध्य क्षेत्र में 24.67 फीसदी और पश्चिम क्षेत्र में 11.61 फीसदी लाइन लॉस होता है। प्रदेश की बिजली कंपनियों को मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने साल 2026-27 तक 15 फीसदी तक लाइन लॉस कम करने का टारगेट दिया है। लाइन लॉस कम करने के लिए बिजली कंपनियां बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबल बिछा रही हैं। इसके अलावा प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इन व्यवस्थाओं से बिजली चोरी रुकेगी और लाइन लॉस भी कम होगा। नियमित बिजली बिल जमा करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को इससे फायदा भी मिलेगा।

टीकमगढ़ में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं। गर्मी के मौसम में लगातार बढ़ती खपत के बावजूद बिल रीडिंग कम आने पर विभाग को शक हुआ, तो छापेमारी शुरू की गई। इस दौरान कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। अधिकारियों ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए मीटर जब्त किए और जांच के लिए भेज दिए। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को मीटर से छेड़छाड़ कर कम रीडिंग करने के नए-नए तरीके देखने को मिले। एक मकान मालिक ने तो मीटर में छोटा सा छेद करने के बाद इंजेक्शन की मदद से डिस्प्ले बटन पर एसिड डाल दिया था, जिससे डिस्प्ले खराब हो गई थी। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता शुभम त्यागी ने कहा कि शहर में बिजली का लोड लगातार बढ़ रहा था, लेकिन विक्रय यूनिट पहले जितनी ही बनी हुई थी। यह साफ था कि बिजली की चोरी हो रही है। जिसके बाद इंदिरा कॉलोनी, शेखों का मोहल्ला, सुधा सागर, कटरा बाजार और लक्कड़खाना में छापेमारी की गई। इस दौरान बिजली चोरी के 10 मामले पकड़ में आए। कई मकान ऐसे थे, जहां तमाम लाइट से चलने वाले उपकरण होने के बावजूद महीने का बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए आ रहा था। उन्होंने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में एक चार मंजिला मकान में दो एसी, चार कूलर, बोर, गीजर, टीवी, फ्रिज समेत लाइट से चलने वाले तमाम उपकरण थे। इस मकान में 15 किलोवाट का लोड था, लेकिन पिछले एक साल से बिजली बिल केवल 100 रुपए प्रतिमाह आ रहा था। जांच में पता चला कि मकान मालिक ने मीटर में छेड़छाड़ की है। उसने मीटर में सीरिंज की मदद से डिस्प्ले बटन पर एसिड डाल दिया था, जिससे डिस्प्ले खराब हो गई। मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वहीं मीटर को जब्त कर लिया गया है।

● **विकास दुबे**

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में मप्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो विभाग पूरी राशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अनुपूरक बजट क्यों दिया जा रहा है। इस गलती से वित्तीय बोझ बढ़ेगा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में गृह विभाग, वित्त विभाग, भू-राजस्व, जिला प्रशासन, कृषि कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, पंचायत एवं महिला बाल विकास को जो मूल बजट मिला था, वे उसे तो खर्च ही नहीं कर पाए, ऊपर से उन्हें अनुपूरक बजट भी दे दिया गया।

बजट की राशि खर्च नहीं अनुपूरक बजट दे दिया

बजट नियमावली में यह नियम है कि बजट खर्च होने का हिसाब-किताब बजट नियंत्रण अधिकारियों के पास रहना चाहिए, लेकिन यहां बजट नियंत्रण अधिकारियों के बजाय संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आंकड़ों का मिलान कर रहा है, जिसके कारण वर्ष 2022-23 के दौरान 2 लाख 36 हजार 395 करोड़ सचित निधि के अंतर्गत कुल व्यय 2 लाख 68 हजार 699 करोड़ का 87.98 प्रतिशत प्राप्ति में 1 लाख 77 हजार 121 करोड़ दर्शाया गया।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार गृह विभाग, वित्त विभाग, भू-राजस्व, जिला प्रशासन, कृषि कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, पंचायत एवं महिला बाल विकास आदि विभागों ने बजट की राशि खर्च किए बिना ही अनुपूरक बजट से भी राशि ले ली। गृह विभाग को बजट में 8,745 करोड़ रुपए मिले थे। जिसमें से उसने 7,665 करोड़ खर्च किए। विभाग के पास 1,145 करोड़ रुपए बचे थे, लेकिन अनुपूरक बजट से 6634 करोड़ ले लिए। इस तरह वित्त विभाग ने 3,846 करोड़ शेष रहते हुए 1,980 करोड़ रुपए लिए। वहीं राजस्व विभाग ने अनुपूरक बजट से 136,24 करोड़, कृषि कल्याण ने 6,710 करोड़, स्वास्थ्य विभाग ने 1,676 करोड़, पीएचई विभाग ने 2000 करोड़, नगरीय विकास ने 2,832 करोड़, स्कूल शिक्षा ने 3.25 करोड़, ग्रामीण विकास ने 2,121 करोड़, जनजातीय कार्य ने 451.22 करोड़, पंचायत विभाग ने 1,472 करोड़ और महिला विकास ने 1,077 करोड़ रुपए की राशि अनुपूरक बजट से ली है।

मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में गृह विभाग, वित्त विभाग, भू-राजस्व, जिला प्रशासन, कृषि कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, पंचायत एवं महिला बाल विकास को मूल बजट में एक लाख 45 हजार 159 करोड़ का प्रावधान किया था। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन विभागों ने बजट का एक लाख 36 हजार 864 करोड़ रुपए ही खर्च किया। इस तरह विभागों के खातों में 26 हजार 843 करोड़ गए शेष बचने के बाद भी इन्होंने सरकार से अनुपूरक बजट में 18 हजार 548 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान करवा लिया। यानी बजट राशि खर्च नहीं होने के बाद भी अनुपूरक में पैसा लेकर इसका बंदरबाट किया। उधर, सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का पालन नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 15.04 प्रतिशत कम हो गया, जबकि 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 9.91 प्रतिशत बढ़ गया। कैग सूत्रों के अनुसार, विभागों ने लेखों में गलत वर्गीकरण करते हुए 2,481 करोड़ के खर्च को राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत व्यय में दर्ज कर लिया। इसी तरह 89.25 करोड़ की राशि को गलत तरीके से

2600 अरब रुपए का हिसाब-किताब नहीं दे रहे अफसर

मप्र में अफसरों की लापरवाही सरकार पर भारी पड़ रही है। हर साल कैग अपनी रिपोर्ट में अफसरों की कारस्तानी को उजागर करता है, लेकिन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। राज्य शासन के अधिकारियों की एक और गंभीर लापरवाही कैग की रिपोर्ट में उजागर की गई है। बताया गया है कि विभागों की ओर से सहायता अनुदान के तौर पर मिली 2600 अरब की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। यह राशि बीते वर्षों में दी गई थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफसरों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विगत वर्षों में यह राशि किस तरह खर्च की गई। यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्हें दिया गया सार्वजनिक धन शामिल है। बड़ी संख्या में सर्टिफिकेट लंबित होना धोखाधड़ी के जोखिम और निधियों के दुरुपयोग से भरा है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट्स में हर साल इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान दिलाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। अनुदान स्वीकृत की ओर से दिए सहायता अनुदान करने वाले प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य और इसे खर्च करने की समय स्पष्ट रूप से होती है।

पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में बजट में खर्च किया जाना बताया।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार मप्र सरकार के बजट का बंदरबाट करने में नौकरशाह भी पीछे नहीं हैं। बिना हिसाब-किताब ही सरकार अनुपूरक बजट में विभागों को पैसा बांट देती है। चाहे विभाग में इस पैसे का दुरुपयोग ही क्यों ना हो रहा हो। इसी कारण भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, क्योंकि अंतिम समय में बजट खर्च करने में आनन-फानन में ठेकेदारों सहित अन्य को पेमेंट कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक दर्जन विभागों के पास बजट से बची हुई राशि 26 हजार 843 करोड़ रखी होने के बाद भी उन्होंने अनुपूरक में 18 हजार 548 करोड़ रुपए ले लिए। 31 मार्च 2023 तक अफसरों के 821 व्यक्तिगत खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में 2,353.57 करोड़ रुपए जमा थे। इन 821 खातों में से 199 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें कुल शेष राशि 214.39 करोड़ रुपए तो तीन साल से अधिक समय से असंचालित थी। यानी इसका उपयोग ही नहीं किया गया और बैंक खातों में अफसरों ने पैसा जमा रखा। उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजा जाता है, इसके बाद ही वह राज्य को राशि आवंटित करता है, लेकिन वर्ष 2023 में बजट राशि खर्च करने के बावजूद एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सर्शत अनुदानों के विरूद्ध 20 हजार 685 करोड़ में से 19 हजार 965 करोड़ बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागों में लंबित थे। इस तरह का फर्जीवाड़े का खुलासा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है।

प्रदेश सरकार का पंचायत विभाग अरबों रुपयों के बजट पर कुंडली मारे बैठा रहा, जिससे न तो वह राशि विकास के कामों पर खर्च की गई है और न ही वित्त वर्ष की समाप्ती पर उस राशि को सरकार को ही लौटाया गया है। यह खुलासा हुआ है हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में। अहम बात यह है कि विभाग ने उन योजनाओं में भी गंभीर लापरवाही दिखाई है, जो न केवल केंद्र की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल हैं। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी शामिल है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार देश में सबसे अच्छा काम होने का दावा कर खुद की पीठ थपथपाती है। रिपोर्ट में इसकी सच्चाई भी बताई गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2023 तक पीएम ग्रामीण आवास योजना का 171.43 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया गया है, वहीं पंच परमेश्वर योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित स्वच्छ भारत मिशन का करीब 896 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है। पंचायत विभाग ने इसे न तो सरकार को लौटाया है और न ही खर्च किया है। पंचायत राज संचालनालय ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल शाखा में एक खाता क्रमांक 3245631964 खोला था। वित्त विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति के बाद यह खाता इस शर्त पर खोला गया कि द्वितीय अनुपूरक में बजट का प्रावधान कर इस योजना को बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके तहत सभी जिला पंचायत एवं जनपद सीईओ को 29 जून 2020 तक उक्त खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। जिससे बैंक खाते में 456.12 करोड़ रुपए जमा हो गए। साथ ही अन्य बैंक खातों में पड़ी राशि 440.78 करोड़ भी इस खाते में अंतरित कर दी गई। इससे बैंक एकाउंट में 896.68 करोड़ रुपए जमा हो गए।

31 मार्च 2023 को बैंक स्टेटमेंट में 896.68 करोड़ रुपए दिखाया गया, जबकि पंचायत संचालनालय के अभिलेखों में राशि 896.20 करोड़ जमा होना बताई गई। यानी 48 लाख रुपए का अंतर इसमें ही पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि विभाग ने एनआईसी रिफंड का 83 लाख, पेसा अधिनियम का 15 लाख, सांसद आदर्श ग्राम योजना का 23 लाख, प्रदर्शन अनुदान का 20 लाख, 12वीं वित्त आयोग का 58 लाख, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का 23 लाख रुपए शामिल है। इस तरह विभिन्न योजनाओं में पैसा होने के बाद भी पंचायत राज संचालनालय द्वारा खर्च नहीं किया गया। यहां तक अगस्त 2023 तक उक्त राशि वित्त विभाग को नहीं लौटाई गई थी। जिसके चलते इसमें भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की आशंका बनी हुई है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

देरी के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ी

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 और 2022-23 के बीच राज्य में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कमी देखी गई। उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19 में 24.58 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 20.39 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19 में 39.37 प्रतिशत से घटकर 38.11 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार की कुल देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं। यह 2018-19 में 1,94,309 करोड़ रुपए से 87.60 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में 3,64,516 करोड़ रुपए हो गई। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में कर चोरी के मामले में 31 मार्च, 2023 तक लंबित मामलों की संख्या 13,813 थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नगरीय प्रशासन और विकास में 22 परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 तक लागत 687.55 करोड़ रुपए बढ़ गई। वहीं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च, 2023 तक 73 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, जिनमें तीन वैधानिक निगम और नौ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल थीं। 73 में से 41 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे।

निगम-मंडलों पर वित्त विभाग की लगाम

मप्र में अधिकांश निगम और मंडल सरकार के लिए सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। अधिकांश निगम-मंडल किसी काम के नहीं रह गए हैं, लेकिन इन पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अब वित्त विभाग ने इन पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। इसके तहत वर्तमान में मप्र केश शिल्पी मंडल, मप्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, मप्र वस्त्र स्वच्छता मंडल और मप्र सिलाई कला मंडल को दिए जाने वाला बजट बंद कर दिया गया है। दरअसल, इन चारों संस्थाओं का खर्चा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उठाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से चारों संस्थाओं ने बजट मांगा तो इसके लिए विभाग ने वित्त विभाग से संपर्क किया। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने इन चारों संस्थाओं को बजट देने से साफ-साफ मना कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इस बार के बजट में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए इनको बजट आवंटित नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बजट में ही सरकार ने इन संस्थाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है तो नगरीय प्रशासन विभाग इनको पैसा कहां से देगा। दरअसल, राजनीतिक पैठ के लिए ऐसे कई निगम, मंडल और आयोग गठित किए गए हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन नेताओं को उपकृत करने के लिए इनमें स्टाफ भी रखे जाते हैं और वाहन, डीजल-पेट्रोल, बिजली-पानी आदि पर हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसलिए वित्त विभाग ने अब ऐसी संस्थाओं पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दर्जनों ऐसी संस्थाओं का गठन कर दिया था, जिनका उद्देश्य सिर्फ जातीय समीकरण को साधना था। लेकिन चुनाव बाद जैसे ही डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐसी संस्थाओं को भंग करने का निर्देश दे दिया। इससे सरकार को हर महीने लाखों रुपए की बचत भी हो रही है। वैसे देखा जाए तो मप्र में अधिकांश निगम-मंडल और आयोग सरकार के लिए घाटे का सौदा बने हुए हैं। मप्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मप्र राज्य वन विकास निगम, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर, मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, संत रविदास मप्र हस्त शिल्प हथकरघा विकास निगम, मप्र होटल कारपोरेशन, मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन जैसी कई संस्थाएं सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हुई हैं। दरअसल, इनसे सरकार को फायदा कम और घाटा ज्यादा हुआ है। प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन इन संस्थाओं में अफसरों की चली है। यही कारण है कि इन संस्थाओं को अफसरों की चारागाह कहा जाता है। इन संस्थाओं में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और अफसरों ने भ्रष्टाचार की फाइलों को दबा दिया है। गौरतलब है कि मप्र में विकास के लिए सरकार ने कभी भी फंड की कमी आड़े नहीं आने दी। सरकार की इस दरियादिली का अफसरों ने भरपूर फायदा उठाया है। पिछले कई वर्षों से अधिकांश संस्थाओं का ना तो ऑडिट हुआ है और ना ही वार्षिक रिपोर्ट कंपनी मंत्रालय को सौंपी गई है। मप्र सरकार ने जुलाई 2005 में 22 से ज्यादा संस्थाएं गठित की थी। इन कंपनियों के पिछले कई वर्षों से ना तो ऑडिट हुए हैं, और ना ही कंपनी मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई है। अगर यह कहा जाए कि ये संस्थाएं फिजूल खर्चे का अड्डा बनी हुई हैं, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

● **अरविंद नारद**

उपक्रमों और निगमों से 1940 करोड़ का घाटा

मप्र के सार्वजनिक उपक्रम और निगम घाटे में चल रहे हैं। 12 सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों से 1940 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घाटे के बाद भी इनके संचालन के कारण राज्य सरकार इन्हें संचालन के लिए समय-समय पर कर्ज भी देती आ रही है। अभी इन निगमों और उपक्रमों पर 25 हजार 236 करोड़ रुपए का राज्य सरकार का कर्ज बाकी है। मप्र के जो एक दर्जन निगम उपक्रम हानि में थे उनकी कुल संचित हानि तो 60 हजार 690 करोड़ रुपए है। अकेले एक साल की हानि ही 1940 करोड़ रुपए है। एजी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 670 करोड़ 84 लाख रुपए की घाटे में चल रही है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का घाटा 903 करोड़ 88 लाख रुपए है। इसी तरह मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का घाटा 257 करोड़ 54 लाख रुपए है। डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का पिछले साल का घाटा 12 करोड़ 59 लाख रुपए रहा। मप्र प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कारपोरेशन का नुकसान 53 लाख रुपए रहा है। मप्र होटल कारपोरेशन लिमिटेड का नुकसान 3 करोड़ 74 लाख रुपए है। डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड ने 76 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान उठाया है। मप्र जल निगम भी 28 लाख रुपए के नुकसान में चल रहा है। मप्र औद्योगिक विकास निगम इस समय 14 करोड़ 85 लाख रुपए के घाटे में है। मप्र वित्त निगम का पिछले साल का नुकसान 49 करोड़ 30 लाख रुपए का रहा है। सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन को 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से 63 हजार 830 करोड़ रुपए की हानि हुई है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों की पूंजी नष्ट हो गई थी। उन पर राज्य शासन का 25 हजार 236 करोड़ रुपए बाकी था। इन निगमों में मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर 8022 करोड़ 65 लाख रुपए, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर 9 हजार 237 करोड़ 63 लाख रुपए, मप्र पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी पर 7976 करोड़ 62 लाख रुपए का राज्य सरकार का कर्ज बाकी था। इसके अलावा डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन व मप्र होटल कारपोरेशन को मिलकर इन पर 60 हजार 776 करोड़ रुपए की संचित हानि थी।

हनीट्रैप गैंग की फांस

जिस तरह बलात्कार पीड़िता के लिए सबसे बड़ी परेशानी और अपमान का कारण बनता है। ठीक उसी तरह, अगर किसी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगता है तो आरोपित के लिए भी कष्ट, अपमान का कारण बनता है। इससे उसे बहुत नुकसान होता है। किसी भी व्यक्ति को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने से बचाए जाने की जरूरत है...सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा यह टिप्पणी उप्र के सहारनपुर के मिर्जापुर में एक युवक के खिलाफ दर्ज हुए बलात्कार के झूठे मामले की एफआईआर निरस्त करते हुए की गई थी।

बलात्कार का यह पहला मामला नहीं है, जो झूठा पाया गया। हर रोज देश के किसी न किसी शहर में बलात्कार जैसे सनसनीखेज अपराध में झूठा फंसाकर लाखों रुपए वसूले जाने की कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि मप्र से लेकर देश के अलग-अलग शहरों में पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी महिलाएं और इनके ब्लैकमेलर पुरुष साथी पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा रेप की एफआईआर को मोटी कमाई का जरिया बना लिया है। बाकायदा ऐसे लोगों की रैकी इस गैंग द्वारा की जाती है। फोन या इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती, फिर मिलने के बहाने बुलाना और इसके बाद शुरू होती है ब्लैकमेलिंग की कहानी। ऐसे मामलों में एफआईआर करना पुलिस की मजबूरी है। अगर पुलिस जांच में आवेदन लेती है तो कई बार पीड़िताएं वरिष्ठ अधिकारी, कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक झेलना पड़ती है।

बलात्कार की जितनी शिकायतें आती हैं, उनमें शादी का झांसा देकर सालों से गलत काम करने, लिव-इन में सालों तक रहने के बाद दुष्कर्म की एफआईआर सबसे ज्यादा हो रही हैं। प्रदेश के चारों बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में यह सबसे ज्यादा हो रही हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें ही सबसे ज्यादा राजीनामा भी हो रहा है। बलात्कार का हर मामला ऐसा है, यह नहीं है लेकिन जिस तरह से बड़े शहरों में इस तरह की गैंग सक्रिय है, उससे साफ है- बलात्कार जैसे संवेदनशील अपराध से वसूली करने वाला यह नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। कई बार ऐसे झूठे मामलों की वजह से सिस्टम में बैठे जिम्मेदार हों या आम लोग हकीकत में हुई घटना को भी संदेह की नजर से देखने लगते हैं। मुरार के ट्रेवल एजेंसी संचालक नंदकिशोर लोधी के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर कराने दो दिन पहले मनीषा प्रजापति नाम की महिला मुरार थाने पहुंची थी। उसके साथी चिंटू जाट ने 15 लाख रुपए की मांग की। पहले उससे दोस्ती की थी। नंदकिशोर को थाने बुलवाया, तब उसने पूरी हकीकत बताई। पुलिस ने मनीषा प्रजापति, उसके साथी चिंटू जाट पर एफआईआर दर्ज की। वह अब तक दुष्कर्म, छेड़छाड़ की चार एफआईआर ग्वालियर में करा चुकी है।

पनिहार के रहने वाले बुजुर्ग ओमप्रकाश दुबौलिया को मिस्ड कॉल के जरिए फंसाया। उसे 27 अप्रैल को ग्वालियर में मिलने बुलाया। कमरे पर ले जाकर ममता नाम की महिला ने अपने साथी बुला लिए। फिर 5 लाख की मांग की। न देने पर झांसी रोड थाने में एफआईआर लिखाने पहुंच गई। पुलिस ने सरगना राधा परिहार, ममता, सुरेश, लोकेश पर एफआईआर की। राधा ने पहले भी एफआईआर कराई है। इंदौर की लेडी डॉन सपना साहू ने गीता कॉलोनी में रहने वाले लोहा कारोबारी सजल मित्तल को फंसाया। दुष्कर्म की एफआईआर से पहले दो करोड़ रुपए मांगे, जब नहीं दिए तो एफआईआर करा दी। फिर 50 लाख रुपए में राजीनामा करने की बात हुई। पुलिस ने सपना साहू व उसके साथी ऋषि, नीरज वर्मा, शुभम, मदन चाचे, राधे पहलवान पर एफआईआर की।

जयपुर पुलिस ने ममता वर्मा नाम की ऐसी सीरियल फरियादिया पकड़ी, जिसने दुष्कर्म और छेड़छाड़ की 16 एफआईआर दर्ज कराई हैं। 8 मई को सदर थाने में वकील पर एफआईआर कराई थी। 19 मई को जयपुर पुलिस ने उसे पकड़ा था। ग्वालियर के दाल बाजार कारोबारी रोहन अग्रवाल से मिस्ड काल के जरिए दोस्ती कर कमरे पर मिलने बुलाने के बाद एक लाख रुपए, सोने की चेन, अंगूठी यह कहकर वसूली गई, उस पर दुष्कर्म की एफआईआर करा दी जाएगी। आरोपित महिलाओं का नाम शिल्पी और प्रियंका है। मप्र हाइकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दुष्कर्म के एक मामले की एफआईआर रद्द करते हुए टिप्पणी की थी- आठ साल तक सहमति से संबंध बनाने को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। शादी का झांसा देकर इतने समय तक दुष्कर्म नहीं हो सकता।

● कुमार विनोद

देश में लोगों को ठगने के लिए तरह-तरह के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे खतरनाक हनीट्रैप गैंग माना जा रहा है। यह गैंग पहले रैकी, फिर फोन करता है। उसके बाद जो फंसता है उसे डर दिखाकर वसूली होती है।

गैंग के बड़े टारगेट

मप्र की राजधानी भोपाल सहित देश के अन्य क्षेत्रों में हनीट्रैप गैंग के टारगेट पर जो लोग हैं, उनमें सरकारी अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी, बड़े कारोबारी, नेता, बड़ी कंपनियों के अधिकारी, कर्मचारी, अकेले और पैसे वाले बुजुर्ग शामिल हैं। आए दिन हनीट्रैप गैंग इन लोगों को फंसाने के लिए फोन करता है। भोपाल ही नहीं बल्कि मप्र में दुष्कर्म के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। यह चिंता का विषय है। लेकिन कानूनविद कहते हैं- दुष्कर्म जैसे सनसनीखेज अपराध में कितनों में राजीनामा हुआ, पीड़िताएं मुकर गईं, कितने मामले झूठे साबित हुए, कितने मामलों में कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द की गई। बाकायदा इसका विश्लेषण जरूरी है। जिससे पुलिस को हकीकत पता लग सकेगी। बाकायदा इसके आंकड़ों के विश्लेषण की जरूरत है।

मप्र में साल दर साल बढ़े बलात्कार के मामले

वर्ष	प्रदेश
2019	2485
2020	2339
2021	2947
2022	3046
2023	3660

मप्र का शासन, प्रशासन और यहां की विधानसभा अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल मानी जाती है, लेकिन पिछले दो दशक से मप्र के माननीयों का मन लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा में नहीं लग रहा है। शायद यही वजह है कि पिछले दो दशक से मप्र विधानसभा का कोई भी सत्र पूरा नहीं चला। हालांकि सत्र भले ही अधूरे रह गए, लेकिन उनमें काम पूरा हुआ।

सत्र सिमटे... काम पूरे हुए

वर्ष 2004 से लेकर 2024 के मानसून सत्र तक पिछले 20 साल में मप्र विधानसभा की 105 बैठकें आयोजित की गईं। लेकिन विडंबना यह है कि इनमें से मात्र 65 दिन ही विधानसभा चल सकी। हालांकि इस दौरान विधानसभा के सारे कामकाज निपटते रहे। ऐसा ही हाल ही में संपन्न इसी मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में भी देखने को मिला। ये सत्र 1 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलने वाला था, लेकिन अपने तय वक्त से 14 दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। इस मानसून सत्र के दौरान मोहन सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट को पेश किया गया। तो वहीं नर्सिंग घोटाले की गूंज भी इस विधानसभा सत्र में सुनाई दी है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब तय वक्त से पहले सत्र को स्थगित कर दिया गया हो, ऐसा पिछले 20 सालों से चला आ रहा है। इस सत्र में भी कई विधायकों के प्रश्न अधूरे रह गए हैं, जो प्रश्न विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र को लेकर लगाए गए थे। इस विधानसभा सत्र में 4 हजार से अधिक प्रश्न लगाए गए थे, जिनमें से आधे भी प्रश्नों पर चर्चा नहीं की गई है।

5 दिन चले मानसून सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों, मंत्रियों, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव को अब खुद ही इनकम टैक्स भरना होगा, जिसे पहले सरकार भरा करती थी। विधानसभा में गौवंश की सुरक्षा को लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक गौवंश की तस्करी में शामिल वाहन न्यायालय की मदद से छूट जाया करते थे। लेकिन अब उन्हें राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। मप्र में विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद कुलगुरु के नाम से पुकारा जाएगा। खुले बोरवेल या नलकूप के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए किसी सरकारी अधिकारी को कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं। पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी की व्यवस्था तय की गई है।

पिछले 20 साल में एक बार भी बजट सत्र तय अवधि तक नहीं चल सका है। 19 जुलाई तक प्रस्तावित इस सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश हुआ था। 4 जुलाई को बजट प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई थी, जो देर शाम खत्म हुई। 5 जुलाई को भी बजट पर चर्चा हुई, जिसके बाद विपक्ष की आपत्तियों के बाद अनुदान मांगों के बाद बजट पारित कर दिया गया। फिर विनियोग प्रस्तावों पर चर्चा शाम तक चली। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। 1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित इस सत्र में कुल 14 बैठकें होनी थीं। 2004 के बाद से 20 सालों में ये सबसे छोटा बजट था। इससे पहले 2022 और 2023 में 13-13 बैठकों के बजट सत्र रखे गए थे। ये भी तय अवधि तक नहीं चल सके थे। साल 2020 में जब कमलनाथ सरकार संकट में थी, तब मार्च में रखा गया 17 बैठकों का बजट सिर्फ 2 बैठकों में ही खत्म हो गया था। 2011 में कुल प्रस्तावित 40 में से 24 बैठकें हुई थीं। 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद जून-जुलाई में हुए बजट सत्र में 37 में से 18 बैठकें हुई थीं। वहीं 2015 में कुल 24 में से सिर्फ 7 बैठकें हुई। लगातार सत्रों की अवधि भी घटती रही है। 2004 में 37 बैठकों के सत्र की तुलना में 2024 में जुलाई सत्र महज 14 बैठकों का था। बजट सत्र में विभिन्न प्रस्ताव आने के बाद विधायक अपने सुझाव देते हैं। बीच में ही सत्र खत्म होने

माननीय भी हालाकान

देश की संसद और राज्यों के विधानमंडलों में अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, समस्याओं का हल निकालने और जनहित में नीतियां बनाने के क्रम में जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस भी होती हैं, तो यह स्वाभाविक और जरूरी है। लेकिन मप्र विधानसभा में पिछले कई सत्र से यह देखने को मिल रहा है कि गैर जरूरी मुद्दे को लकीर बनाकर सत्तापक्ष और विपक्ष उसकी कोर पीटने में लगे रहते हैं और दो-चार दिन में ही सत्र का समापन कर दिया जाता है। जनता से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो पाती है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद माननीय इस बाद पर चिंता जता रहे हैं कि सदन में वे जनता की आवाज नहीं उठा सके। दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान हर विधायक चाहता है कि उसका सवाल चर्चा में आए। माननीय अपने क्षेत्र में जाएं तो लोगों को बता सकें कि उन्होंने आपकी आवाज सदन में उठाई है। विपक्ष के सदस्यों को ज्यादा उम्मीद रहती है कि सरकार को घेरने से विकास के कार्य संभव होंगे या फिर भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर कार्यवाही के निर्देश होंगे।

से विधायक अपनी बात नहीं रख पाते। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सत्रों की अवधि घटने का एक कारण ये भी है कि सरकार का बिजनेस अब इतना ज्यादा नहीं रहता और विधायक भी क्षेत्र में ज्यादा रहना चाहते हैं। कई बार इतने विधायक भी नहीं आते कि कोरम पूरा हो सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सरकार बार-बार कहती है कि सत्र लंबा खींचने लायक बिजनेस नहीं होता। ये सही नहीं है। लोकायुक्त की कई रिपोर्ट, विभागों और कमेटियों की रिपोर्ट लंबित है। इन्हें सरकार सदन में क्यों नहीं रखती। प्रश्नकाल भी बिजनेस है, जिसमें जनहित के मुद्दे आते हैं।

लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद हो या विधानसभा, जनता के मुद्दों पर चर्चा, सवाल-जवाब और फिर निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन। बीते कई वर्षों में यही चिंताजनक ट्रेंड मप्र विधानसभा में दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़ों को देखें तो मप्र में साल दर साल विधानसभा सत्रों की संख्या भी कम हो रही है। 12वीं विधानसभा में 275 दिन का कुल सत्र 159 दिन चला था। 13वीं विधानसभा में 262 दिन के सत्र में 167 दिन सदन चला था। 14वीं विधानसभा में 182 दिन के सत्र में 135 दिन सदन चला था। वहीं 15वीं विधानसभा में 132 दिन के सत्र में 83 दिन ही सदन चला था। मप्र की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। 4 दिन का यह सत्र पूरे दिन चला। लेकिन बजट सत्र अधूरा ही रह गया। जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार मप्र विधानसभा का सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक का था, लेकिन इसे 14 फरवरी की कार्यवाही के साथ स्थगित कर दिया गया। यह पहला मौका नहीं, जब मप्र विधानसभा का सत्र निर्धारित अवधि से पहले स्थगित किया गया। मप्र में 5 वर्षों से विधानसभा सत्र की अवधि सिमटती जा रही है।

15वीं विधानसभा में कोई भी सत्र पूरे दिन नहीं चला। वहीं 16वीं विधानसभा का पहला सत्र महज शपथ ग्रहण की औपचारिकता के लिए था। जबकि 7 फरवरी से शुरू हुआ बजट सत्र पूरे समय तक नहीं चल पाया। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन। बीते कई वर्षों में यही चिंताजनक ट्रेड मप्र विधानसभा में दिखाई दे रहा है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मप्र विधानसभा में हाल में हुए प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्र की अवधि छोटे होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लंबी अवधि के सत्र आयोजित किए जाने की बात कही थी, लेकिन मप्र विधानसभा में 13 दिन का बजट सत्र निर्धारित अवधि से 5 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।

विधानसभा के सत्र भले की आधे-अधूरे हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस दौरान अपने सारे काम निपटा लेती है। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र कुल 28 घंटे 9 मिनट चला और छह बैठकें हुईं। जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। सदन ने अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर लेखानुदान पारित किया, वहीं वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र में कुल 2,303 प्रश्न प्राप्त हुए। ध्यानाकर्षण की कुल 541 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 40 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। दरअसल, पक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रूचि अब अधिक अवधि तक सत्र चलाने में नहीं रह गई है।

● **लोकेश शर्मा**

पहले बजट में दिखा मोहन का मैनेजमेंट

इस मानसून सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पहला बजट कैसा होगा? जैसा माना जा रहा था, वैसा ही। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई नई योजना। न ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया। सरकार ने यह मैसेज भी दिया है कि लोकलुभावन योजनाओं की बजाय इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। वजह भी साफ है- निकट भविष्य में कोई चुनावी मजबूरी नहीं है। हां, धर्म पर खास ध्यान देते हुए सरकार ने अपना संवेदनशील चेहरा दिखाने का प्रयास जरूर किया है। एक घोषणा पर गौर कीजिए- सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान मृत्यु होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रहा। बजट का सबसे ज्यादा 15 फीसदी हिस्सा इसी पर खर्च होगा। सरकार मानती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक्सप्रेस-वे पर ही प्रदेश के डेवलपमेंट की गाड़ी स्पीड से चल सकती है। हालांकि इस सेक्टर में किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान बजट में नहीं हुआ, लेकिन चुनाव पहले ही केंद्र व राज्य की साझेदारी से प्रदेश में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार पर काम शुरू हो गया था। कुल 6 एक्सप्रेस-वे अगले 5 सालों में तैयार होना है। इनके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे। इन्हीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का रास्ता निकलेगा। पुलिस महकमे के अलावा टीचर्स की नई नियुक्ति का जिक्र कर बेरोजगार युवाओं की कुछ उम्मीदें जगाई हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस में राहत देने की घोषणा भी की है। हालांकि, सरकार की मंशा साफ है कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही ध्यान न दें। अपना काम-धंधा शुरू करने की तैयारी करें, सरकार कर्ज दिलाने के लिए तैयार है। डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट पिछली शिवराज सरकार से भले ही 16 फीसदी ज्यादा है, लेकिन मोहन सरकार ने शिवराज की कई योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। साथ ही पिछले बजट में जो घोषणाएं थी उनका इस बजट में कोई जिक्र भी नहीं है। मसलन शिवराज सरकार ने अपने आखिरी बजट में एक लाख सरकारी नौकरी, 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी देने जैसी कई योजनाओं को शामिल किया था। इससे उलट इस सरकार का फोकस मोदी की चार जातियों महिला, किसान, युवा व गरीब पर रहा है। यही वजह है कि कुल बजट का 33 फीसदी पैसा महिलाओं पर खर्च किया जाएगा।

जानलेवा वायु प्रदूषण

देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब एक ताजा अध्ययन में जो पता चला है, उससे हम सभी का चिंतित होना स्वभाविक है। दरअसल इस अध्ययन में दावा किया गया है कि देश के 10 शहरों में हर साल 33 हजार लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते हो रही है। यह अध्ययन लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में छपा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साफ हवा के मानक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साफ हवा के मानकों से पहले ही ज्यादा हैं, लेकिन कई शहरों में तय मानकों से भी कई गुना ज्यादा प्रदूषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसके चलते लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, देश के 10 शहरों- अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में साल 2008 से 2019 के बीच अध्ययन किया, इन शहरों में वायु प्रदूषण से 33 हजार मौतें हुई हैं। अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे वायु प्रदूषण के स्तर से भी देश में दैनिक मृत्यु दर में वृद्धि होती है। देश के 10 शहरों- अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में, प्रतिवर्ष लगभग 33,000 मौतें वायु प्रदूषण के स्तर के कारण होती हैं, जो डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों से अधिक है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण से जनित बीमारियों से हर साल 12 हजार लोगों की मौतें हुई हैं, जो देश में हुई कुल मौतों का 11.5 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को कठोर करने की जरूरत है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास दोगुने करने की जरूरत है।

दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा मौतें वाराणसी में हुई हैं, जहां हर साल 830 लोगों की जान गई है, जो कि कुल मौतों की संख्या का 10.2 प्रतिशत है। वहीं बेंगलुरु में 2,100, चेन्नई में 2900, कोलकाता में 4700 और मुंबई में करीब 5100 लोगों की मौत हर साल वायु प्रदूषण के चलते हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया है। हालांकि अभी भी पहाड़ी शहर में वायु प्रदूषण का स्तर एक जोखिम बना हुआ है। शिमला में हर साल 59 मौतें हुई हैं, जो कुल मौतों का 3.7 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज कंट्रोल, स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड और बोस्टन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने तैयार की है। भारत के प्रदूषित शहरों के लिए हवा साफ करने के लिए केवल एक साल बाकी है। जनवरी 2019 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 131 शहरों और शहरी समूहों में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) लॉन्च किया था, जिनमें लगातार प्रदूषण का उच्च स्तर पाया गया था। इसका लक्ष्य 2019 के स्तर से 2025-26 तक इन शहरों में वायुमंडल में पाए जाने वाले महीन कणों (पीएम) की मात्रा को 40 प्रतिशत तक कम करना था।

कार्यक्रम को लागू करने में मदद के लिए, एनसीएपी ने प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाली धनराशि का वादा किया था, जो वायु प्रदूषण को रोकने की एक नई तरह की रणनीति है। इस कार्यक्रम के लिए 19,711 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक सभी 131 शहरों में पीएम 10 (10 माइक्रॉन या उससे कम व्यास वाले महीन कण) के स्तर में सुधार हुआ है। लेकिन क्या ये शहर वायु प्रदूषण को वास्तव में कम करने में सफल हुए हैं, जो फेफड़ों के कैंसर से लेकर हृदय रोगों, जन्म के समय कम वजन और अकाल मृत्यु तक कई बीमारियों का कारण बन सकता है? एनसीएपी के तहत आवंटित 19,711 करोड़ रुपए में से, 16,539 करोड़ रुपए 49 शहरों और शहरी समूहों के लिए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। शेष 3,172 करोड़ रुपए कम आबादी वाले 82 शहरों के लिए आवंटित किए गए हैं। हालांकि, इस आंकड़े के विश्लेषण से धन का कम इस्तेमाल सामने आता है, जो क्रियान्वयन में ढिलाई का संकेत देता है। दिसंबर 2023 तक, 49 बड़े शहरों को 8,357.51 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उन्होंने इसका केवल 70 प्रतिशत यानी 5,835.03 करोड़ रुपए ही खर्च किया। 82 छोटे शहरों को 1,292.5 करोड़ रुपए मिले और उन्होंने इसका केवल 37.5 प्रतिशत यानी 480.92 करोड़ रुपए ही खर्च किया। इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार्रवाई का दायरा और गति अभी भी लक्ष्य से पीछे है।

हवा साफ करने में कितनी तरक्की हुई है, इसे जांचने का तरीका भी सवालों में है। उदाहरण के लिए, एनसीएपी को मूल रूप से पीएम10 और पीएम2.5 दोनों तरह के महीन कणों को कम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन असल में हवा की गुणवत्ता में सुधार को आंकने के लिए सिर्फ पीएम10 (जो हवा में उड़ने वाले बड़े धूल के कण होते हैं) को ही देखा जाता है। इससे ध्यान और पैसा धूल नियंत्रण पर ही लगने लगा है, जबकि पीएम2.5 कणों की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। ये कण ज्यादा हानिकारक होते हैं और मुख्य रूप से जलने वाली चीजों से निकलते हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

मजबूत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाएं

कई कानूनों के तहत प्रदूषण नियंत्रण का काम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) करता है। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली में कमी रहती है क्योंकि इनके पास पर्याप्त कर्मचारी, पैसा और जरूरी उपकरण नहीं होते। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 5 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सभी एसपीसीबी में स्वीकृत पदों में से आधे से ज्यादा (6,075) खाली पड़े हैं। आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मप्र, उत्तराखंड और मणिपुर में तो ये खाली पद 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं। कर्मचारियों की इतनी कमी से प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वहां 1,11,928 कारखानों की निगरानी के लिए स्वीकृत 839 पदों में से सिर्फ 505 पद भरे हुए हैं। इन 505 कर्मचारियों में से भी सिर्फ 315 ही तकनीकी विशेषज्ञ हैं। यानी हर एक विशेषज्ञ को 355 कारखानों की निगरानी करनी पड़ती है।

क्या अल्पसंख्यक हो रहे हैं बहुसंख्यक?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। जस्टिस रोहित रंजन ने ये टिप्पणी सामूहिक धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। मामला एक गांव में हिंदुओं के सामूहिक रूप से धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपनाने से जुड़ा था। सामूहिक धर्मांतरण कराने का आरोप कैलाश नाम के व्यक्ति पर लगा है। हाईकोर्ट ने कैलाश की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे धार्मिक जमावड़ों को तुरंत रोका जाना चाहिए, जहां धर्मांतरण हो रहा है और लोगों का धर्म बदला जा रहा है। जस्टिस रोहित रंजन ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। इस दौरान हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि उप्र के कई हिस्सों में एससी-एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में बदला जा रहा है।

रामकली प्रजापति नाम की महिला ने हमीरपुर जिले के मौदाहा गांव के रहने वाले कैलाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रजापति ने आरोप लगाया था कि कैलाश मानसिक रूप से बीमार उसके भाई को दिल्ली ले गया था। कैलाश ने वादा किया कि वो उसके भाई का इलाज करवाएगा और ठीक होने पर वापस गांव भेज देगा, लेकिन इसकी जगह उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। एफआईआर के मुताबिक, जब कैलाश वापस लौटा तो वो गांव के सभी लोगों को दिल्ली में एक कार्यक्रम में ले गया, जहां उसने सभी को कथित तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। कैलाश ने प्रजापति के भाई को ईसाई धर्म अपनाने के बदले पैसे की पेशकश की थी। वहीं, कोर्ट में कैलाश के वकील ने दावा किया कि रामकली के भाई का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। देश के कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून हैं। उप्र की योगी सरकार ने 2021 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया था। इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती से, लालच देकर या डरा-धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 से 5 साल तक की जेल और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के मामले में 2 से 10 साल की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

वहीं, सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और कम से कम 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार जबरन धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है तो सजा को दोगुना किया जा सकता है। मसलन, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल की जेल की बजाय 2 से 10 साल की सजा हो सकती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8 प्रतिशत हिंदू और 14.2 प्रतिशत मुस्लिम हैं। इनके बाद ईसाई 2.78 करोड़ (2.3 प्रतिशत) और सिख 2.08 करोड़ (1.7 प्रतिशत) हैं। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 1 प्रतिशत से भी कम है। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ी थी। जबकि, हिंदू 17 प्रतिशत से कम बढ़े थे। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5 प्रतिशत, सिख 8.4 प्रतिशत, बौद्ध 6.1 प्रतिशत और जैन 5.4 प्रतिशत बढ़े थे।

वहीं, अगर 1951 से 2011 तक की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। 1951 में 3.54 करोड़ थी, जो 2011 तक 386 प्रतिशत बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। जबकि, 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.35 करोड़ थी। 2011 तक हिंदुओं की आबादी 218 प्रतिशत बढ़कर 96.62 करोड़ पहुंच गई। इसी तरह सिखों की आबादी 235प्रतिशत और ईसाइयों की 232 प्रतिशत बढ़ गई। 1951 में भारत में हिंदू 84 प्रतिशत, मुस्लिम 9 प्रतिशत, ईसाई 2.2 प्रतिशत और सिख 1.7 प्रतिशत थे। 2011 की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.8 प्रतिशत, मुस्लिमों की 14.2 प्रतिशत, ईसाइयों की 2.3 प्रतिशत और सिखों की 1.7प्रतिशत थी। इसी साल मई में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में दावा किया गया था कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8प्रतिशत तक घट गई। स्टडी में कहा गया था कि भारत में बहुसंख्यक आबादी घट रही है, जबकि दूसरे मुल्कों में बहुसंख्यक आबादी बढ़ रही है। भारत के अलावा म्यांमार और नेपाल में भी बहुसंख्यक आबादी घटी है। म्यांमार में बहुसंख्यक आबादी (बौद्ध) में 9.8 प्रतिशत और नेपाल में बहुसंख्यक (हिंदू) आबादी में 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी ओर, बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की आबादी में हिस्सेदारी 18.5 प्रतिशत और पाकिस्तान में 3.75 प्रतिशत तक बढ़ गई है। स्टडी में कहा गया था कि 1971 में बांग्लादेश के अलग मुल्क बनने के बाद से मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है।

● **प्रवीण सक्सेना**

जबरन धर्मांतरण पर क्या है कानून

फिलहाल, देश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत, देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि, किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे लेकर कानून है। इनमें ओडिशा, उप्र, मप्र, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देशों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून हैं। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान में इसे लेकर कानून है। नेपाल में जबरन धर्मांतरण पर 6 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं, म्यांमार में 2 साल और श्रीलंका में 7 साल तक की सजा हो सकती है। भूटान में भी कानून है, लेकिन यहां सजा का जिक्र नहीं है, बस इतना है कि कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं और यहां सबसे कठोर कानून है। यहां जबरन धर्मांतरण पर 5 साल की कैद से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। यहां 18 साल से कम उम्र के लोग भी अपना धर्म नहीं बदल सकते।

2 साल बाद भी नहीं मिली स्कूल ड्रेस

एक तरफ सरकार सीएम राइज जैसे स्कूल खोल रही है, ताकि छात्रों को बेहतर संसाधन के साथ शिक्षा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को पिछले 2 साल से ड्रेस नहीं मिली है, इस कारण वे बिना ड्रेस स्कूल जाने को मजबूर हैं।

मप्र के सरकारी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बीते 18 जून से खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही विद्यार्थियों को ड्रेस और किताबों का वितरण होना था, लेकिन राजधानी समेत प्रदेशभर के 66 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म या उसकी राशि नहीं मिल पाई है। इस कारण विद्यार्थी स्कूल ड्रेस की जगह रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं।

दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क दो जोड़ी ड्रेस दी जाती है। पिछले सालों में ड्रेस की राशि विद्यार्थियों के खातों में डाली जाती थी, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावक राशि लेकर अपनी मर्जी से कहीं से भी ड्रेस सिलवा सकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद इसका काम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वसहायता समूह को दिया गया। जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन जब स्वसहायता समूह के माध्यम से सिलकर स्कूलों में यूनिफार्म पहुंची तो उनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। साथ ही बच्चों की नाप के अनुसार उन्हें ड्रेस नहीं मिल सकी। इसके बाद कोरोना के चलते स्कूल बंद रहे।

कोरोना की पाबंदी हटने के बाद आजीविका मिशन के माध्यम से स्कूलों में दो साल पहले ड्रेस नहीं पहुंच सकी। दो साल पहले की यूनिफार्म को कई स्कूलों में पिछले साल वितरण शुरू किया, लेकिन वह भी सभी स्कूलों में नहीं पहुंच सकी। इसके राज्य शिक्षा केंद्र ने कुछ जिलों में ड्रेस की राशि विद्यार्थियों के खातों में डालने व कुछ को ड्रेस वितरित करने के दिशा-निर्देश जारी किए। लेकिन सत्र 2023-24 की ड्रेस वितरण का कार्यक्रम सत्र समाप्ति के बाद भी नहीं हो पाया है। जबकि अब स्कूलों का नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 पहली अप्रैल से शुरू हो चुका है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकारी स्कूलों में 390 करोड़ खर्च करने के बाद भी पिछले साल की सभी 66 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म या उसकी राशि नहीं मिल पाई है। स्कूलों में विद्यार्थियों को बीते पांच सालों से यूनिफार्म के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्कूलों में पिछले दो साल से ड्रेस वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। वह भी पूरा नहीं हुआ है। इससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी रंग-बिरंगे कपड़ों में ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। अब अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों को खातों में गड़बड़ी बताते हुए उसमें सुधार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा यूनिफार्म दी जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 66 लाख के करीब है। हर बच्चे को दो जोड़ी यूनिफार्म या राशि दी जाती है। जिस पर प्रति छात्र 600 रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों की यूनिफार्म पर हर साल लगभग 390 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बच्चों को यूनिफार्म देने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) की है। सरकार के निर्णय के बाद आरएसके ने यह काम आजीविका मिशन के माध्यम से स्वसहायता समूह को दिया था। फिलहाल अब आजीविका मिशन के समय पर ड्रेस नहीं देने व घटिया क्वालिटी होने के कारण राशि विद्यार्थियों के खाते में डाली जा रही है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

नए दिशा-निर्देश जारी

राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक आर उमा माहेश्वरी ने ड्रेस वितरण को लेकर नवीन दिशा-निर्देश दिए है। जारी निर्देशों में कहा है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सत्र 2023-24 के लिए अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी एवं सिंगरौली कुल 22 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में गणवेश प्रदाय की कार्यवाही की जा रही है। इन जिलों के स्कूलों के विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। इसके अलावा 30 जिलों में राशि प्रदाय करने के समय कुछ छात्रों या पालकों के खाते में त्रुटि होने के कारण उनके खातों में राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी। अतः शालावार समीक्षा करते हुए गणवेश की राशि प्राप्त नहीं होने वाले छात्रों या पालकों के खातों को अपडेट किया जाए। यह कार्यवाही 30 जून तक पूर्ण करनी थी। गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने साल 2020 में यूनिफार्म सिलाई का काम ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के माध्यम से स्वंयसेवी संस्थानों को दिया गया था। नतीजा यह रहा कि सत्र बीतने के बाद मार्च 2021 में स्कूलों में यूनिफार्म पहुंच सकी थी। कोरोना के चलते स्कूल बंद होने के कारण शिक्षकों को घर-घर जाकर यूनिफार्म पहुंचानी पड़ी। बच्चों का सही नाप न होने के कारण साइज भी छोटा पड़ गया था। वहीं सिलाई भी ठीक नहीं थी। इसके बाद 2021 में कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, 2022 की यूनिफार्म 2023 में पहुंचाना शुरू की। लेकिन वर्ष 2024 के जून माह तक भी कई बच्चों को ड्रेस नहीं मिली है। वहीं इस साल सत्र 2024-25 में ड्रेस को लेकर फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं है।

खंडवा बना दहशतगर्दी का गढ़

सिमी का गढ़ रहे खंडवा का आतंक से पुराना नाता है। 16 साल पहले एटीएस जवान सीताराम यादव सहित तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर आतंक का बीजारोपण अबु फैजल ने किया था। अब एक बार फिर खंडवा की जमीन से इस प्रकार के मॉड्यूल को अपनाकर आतंक का परचम लहराने की कोशिश हो रही है। 32 वर्षीय अब्दुल रकीब के बाद 36 वर्षीय फैजल शेख की फितरत एटीएस की नजरों से बच नहीं सकी। अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही एसटीएफ और मप्र एटीएस ने उन्हें धरदबोचा। एक साल पहले खंडवा से अब्दुल रकबी पुत्र अब्दुल वकील कुरैशी भी इंटरनेट के माध्यम से बम बनाने की ट्रेनिंग देने और पश्चिम बंगाल की आंतकी घटना को अंजाम देने वालों के संपर्क में होने से पकड़ा गया था। उसे पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। फैजल भी उसका साथी होने से एनआईए, एसएफटी और एटीएस के रडार पर था। जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत हाथ लगते ही उसे खंडवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

इंटरनेट के जरिए आतंक को जिंदा रखने का प्रयास खंडवा में 28 नवंबर 2009 को तिहरे हत्याकांड को प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के गुर्गों ने अंजाम दिया था। इनका सरगना मुंबई का डॉ. अबु फैजल था। मूलत: उप्र का रहने वाला अबु फैजल खंडवा में अपना आतंकी साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, इसके लिए निमाड़ और मालवा में इस्लामिक आंतकवाद का जहर फैलाने के लिए युवा को जोड़ने की कोशिश की। इसमें कुछ हद तक वह सफल भी हुआ, लेकिन जांच एजेंसियों और पुलिस की कोशिशों से सिमी सहित अन्य आंतकी संगठन खंडवा में अपनी जड़ें नहीं जमा सके। सिमी गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद जमीनी गतिविधियों पर लगाम लग गई, लेकिन इंटरनेट के जरिए युवाओं में इस्लामिक कट्टरवाद और नफरत का जहर भरकर आतंक को कायम रखने के प्रयास जारी हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहां रकीब और फैजल जैसे युवा भटककर आतंक की राह अख्तियार कर रहे हैं। आतंकी अबु फैजल और यासीन भटकल से प्रभावित होकर खंडवा का युवा फैजल हनीफ शेख विध्वंस और दहशत के जरिए स्वयं को अन्य युवाओं का रोल मॉडल व हीरो बनने की कोशिश में लगा था। वह अपने मंसूबों में सफल हो पाता इससे पहले एटीएस भोपाल की टीम ने उसे धरदबोचा।

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया संगठन को 2001 में आतंकी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। खंडवा में तिहरे हत्याकांड के बाद सातों सिमी आतंकी जिला जेल से 1 अक्टूबर 2013 को भाग निकले थे। इनमें मुंबई निवासी अबु फैजल, खंडवा के गणेश तलाई का अमजद खान, असलम, जाकिर हुसैन, मेहबूब उर्फ गुड्डू और करेली निवासी एजाजुद्दीन पर हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में एक सहयोगी आबिद अंसारी जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद थे। खंडवा जेल से भागने के 3 साल बाद इन्हें एटीएस ने गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भोपाल में रखा था। 31 अक्टूबर 2016 को शेख मुजीब, असलम, हबीब उर्फ शेट्टी, साजिद उर्फ शेरू, अबु फैजल, महबूब, एजाजुद्दीन और इकरार शेख भोपाल जेल से भागने में कामयाब हो गए थे। इस दौरान एनकाउंटर में सिमी के 7 आतंकी मारे गए थे। इनमें अबु फैजल बच गया था। भोपाल सेंट्रल जेल में पहले से सजा काट रहे आतंकी अबु फैजल को दिसंबर 2023 में एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा वर्ष 2013 में खंडवा जेल तोड़ने के मामले में सुनाई गई थी। जिहादी मानसिकता ने एक बार फिर खंडवा को शर्मसार कर दिया। मशहूर होने के चक्कर में आतंकी संगठनों के संपर्क में आकर फैजान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन एटीएस की कार्रवाई ने आतंकी के मंसूबों को नाकाम करते हुए उसे दबोच लिया। फैजान के भाई मोहम्मद इमरान का कहना है कि फैजान को फेमस होने का जुनून सवार था। इंटरनेट अकाउंट पर भड़काऊ सामग्री अपलोड करने से उसे कई बार समझाया, लेकिन वह समझ नहीं पाया और दहशतगर्दी की राह पर चल पड़ा। उसका यह कदम पूरे परिवार के लिए कलंक बन गया। फैजान के परिवार में माता-पिता व एक भाई है। पिता की जूनी इंदौर लाइन पर लेथ मशीन की दुकान है। उसी में फैजान काम करता है। वहीं रकीब आईएसआईएस संगठन से जुड़ा है। फैजान व रकीब दोनों की जिहादी मानसिकता थी।

● **बृजेश सिंह**

कसाब और यासीन जैसा बनना चाहता था फैजान

मप्र एटीएस ने गत दिनों बड़ी कार्रवाई में खंडवा जिले से प्रतिबंधित संगठन- इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) से जुड़े आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया है। आतंकी फैजान खुद को बड़ा मुजाहिद साबित करना चाहता था। उसने इंटरनेट मीडिया पर जिहादी पोस्ट भी की थीं। मप्र एटीएस के आईजी डॉ. आशीष ने बताया कि आतंकी फैजान के इरादे बेहद खतरनाक थे। वह लोन वुल्फ अटैक करके स्वयं को इंडियन मुजाहिद्दीन के यासीन भटकल एवं सिमी सरगना अबु फैजल व कसाब की तरह बड़ा मुजाहिद साबित करना चाहता था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसके द्वारा स्थानीय अवैध हथियार कारोबारी तथा राज्य के बाहर के लोगों से संपर्क करके पिस्टल एवं कारतूस एकत्र किए जा रहे थे। आतंकी के पास से पिस्टल, कारतूस और काफी जिहादी साहित्य बरामद किया गया है। एटीएस के अनुसार, फैजान के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे। इसके लिए उसकी योजना लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की थी। इसे अंजाम देने के लिए वह सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिजनों की निगरानी व रैकी कर रहा था। आरोपित की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है और एटीएस उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगाने में जुटी है। एटीएस ने आतंकी के पास से 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन के अलावा आईएम, आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों से संबंधित जिहादी साहित्य व सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म भी बरामद किए हैं।

भोले बाबा का मायाजाल

सत्संग में बाबा के बगल में पत्नी नहीं मामी बैठती हैं!

केदार नगर का घर हर हफ्ते दो दिन सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए खुलता है। घर खोलने के लिए बाबा के लोग आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहां सिर्फ बाबा के घर के दर्शन करने के लिए उनकी चौखट को चूमने के लिए बड़ी तादाद में दूरदराज से महिलाएं यहां आती हैं। उनके गांव वाले बताते हैं कि बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है। लेकिन उनके साथ सत्संग में सिंहासन में उनके बगल में बैठने वाली महिला उनकी पत्नी नहीं, बल्कि मामी हैं। बाबा के रिश्ते अपने भाई के साथ ही ठीक नहीं हैं। इसलिए वो अब अपने गांव भी नहीं जाता। फिलहाल उनके भक्त उप्र के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं। जो सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। फिलहाल हाथरस वाले हादसे के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। एफआईआर में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद से बाबा फरार यानी गायब हैं।

एक कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। हाथरस में 121 मौतों के जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का भी एक अतीत है। उसके अतीत में ऐसी काली कहानियां छिपी हैं, जिन्हें सुनने और जानने के बाद ये हैरानी होती है कि आखिर उप्र पुलिस का एक मामूली सा कांस्टेबल अचानक एक रोज इतना बड़ा और महा प्रतापी बाबा कैसे बन गया?

दरअसल, सूरजपाल सिंह जाटव कभी उप्र पुलिस का एक सिपाही हुआ करता था। इस दौरान लंबे समय तक उसकी पोस्टिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू में रही। लेकिन नौकरी के दौरान ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और इसी जेल यात्रा के चलते उसकी पुलिस की नौकरी भी चली गई। लेकिन जेल में रहते हुए न जाने कौन सा ज्ञान मिला कि बाबा बन गया। जेल से बाहर आकर यौन शोषण के आरोपी पुलिस वाले से सीधे सत्संग करने और उपदेश देने वाला संत बन बैठा। इसके भजन प्रवचन की शुरुआत पहले इसके घर से हुई। फिर देखते ही देखते इसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और तब घर से निकलकर सत्संग का सिलसिला अड़ोस-पड़ोस में, फिर खुली जगहों में, पंडालों में और अलग-अलग राज्यों में शुरू हो गया। बाबा अपने सत्संगों में अपनी नौकरी जाने की बात कभी नहीं कहता।

वो ये बताता कि भगवान के दर्शन होने के बाद उसने खुद ही पुलिस की नौकरी से वॉलेंटियरली रिटायरमेंट ले लिया है। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल सिंह जाटव पर सिर्फ यौन शोषण की एक एफआईआर ही दर्ज हुई थी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसके ऊपर अब तक पांच मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें 1-1 केस उप्र के आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रूखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज हुआ है। बाबा को जानने वाले बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया है। उसके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन वो दूसरे बाबाओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनता था और ना ही उनकी तरह बाल और दाढ़ी रखता था, बल्कि इसके उलट वो हमेशा सफेद सूट में ही नजर आता और शायद यही उसकी एक यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्वाइंट भी बन गई। इसके बाद बाबा ने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर दी। उसके चाहने वालों में गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों की तादाद ही ज्यादा है। उन दिनों बाबा के घर के बाहर एक हैंडपंप हुआ करता था। बाबा ने उसके पानी को चमत्कारिक बताना शुरू कर दिया और लोग उसी हैंडपंप का पानी पीने के लिए दूर-दूर से आने लगे। इसके बाद बाबा ने जहां-जहां आश्रम बनाए या जहां-जहां भी उसका ठिकाना होता, वहां हैंडपंप जरूर लगा लेता।

भक्त हैंडपंप का पानी पीकर खुद को धन्य समझने लगते। बाबा को जानने वाले एक शख्स पंकज ने बाबा से जुड़ा एक वाकया बताया। उनका कहना है कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव की अपनी कोई संतान नहीं है। उसने अपनी भतीजी को गोद ले लिया था। कुछ समय बाद उसे कैंसर होने की बात सामने आई। एक बार जब बाबा सत्संग से लौटकर आए, तब तक उनकी गोद ली हुई भतीजी की मौत हो चुकी थी। तब बाबा के अनुयायी उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाहते थे। क्योंकि उन्हें यकीन था कि बाबा अपने चमत्कार से अपनी बेटी को ठीक कर देंगे। बल्कि कुछ तो दावा कर रहे थे कि बाबा ने अपनी बेटी को ठीक कर भी दिया है। इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार कहानी में पुलिस की एंट्री हुई और अनुयायियों पर लाठीचार्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में इस मामले में बाबा बरी हो गया।

58 वर्षीय सूरजपाल सिंह जाटव कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव के एक दलित परिवार से है, जो हाथरस से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इस गांव की प्रधान नाजिस खानम के पति जफर अली का कहना है कि वो शादीशुदा हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं। पुलिस बल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम भोले बाबा रख लिया था, जबकि उनकी पत्नी को माताश्री के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार संपन्न था। वो तीन भाईयों में दूसरे नंबर के हैं।

प्रधानपति ने आगे बताया कि उनके बड़े भाई की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जबकि उनके छोटे भाई राकेश, जो एक किसान हैं, अभी भी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। उन्होंने गांव में अपनी 30 बीघा जमीन पर आश्रम बनवाया है। दूसरे जिलों और यहां तक कि राज्यों से भी लोग उनका आशीर्वाद लेने आश्रम आते हैं। उन्हें आश्रम में रहने की सुविधा भी दी जाती है। अपने खिलाफ किसी साजिश के संदेह में उन्होंने गांव छोड़ दिया था। बाबा अपने गांव से निकलकर पहले आगरा के केदारनगर में रहते थे। वहां बाबा के पड़ोसियों का अपना अलग ही दर्द है। उनका कहना है कि बाबा अब अपने पुराने मकान में नहीं आते। यहां आए हुए उन्हें 15 साल हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद बाबा के भक्त उनके पुराने मकान में हाजिरी लगाते हैं। भक्तों की भीड़ से अक्सर उनके घर के पास की गली बंद हो जाती है। कई बार प्रोग्राम के बाद पड़ोसियों की बाइक और दूसरी छोटी-मोटी चीजें चोरी चली जाती हैं।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

बुंदेलखंड बनेगा पावर हाउस

दशकों से देश के सबसे शुष्क और पिछड़े क्षेत्रों में शुमार बुंदेलखंड रीजन अब प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इस परिक्षेत्र में विगत 7 साल में सर्वाधिक विकास कार्य किए गए हैं। हाल ही में 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। इसके बाद बुंदेलखंड का पूरा इलाका उप्र के लिए ऊर्जा का नया हब बनने जा रहा है। यहां स्थापित होने वाली अधिकतर परियोजनाएं सौर ऊर्जा के उत्पादन पर आधारित हैं। तकरीबन 10 बड़ी परियोजनाएं ऐसी हैं जो सीधे-सीधे सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। इन परियोजनाओं से ही तीन हजार मेगावाट से अधिक का विद्युत उत्पादन होगा।

दरअसल, बुंदेलखंड में वर्ष 2017 के बाद से विशेष ध्यान दिया जाने लगा। शुष्क और पिछड़ा इलाका होने और कनेक्टिविटी का जरिया न होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार शुरू से ही धीमी रही है। बावजूद इसके पिछले 7 वर्षों में एक के बाद एक विकास और आधारभूत संरचनाओं से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट के जरिए निवेशकों को इस रीजन में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। इसके परिणामस्वरूप उप्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एक साल बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए तकरीबन 30 हजार करोड़ की 29 बड़ी परियोजनाओं ने बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित करना आरंभ कर दिया है। इनमें भी 10 परियोजनाएं सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, जो कि बुंदेलखंड के हमीरपुर को छोड़कर बाकी सभी 6 जनपदों (जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा) में स्थापित हो रही हैं। अकेले झांसी जनपद में तीन सोलर पॉवर परियोजना स्थापित होने जा रही हैं।

बुंदेलखंड रीजन के झांसी मंडल के मुख्यालय जनपद झांसी की बात करें तो यहां टुस्को की ओर से 600 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। 3430 करोड़ की इस परियोजना से 300 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसके अलावा फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 1200 करोड़ से 100 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना करेगा, जिससे 1000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं सन सोर्स एनर्जी 600 करोड़ से 135 मेगावाट ओपन एक्सेस सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा, जिससे 2000 रोजगार का सृजन होगा। ललितपुर जिले में टुस्को की ओर से 600 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। 3450 करोड़ की इस परियोजना से 300 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी प्रकार सूर्य ऊर्जा फॉर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 150 करोड़ की लागत से 10-15 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो 200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। बांदा में अवाडा इंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड 350 करोड़ की लागत से 750 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इसके अलावा 62 करोड़ की लागत से सनश्योर सोलर पार्क एट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है।

चित्रकूट की बात करें तो यहां टुस्को लिमिटेड 4700 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना करेगा। इससे 400 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा श्री सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 202 करोड़ से सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना करेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा में टुस्को लिमिटेड द्वारा 1008 करोड़ से 155 मेगावाट अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। इससे 78 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। महोबा में ही आईबी वोगट सोलर फॉर प्राइवेट लिमिटेड 80 करोड़ की लागत से सोलर पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। अन्य बड़ी परियोजनाओं में 2840 करोड़ से रेलवे के एलबीएच कोच प्रोजेक्ट और ट्रैक वर्क का प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

संत मां कर्मा मानव संवर्धन समिति की ओर से 501 करोड़ की लागत से प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ललितपुर में 30 करोड़ की लागत से स्टोन माइनिंग और 20 करोड़ से डिफेंस सेक्टर के लिए गन प्रोपलेंट प्रोजेक्ट स्थापित की जा रही है। चित्रकूट में सौराष्ट्र भुज फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ से फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। यही नहीं चित्रकूट में वरुन बेवरेज लिमिटेड 496 करोड़ और शुक्ला इंटरप्राइजेज फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 200 करोड़ का बड़ा निवेश कर चुकी है। इसी प्रकार हमीरपुर में मैन्यूफैक्चरिंग और एग्री बेस्ड सॉयल प्रोजेक्ट्स में भी तीन बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 940 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महोबा में भी देशी भोग की ओर से फूड प्रॉसेसिंग मेकिंग यूनिट जीआरएस होटल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 50-50 करोड़ का निवेश किया गया है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

डिफेंस कॉरीडोर में बंपर निवेश

बुंदेलखंड की दशा व दिशा डिफेंस कॉरीडोर के झांसी नोड में हो रहे बंपर निवेश, सोलर परियोजनाओं और बल्क ड्रग पार्क से बदलेगी। उप्र में बन रहे डिफेंस कॉरीडोर के झांसी नोड में उप्र सरकार को अब तक 7514.91 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। इस निवेश के लिए 26 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे 5774 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। औद्योगिक विकास विभाग के तहत कार्यरत इन्वेस्ट उप्र के मुताबिक डिफेंस कॉरीडोर में अब तक हस्ताक्षरित 26 इकाइयों के लिए समझौता ज्ञापनों में से 8 के लिए जमीन का आवंटन पूरा कर दिया गया है। कॉरीडोर के झांसी नोड में लग रही इन इकाइयों में 3309.11 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1570 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिन उद्यमों को जमीन आवंटन किया जा चुका है उनमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डब्ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स, लारेंको डिफेंस, मुरारी इंजीनियरिंग व स्वर्ण इंफ्राटेल प्रमुख हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरीडोर में रक्षा उद्योग से संबंधित कलपुर्जे व अन्य सामाग्री तैयार करने के लिए छोटे व मझोले उद्योग भी लगेंगे।

डॉ. मोहन का मनमोहनी प्रयास

क्या मप्र बन पाएगा बिजनेस का हब?

मप्र के आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगाएगी। आशा की जा रही है कि डॉ. मोहन के मनमोहनी प्रयास से मप्र बिजनेस का हब बनेगा। ऐसा इसलिए कि मप्र में एक समान औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह फॉर्मूला कारगर साबित होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि प्रदेश में अभी तक 7 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किए गए हैं। इस दौरान लाखों करोड़ रुपए के एमयू भी साइन हुए हैं। लेकिन कई करार खत्म हो गए, तो कई अधर में लटके हैं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में अब तक औद्योगिक विकास और निवेश के नाम पर विदेश यात्राओं और इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होता रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत न निवेश आया और न ही औद्योगिक विकास हो पाया। इन चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेशभर में समुचित औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में अभी तक कुछ ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो पाया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से क्षेत्रवार निवेश और औद्योगिक विकास की पहल होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुराने निवेश के प्रस्तावों का क्या हुआ। सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अब तक 7 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किए हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की राह अभी तक देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि डॉ. मोहन यादव का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फॉर्मूला कितना सफल हो पाता है।

विदेशों के दौरे और इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य होता है कि विदेशी कंपनियां प्रदेश में निवेश करें और विकास में सहायक हों। लेकिन पिछली तमाम इन्वेस्टर्स मीट के बाद प्रदेश के हिस्से में क्या आया ये बात गौर करने वाली है। साल 2007 से शुरू हुई इन्वेस्टर्स मीट में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सवाल यही सामने आता है कि इन तमाम आयोजनों के बाद प्रदेश में कितना निवेश आया, कुल कितने प्रोजेक्ट्स साइन होकर जमीन पर उतरे और कितने बेरोजगारों को काम मिला। सरकार की मानें तो प्रदेश में वर्ष 2007 से लेकर अब तक हुईं इन्वेस्टर्स मीट इसके अलावा समय-समय पर हुए अन्य आयोजनों का ही नतीजा है कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने मप्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। देश के नामी-गिरामी उद्योगपति मप्र आकर निवेश कर रहे हैं। केवल एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि उन सभी क्षेत्रों में निवेशकों की दिलचस्पी सामने आ रही है, जहां जरा भी संभावनाएं उन्हें दिखाई दे रहीं हैं। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर सुदूर कस्बों और यहां तक कि चंबल के बीहड़ों में भी उद्योगों की नींव डलने लगी है। लेकिन धरातल पर फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मप्र में एक समान औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो फॉर्मूला बनाया है उसकी अगली कड़ी में 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस कॉन्क्लेव से केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में निवेशकों की सहभागिता से विकास के द्वार खुलेंगे।

1.60 लाख करोड़ का होगा निवेश

मप्र के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगाएगी। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न औद्योगिक समूहों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक करके की है। इसमें रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपए की इच्छा जताई है। बैतूल, शहडोल और दमोह में 17 हजार करोड़ रुपये के निवेश का जेएस डब्ल्यू लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है।

उज्जैन में हुई पहली रीजनल इन्वेस्टर्स समिट और मुंबई में मिले निवेश के प्रस्तावों को मिला लिया जाए तो प्रदेश में 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गत दिनों प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेश के लिए सबसे अच्छा राज्य है। यहां बिजली, भूमि, पानी और मानव संसाधन उपलब्ध है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। उद्योग प्रदेश के सभी अंचलों में लगे, इसलिए रीजनल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की है। पहली समिट उज्जैन में हुई, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। एग्रो आयल एंड गैस के प्रबंध संचालक प्रणव अडानी ने 75000 करोड़, जेके सीमेंट ने 4000 करोड़, एशियन पेंट्स ने 2000 करोड़, एचईजी ने 1,800 करोड़, वोल्वो आयशर और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने 1500-1500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इस निवेश से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह मुंबई में विभिन्न उद्योगपतियों से अलग-अलग चर्चा में 73 हजार

2007 से 2016 और 2023 में 6 जीआईएस

आयोजन स्थल	निवेश प्रस्ताव	राशि
इंदौर जीआईएस अक्टूबर 2007	102	1,20,621 करोड
खजुराहो जीआईएस अक्टूबर 2010	109	2,37,789.79 करोड़
इंदौर जीआईएस अक्टूबर 2012	425	1,67,551.09 करोड़
इंदौर जीआईएस अक्टूबर 2014	3160	4,27,259.1928 करोड़
इंदौर जीआईएस अक्टूबर 2016	2635	5,17,269.6942 करोड़
इंदौर जीआईएस जनवरी 2023	6,957	15,42,550.84 करोड़
कुल निवेश प्रस्ताव	13,388	30,13,041.607 करोड़

धरातल पर 3.47 लाख करोड़ का आया पूंजी निवेश

आयोजन स्थल	निवेश संख्या	पूंजी निवेश	रोजगार मिला
जीआईएस अक्टूबर 2007	19	26,165.35 करोड़	7240
जीआईएस अक्टूबर 2010	27	24883.91 करोड़	13,447
जीआईएस अक्टूबर 2012	257	26929.76 करोड़	1,02,425
जीआईएस अक्टूबर 2014	143	59136.39 करोड़	13,863
जीआईएस अक्टूबर 2016	223	197647.8039 करोड़	27,462
जीआईएस जनवरी 2023	93	13,128.19 करोड़	42,612
कुल	**762**	**3,47,891.4039 करोड़**	**2,07,049**

15 साल में मप्र में कितना निवेश

वर्ष	एमओयू	निवेश प्रस्ताव	जमीन पर उतरे	रोजगार संख्या
2007	102	1.20 लाख करोड़	17,311 करोड़	49,750
2010	109	2.35 लाख करोड़	26,879 करोड़	25,000
2012	425	3.50 लाख करोड़	26,054 करोड़	31,530
2014	3,160	4.35 लाख करोड़	49,272 करोड़	38,750
2016	2,635	5.63 लाख करोड़	32,597 करोड़	92,700
	6,431	17.03 लाख करोड़	1,52,113 करोड़	2,37,730

(2019 में कमलनाथ सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बजाय मैन्निफिसेंट मप्र का आयोजन किया था, जिसमें 74 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव)

950 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई गई है। इसमें रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपए, जेएस डब्ल्यू लिमिटेड ने बैतूल, शहडोल और दमोह में 17 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। एलएंडटी ने इंदौर में 2 हजार करोड़, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने नागदा में 4000 करोड़ गोदरेज कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स ने मालनपुर भिंड में 450 करोड़ और योटा डेटा सर्विस ने इंदौर में 500 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे भी लगभग एक लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। महिंद्रा होलीडे ने देवास और बांधवगढ़ में 750, ओबेराय होटल ग्रुप ने 400 करोड़ और साज होटल ग्रुप ने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं।

जबलपुर में 1,222 करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन के बाद 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी। इसमें बायर सेलर मीट भी होगी। विभिन्न समूहों के लगभग एक हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे। 70 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। इनमें 1,222 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 3,444 को रोजगार मिलेगा। इस समिट में रक्षा और कृषि उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश की संभावना है। इसी तरह का आयोजन सितंबर में ग्वालियर और अक्टूबर में रीवा में होगा। सागर या दमोह में भी समिट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में न केवल उद्योग लगे, बल्कि उत्पाद भी यहीं तैयार हों। कच्चा माल अन्य प्रांतों में न जाए। इससे रोजगार के अवसर और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। 25 जुलाई को तमिलनाडु के कोयंबटूर में उद्योगपतियों से चर्चा होगी। अगस्त में बेंगलुरू और सितंबर में दिल्ली में इसी तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। सितंबर में ही इंदौर में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव होगा। उज्जैन में मेडीकल डिवाइस पार्क को विस्तार दिया जा रहा है तो धार में पीएम मित्रा पार्क से बड़ा रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो किसी भी कारण से उद्योग नहीं लगा पाएगा, उससे भूमि लेकर दूसरे को दे दी जाएगी। पूर्व में हुई इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहा कि उसमें भी निवेश आया है।

अभी असंतुलित औद्योगिक विकास

करीब दो दशक के दौरान औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में जितनी चर्चा मप्र की हो रही है, उतनी शायद ही किसी राज्य की हो। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास भी हुआ है। लेकिन यह औद्योगिक विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। ऐसे में प्रदेश में औद्योगिक विकास की असंतुलित तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में एक समान औद्योगिक विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फॉर्मूला बनाया है। पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में आयोजित हो चुका है। अब दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित होने जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। कॉन्क्लेव में अधिक से अधिक निवेशक आएं ताकि जबलपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एमपीआईडीसी की कार्यकारी संचालक सृष्टि प्रजापति ने कहा कि एमपीआईडीसी द्वारा 20 जुलाई को नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्चरल एंड इनफॉर्मेशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिफेंस, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, एग्रोफूड सहित विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। औद्योगिक विकास होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास में गति परिलक्षित होने लगेगी।

जबलपुर में होने वाले क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के लिए राज्य सरकार बड़े उद्योगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि सहायक इकाइयों को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विक्रेता आधार का विस्तार किया जा सके। रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और खनिजों सहित अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग सम्मेलन के लिए शीर्ष उद्योगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सरकार का ध्यान अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने पर नहीं बल्कि महाकौशल क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने और एमएसएमई के लिए एक मंच तैयार करने पर है। नोडल मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने उद्योगपतियों और संभावित निवेशकों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। एमपीआईडीसी के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का दूसरा संस्करण 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। हमने सम्मेलन के लिए उद्योगों और संभावित निवेशकों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। चूंकि यह एक क्षेत्रीय सम्मेलन है, इसलिए इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को सहायता प्रदान करना और उनके और बड़े खिलाड़ियों के बीच संबंध स्थापित करना है। स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा, कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा, खनिज और कृषि जबलपुर में उद्योग

सम्मेलन के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। एमपीआईडीसी के पास जबलपुर में 15 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें पंधुरना जिले का बोरगांव, फूड पार्कऔर मनेरी औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। एमपीआईडीसी जबलपुर की कार्यकारी निदेशक सृष्टि प्रजापति ने कहा कि हमारा लक्ष्य देशभर से जबलपुर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। हमारे पास 15 औद्योगिक क्षेत्र और प्रचुर मात्रा में भूमि बैंक है। हम जबलपुर में निवेश के अवसरों के बारे में निवेशकों को सूचित करने के लिए प्रस्तुतियां दे रहे हैं।

निवेशक सम्मेलन का बदला कलेवर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की परिकल्पना पर निवेशक सम्मेलन का कलेवर अब बदल गया है। इसकी झलक उज्जैन में आयोजित पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्ट मप्र: रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के समापन समारोह के मौके पर कहा कि वह बात कम करने, काम ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। राज्य में उद्योग का यह प्रमुख कार्यक्रम 2007 में शुरू होने के बाद पहली बार औद्योगिक राजधानी इंदौर से बाहर हुआ। लेकिन यह एकमात्र बदलाव नहीं है। कई अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं। संभवत: पहली बाद मुख्य सम्मेलन के साथ-साथ शिलान्यास कार्यक्रम और फैक्टरियों के उद्घाटन भी किए गए हैं। इससे यह संदेश देने की कवायद की गई है कि उद्योग सम्मेलन केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 283 उद्योग समूहों के लिए 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पत्र भी जारी किए। इस कदम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आने और 26,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने रिमोट से 61 इकाइयों का उद्घाटन किया, जिनमें 10,064 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं और इनसे 17,000 से ज्यादा नई नौकरियों का सृजन हुआ है। इतना ही नहीं, सभी उद्घाटन और भूमिपूजन में स्थानीय विधायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए, जो 20 से अधिक अलग-अलग स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में मौजूद थे। यह उनके विधानसभा क्षेत्रों में लघु-उद्योग बैठकों को प्रतिबिंबित करता है। उनकी भागीदारी का उद्देश्य न केवल उन्हें स्वामित्व की भावना देना है बल्कि आगामी आम चुनावों के लिए तैयारी करना भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिला सम्मेलनों में स्थानीय भागीदारी होती है। राज्य के वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इस तरह राज्य के नीमच जिले में आयोजित एक बैठक में उपस्थित थे। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एक अन्य जिले से इस कार्यक्रम में शामिल थे।

अनिल अंबानी करेंगे 50 हजार करोड़ का निवेश

रिलायंस के अनिल अंबानी ने मप्र में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि उनका यह प्रस्ताव कितना विश्वसनीय है, क्योंकि पूर्व में भी अंबानी ने प्रदेश में रक्षा के क्षेत्र में निवेश करने का बड़ा प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। कॉन्क्लेव में ग्रेसिम के एचके अग्रवाल सहित कई उद्योगपतियों ने निवेश पर चर्चा की। अनिल अंबानी ने तो कहा कि जबलपुर में डिफेन्स सेक्टर में निवेश करना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। जेएसडब्ल्यू के पार्थ जिंदल ने बैतूल, शहडोल और दमोह में 17 हजार करोड़, एलएंडटी ने इंदौर में 2000 करोड़, गोदरेज ने भिंड में 450 करोड़, योटा डेटा सर्विस ने इंदौर में 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है। 5 बड़ी स्टार्टअप कंपनियों के साथ बैठक हुई। अब विदेशी निवेशक मप्र में संभावना देख रहे हैं। 25 जुलाई को कोयम्बटूर में निवेशकों से चर्चा होगी। अगस्त में बैंगलोर तो सितंबर में दिल्ली में ये कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक महिंद्रा हॉलिडे ने देवास-बांधवगढ़ में 750 करोड़ तो ओबरॉय समूह ने कई पर्यटक स्थलों पर 400 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है। साथ ही साज होटल समूह ने वाइल्डलाइफ टूरिज्म में कई जगह निवेश में रुचि ली है। जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ग्वालियर में सितंबर तो रीवा में अक्टूबर में ये कॉन्क्लेव होंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक ग्वालियर, रीवा, सागर के लिए प्रस्ताव मिलने लगे हैं। इंदौर में सितम्बर में टेक्सटाइल समिट होगी। 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। मुख्य फोकस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर होगा।

अगर आकार के हिसाब से देखें तो क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन बहुत छोटा था। दिसंबर 2022 में इंदौर में आयोजित सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि 2 दिन के आयोजन में राज्य में 15.42 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे 29 लाख नौकरियों का सृजन होगा। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन ने राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इसमें से सिर्फ अडाणी समूह ने 75,000 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है। क्षेत्रीय कॉन्क्लेव में हिस्सेदारों की संख्या भी पहले के वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तुलना में कम रही। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि यह क्षेत्रीय सम्मेलन था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जबलपुर, ग्वालियर और रीवा जैसे शहरों में इसी तरह के अन्य क्षेत्रीय सम्मेलन कराए जाएंगे। एक और उल्लेखनीय बदलाव निवेश आकर्षित करने के अभियान में सामाजिक क्षेत्र की पहल को जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने दूरदराज के गरीब मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस सेवा की भी शुरुआत की, जिससे मरीजों को बड़े अस्पतालों में पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने जोर दिया कि उद्योग को सभी की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है।

निवेश आकर्षित करने में मप्र अव्वल

अब पिछले डेढ दशक की औद्योगिक गतिविधियों का आंकलन करें तो हम पाते हैं कि देश में निवेश को आकर्षित करने में मप्र अव्वल है। दरअसल, यह नए दौर का मप्र है। बीते 15 वर्षों में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में जितनी चर्चा मप्र की हो रही है, उतनी शायद ही किसी राज्य की हो। यही कारण है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में हाल ही में हुए दो दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए। यहां 12 देशों से आए उद्यमियों के साथ ही 3700 से

अधिक उद्योगपति शामिल हुए। इस सम्मेलन के माध्यम से 17 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की राह भी आसान हुई। किसी भी राज्य में होने वाला निजी निवेश उसकी आर्थिक नीतियों का आईना माना जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बीते 5 वर्षों में प्रदेश सरकार निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने में अन्य राज्यों की तुलना में आगे ही रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में प्रदेशों में होने वाले विदेशी निवेश में मप्र की भागीदारी 1.6 प्रतिशत ही थी, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 5 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। पर्याप्त लैंड बैंक और उद्योग हितैषी नीतियों के प्रचार का लाभ भी प्रदेश को मिल रहा है। अब आवश्यकता है नीतियों को उद्योगों के लिए और अधिक कारगर बनाने की।

दो दशक पहले मप्र में निवेश का परिदृश्य अच्छा नहीं था। अधोसंरचनात्मक स्थिति खराब होने की वजह से औद्योगिक इकाइयां यहां आने के बजाय दूसरे राज्यों का रुख करती थीं। बीते वर्षों में प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से कार्य हुआ। अच्छी सड़कें, बेहतर लैंडबैंक, बिजली और पानी की उपलब्धता ने निवेशकों का ध्यान मप्र की ओर दोबारा आकर्षित किया। यहां होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों में देश-दुनिया के बड़े उद्योगपतियों ने पहुंचकर प्रदेश के औद्योगिक वातावरण और अधोसंरचना का गहराई से अध्ययन किया। निश्चित ही ये प्रयास प्रदेश के विकास की तस्वीर में बदलाव लाने में सफल साबित हुए और प्रदेश का औद्योगिक चेहरा बदलने लगा। इन सबके बावजूद तंत्र की असली परीक्षा निवेश करार के धरातल पर उतरने के बाद ही शुरू होती है। उद्योगों के लिए तीन वर्ष तक अनुमति की आवश्यकता नहीं, पोर्टल पर ही अपनी समस्याओं का समाधान और सिंगल विंडो जैसी सुविधाएं व्यवहार में पूरी तरह लागू नहीं हो पाईं। एक के बाद एक कई विंडो से गुजरने के बाद ही उद्योगपति लक्षित स्थल तक पहुंच पाते हैं।

मप्र के औद्योगिक परिदृश्य की बड़ी चुनौती नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना भी है। प्रदेश की बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। यहां अधोसंरचनात्मक ढांचे की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, जितनी उद्योगों को चाहिए। यही कारण है कि स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में ही उद्योगपति जाना चाहते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों की अपनी सीमा है। चाहे इंदौर के पास पीथमपुर हो या देवास का औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर भोपाल का गोविंदपुरा। इन औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास आवासीय क्षेत्र तेजी से विकसित होते चले गए। फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार की गुंजाइश यहां नहीं बची। उधर, पहले से स्थापित इन क्षेत्रों में बेहतर संपर्क और संसाधन होने से बाहर से आने वाले उद्योग इसी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि सरकार ने इस समस्या को देखते हुए नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर विकसित करना शुरू तो किए हैं, लेकिन इनकी गति धीमी होने से ये प्रभावी नहीं हो पाए हैं। प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर का एक पहलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी हैं। अकेले एमएसएमई के तहत ही प्रदेश में पौने दस लाख से अधिक उद्योग पंजीकृत हैं। इनकी पीड़ा यही है कि समिट जैसे आयोजनों के माध्यम से बड़े उद्योगों के लिए तो रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, लेकिन छोटे उद्योगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं जाता है। शहरी क्षेत्रों के पास की औद्योगिक जमीनें बड़े उद्योग ले लेते हैं और छोटे उद्योगों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में जमीन मुहैया करवा दी जाती हैं। वहां आवागमन और अधोसंरचना विकसित करने का खर्च ही इतना अधिक होता है कि छोटे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना कठिन हो जाता है। सरकार की अनुदान योजनाएं भी छोटे उद्योग और एमएसएमई के लिए कड़ी हैं। इसे अधिक लचीला बनाने की मांग इस क्षेत्र के उद्योगपति लंबे समय से कर रहे हैं।

प्रदेश में निवेश कर चुके उद्योगपतियों के अलावा स्थानीय उद्योगपतियों की यह पीड़ा भी है कि उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में यहां महंगी बिजली मिलती है। औद्योगिक इकाई के लिए नया बिजली संयोजन लेने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। इसी तरह प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करने के लिए उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बदले में दी जा रही पीएनजी पर टैक्स की दर मप्र में सबसे अधिक है। पीएनजी पर महाराष्ट्र में 4 प्रतिशत वैट (टैक्स) लगता है तो मप्र में पीएनजी पर सरकार 13 प्रतिशत वैट वसूल रही है।

इंडस्ट्रियल टाउनशिप फेल, अब गेल का खेल

मप्र में औद्योगिक विकास की हकीकत का आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि आष्टा और देवास के बीच 20 हजार एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव बनाया गया था। यहीं नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनना था। इसको लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन योजना फेल हो गई। वहीं अब पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। उसने आष्टा के पास 800 हेक्टेयर जमीन पसंद कर ली है। इस जमीन में से 450 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, जबकि 350 हेक्टेयर की भूमि निजी स्वामित्व वाली है। सीहोर के अधिकारियों के अनुसार कंपनी को सीहोर इसीलिए पसंद आया है क्योंकि यह केंद्र में है और इसकी कनेक्टिविटी इंदौर, भोपाल सहित अन्य राज्यों से भी आसान है। कंपनी विवादित जमीन से बच रही थी। वह जमीन सीहोर के आष्टा में मिल रही है। कंपनी ने जहां जमीन पसंद की है क्योंकि वहां आसपास किसी तरह के अतिक्रमण नहीं हैं, न ही धार्मिक स्थल है और ना ही किसी तरह की कोई समस्या है। यही कारण है कि कंपनी को यह जमीन पसंद आ गई। कंपनी के प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद यहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं एमपीआईडीसी के द्वारा दी जाएगी। गेल यहां पर 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अधिकारियों के अनुसार गेल का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो 5 से 6 साल में यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा।

टूट रही नक्सलियों की कमर

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ में सेंट्रल कमेटी के बड़े नक्सलियों का ठिकाना है। इन इलाकों में नक्सलियों के कई बड़े लीडर भी मौजूद हैं। इस वजह से यह इलाका काफी कोर इलाका भी माना जाता है। यहां सेंट्रल कमेटी के बड़े लीडरों की मौजूदगी हमेशा रहती है। इधर, सेंट्रल कमेटी के बड़े लीडर काफी उम्रदराज के हो गए हैं। इतना ही नहीं उनके पास कोई पहचान-पत्र भी नहीं है। ऐसे में ये कहीं इलाज कराने भी नहीं जा सकते हैं। नक्सली लीडर के जंगल में ही रहकर अपना इलाज करवाने की सूचना पुलिस महकमे को भी है। बताया जा रहा है कि उम्रदराज नक्सली शहर या मेट्रो सिटी इलाज के लिए जाते हैं तो बिना पहचान पत्र के इनका इलाज नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं वे अब सुरक्षा बल के जवानों के निशाने में आ गए हैं। ऐसे में उनकी मुसीबत और बढ़ गई है।

वहीं उम्रदराज हो चुके सेंट्रल कमेटी के नक्सली नेता रमन्ना, आरके की मौत कोरोनाकाल में इलाज नहीं मिलने से हो गई थी, लेकिन अब भी सेंट्रल कमेटी के गणेश उइके, सोनू, पाप राव जैसे कई बड़े लीडर्स की उम्र 65 से 70 पार हो गई है। इन्हें अब सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं लगातार हो रही मुठभेड़ के दौरान बड़े नक्सली नेताओं के लिए अब बचना मुश्किल हो गया है। फिलहाल इन नक्सलियों की पहचान भी सामने नहीं आ पा रही हैं। इस मामले में सुरक्षा महकमे के पास पुख्ता इनपुट भी है। एक बार फिर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने नक्सलियों से अपील की है कि वे मुख्यधारा में लौट आएं और आत्मसमर्पण करें। अबूझमाड़ को फौरन छोड़ दें वरना अंजाम उनके लिए घातक होगा। सुरक्षा बलों ने साल 2014 से माओवादी बहुल इलाकों में शिविर लगाना शुरू किया था। साल 2019 के बाद 250 से अधिक शिविर स्थापित किए गए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-23 की तुलना में साल 2004-14 में नक्सली हिंसा की घटनाएं 14862 से घटकर 7128 हो गई हैं। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौत की संख्या साल 2004-14 के मुकाबले 2014-23 में 72 फीसदी कम हो गई है। ये संख्या 1750 से घटकर 485 हो गई है। वहीं आम लोगों के मौतों की संख्या 68 फीसदी घटकर 4285 से 1383 हो गई है। साल 2010 में हिंसा वाले जिलों की संख्या 96 थी। साल 2022 में यह 53 फीसदी घटकर 45 हो गई। इसके साथ ही हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या साल 2010 में 465 से घटकर साल 2022 में 176 हो गई। पिछले 5 वर्षों में उन 90 जिलों में 5 हजार से अधिक डाकघर स्थापित किए गए, जहां माओवादी की सक्रियता है। अक्सर उनका मूवमेंट देखा जाता है।

गत दिनों कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में बिनागुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की टीम ने घेरकर बड़ी संख्या नक्सलियों को मार गिराया। यह कार्रवाई सटीक खुफिया सूचना के आधार पर की गई। यही कारण है कि सुरक्षाबल इस आमने-सामने की लड़ाई में नक्सलियों पर हावी दिखे। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। आमतौर पर नक्सली अपने साथियों के शव साथ ले जाने में सफल रहते हैं। इसलिए हताहत नक्सलियों की संख्या का सही अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता था, परंतु इस बार परिस्थिति अलग थी। सुरक्षाबल योजना और तैयारी में नक्सलियों पर भारी पड़े। इसीलिए न केवल अभियान सफल रहा, अपितु सभी 29 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। योजना की सटीकता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ तीन जवान घायल हुए। कांकेर में मिली सफलता इकलौती नहीं है। हाल के दिनों में बस्तर संभाग के दक्षिणी छोर में स्थित कोरचोली और लेंड्रा के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया था। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों का कहना है कि इस बार हताहतों की संख्या और बढ़ी है। मुठभेड़ में मारे गए आधा दर्जन से अधिक शव नक्सली अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए हैं। यही नहीं, 10 घंटे तक चली मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए हैं। नक्सली अब समझ रहे हैं कि बस्तर से उनके बाहर जाने का समय आ गया है।

अबूझमाड़ के कोड़तामेटा क्षेत्र के घमंडी व हिकुलनार के जंगल में सुरक्षा बल ने गत दिनों 72 घंटे अभियान चलाकर वहां नक्सलियों के हथियार बनाने के अस्थायी डेरे को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस डेरे में नक्सलियों के शीर्ष स्तर के केंद्रीय समिति के नेता सोनू उर्फ भूपति, कोसा व माड़ डिविजन की प्रभारी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य माड़ डिवीजन की सचिव रनिता उर्फ जयमति सहित 70 से 80 नक्सली उपस्थित थे, पर सुरक्षा बल के आने की भनक लगने के बाद वे वहां से भाग खड़े हुए और पीछे रह गई टीम के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

तंगहाली के शिकार नक्सली छाप रहे नकली नोट

नक्सली संगठनों की तंगहाली का आलम यह है कि वो नकली नोट छापकर दिन गुजारने को मजबूर हैं। उनके विभिन्न इलाकों से सुरक्षाबलों ने नकली नोट बनाने के उपकरण मसलन, कलर प्रिंटर मशीन, इन्वर्टर मशीन, कलर इंक और 50, 100, 200 व 500 रुपए के नकली नोट के सैम्पल और भरी मात्रा में बंदूक, वायरलेस सेट, मैग्जीन पोच, नक्सली काली वर्दी कपड़ा व भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस अफसर के अनुसार वर्ष 2022 में बड़े नक्सली कैडरों के द्वारा प्रत्येक एरिया कमेटी के एक-एक नक्सली सदस्य को नकली नोट छापने का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद अपने-अपने एरिया कमेटी में प्रशिक्षित नक्सली के द्वारा नकली नोट छापकर अंदरूनी क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों में खपाया जा रहा है। खुद को आदिवासियों का हितैशी बताने वाले नक्सली संगठन नकली नोट छापकर आदिवासियों के साथ छल-कपट कर रहे है। क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा रात-दिन मेहनत मजदूरी कर बनाए गए सामान को नकली नोट से खरीदकर उन्हें लगातार धोखा दे रहे हैं। इन नकली नोटों का परिचालन कर नक्सली भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंचा रहे हैं।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी। आगामी चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार जनता को कई तरह की सौगात देगी। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। जानकारों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में अब 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इसका बजट में प्रावधान किया जाएगा। वहीं घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पर भी सरकार का फोकस इस बजट में देखने को मिलेगा। अधिकारी बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

अबकी बार... सबका ख्याल!

बजट 2024 से आम जनता, बिजनेस करने वाले, सैलरीड क्लास और स्टूडेंट्स को काफी उम्मीदें हैं। बजट 2024 कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा तय करेगा। वित्तमंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया था। ग्लोबल रिसेशन के संकेतों के बीच पेश होने वाले इस बजट में घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ जॉब्स पर फोकस हो सकता है।

वहीं, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सातवीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। बजट की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में 23 तारीख को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता, बिजनेस करने वाले, सैलरीड क्लास और स्टूडेंट्स को काफी उम्मीदें हैं। वैश्विक मंदी के संकेतों के बीच पेश होने वाले इस बजट में घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ रोजगार पैदा करने पर फोकस हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सातवीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। इससे पहले भी उनके नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज हैं।

वित्तवर्ष 2024-25 के आम बजट में टैक्सपेयर्स खासकर लोअर इनकम कैटेगिरी के लोगों को राहत देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि खपत को बढ़ावा मिल सके। उद्योग जगत के लोगों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को यह सुझाव दिया है। वित्तमंत्री 23 जुलाई को 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं, जो नई सरकार का पहला प्रमुख नीति दस्तावेज होगा। उद्योग जगत ने वित्तमंत्री से कॉरपोरेट टैक्स को कम करने, कर छूट को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर आधार को व्यापक बनाने का भी आग्रह किया।

उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि कंप्लायंस में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर प्रणाली को युक्तिसंगत और सरल बनाना चाहिए। कर व्यवस्था को अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाने के लिए कॉरपोरेट कर दरों को कम करने, कर छूट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और कर आधार को व्यापक बनाने जैसे उपायों पर विचार करना चाहिए। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि सरकार 11.1 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लक्ष्य के साथ समझौता किए बिना 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.9-5 प्रतिशत तय कर सकती है। इससे पहले एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने इसके 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि राजस्व के मोर्चे पर अनुकूल घटनाक्रम वित्तवर्ष 2024-25 में राजकोषीय स्थिति की दृष्टि से सकारात्मक संकेत देते हैं। इक्रा का मानना है कि चालू वित्तवर्ष के बाद राजकोषीय मजबूती काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। जॉपर इंश्योरटेक के को-फाउंडर और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) मयंक गुप्ता ने कहा कि बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा

सातवीं बार बजट पेश करेंगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सातवीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वित्तमंत्री रहते हुए लगातार छह बार बजट पेश किया था। अब तक किसी भी वित्तमंत्री ने लगातार इतने बजट पेश नहीं किए हैं। इस मामले में वह मोरारजी देसाई के छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। इससे पहले सीतारमण ने 2019 और 2024 के दो अंतरिम बजट और चार पूर्ण बजट पेश किए हैं। सीतारमण के नाम मोदी सरकार में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बनने का रिकॉर्ड भी है। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। 2017 में पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। इससे पहले वह उद्योग और वाणिज्य मंत्री थीं। अरुण जेटली (वित्त मंत्री 2014-19) के बीमार होने पर सीतारमण ने 2019 के आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित मोदी सरकार में वित्त विभाग का प्रभार संभाला था।

देने और विशेष रूप से निम्न आय वर्ग को राहत देने वाली नीतियों पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है, ताकि खपत को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बीमा के लिहाज से आयकर अधिनियम की धारा 80सी में संशोधन करना चाहिए, ताकि अधिक व्यक्तियों को बीमा उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत टर्म जीवन बीमा के लिए छूट भी होनी चाहिए।

डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने सुझाव दिया कि सरकार को पीएलआई योजनाओं के दायरे का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर उन क्षेत्रों के लिए ऐसा करना चाहिए, जो अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं, जैसे कपड़ा, हस्तशिल्प और चमड़ा। मजूमदार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे सफल क्षेत्रों में योजनाएं जारी रहनी चाहिए। रेलिगेयर फिनवेस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पंकज शर्मा ने उम्मीद जताई कि ब्याज दर सब्सिडी के जरिए वित्तपोषण लागत को कम करने और नीतिगत उपायों से ऋण तक पहुंच को आसान बनाने की जरूरत है। एसोचैम ने किसानों के लिए उत्पादकता, बाजार पहुंच और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों का भी सुझाव दिया है।

बजट में खासतौर पर किसानों को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की जाने वाली घोषणाओं से काफी आस है। वे चाहते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का पर्याप्त पैसा मिले। किसान शुरू से ही अलग-अलग फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ एमएसपी के बढ़ने से उनको पूरा फायदा मिलेगा। इस सिलसिले में भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं, जिनमें एमएसपी सिस्टम को नए रूप में पेश करने समेत निजी इकाईयों को खरीद में शामिल करना और आजीविका क्रेडिट कार्ड शुरू करना है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ने कृषि क्षेत्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को नए फॉर्मेट में लाने को कहा है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सरकार

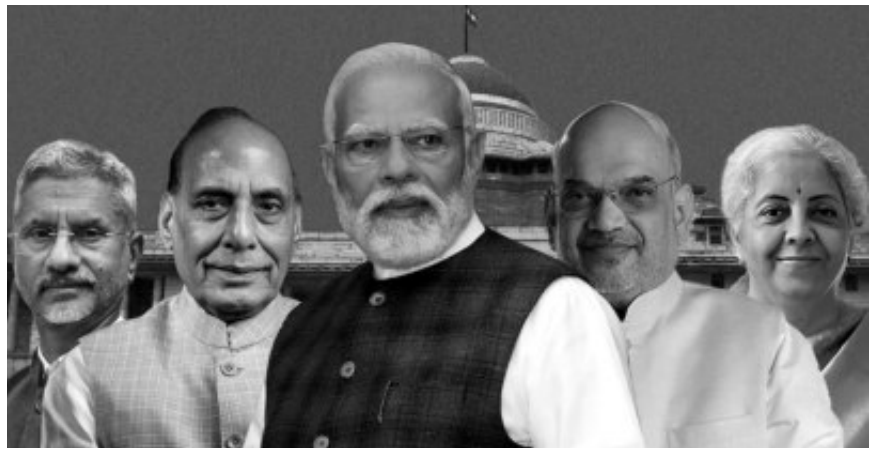

को राजकोषीय बोझ घटाने और किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिल सके इसके लिए निजी इकाइयों को खरीद में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और जलवायु पर आधारित फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में मौजूदा एमएसपी सिस्टम की खामियों के बारे में भी बात की गई। जिसमें बताया गया कि महज खास फसलों पर ध्यान देने, निजी निवेश को दूर रखने और निर्यात प्रतिस्पर्धा के चलते इस पर नकारात्मक असर पड़ता है। वर्तमान में सरकार मुख्य रूप से गेहूं और चावल खरीदती है, जो कुल कृषि उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत है। जबकि इसके ठीक उलट पशुधन, सब्जियां और फल जैसे क्षेत्र से संयुक्त रूप से कृषि उत्पादन का 71 प्रतिशत है, लेकिन इन्हें एमएसपी में पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट में आजीविका क्रेडिट कार्ड शुरू करने और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए एक व्यापक ऋण गारंटी कोष स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है। ये ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने और क्रेडिट फ्लो को मैनेज करने में मदद करेगा। इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इसके बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने और मजबूत मार्केटिंग फ्रेमवर्क को अमल में लाने की बात कही गई है। साथ ही फसलों के स्टोरेज, ग्रेडिंग, छटाई और खुदरा बिक्री जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन उपयों को अपनाने से किसानों की स्थिति में सुधार होगा।

इस बजट में सरकार का फोकस हेल्थकेयर पर हो सकता है। बजट में देश के करीब 17 करोड़ लोगों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना की कवरेज लिमिट डबल करने का ऐलान कर सकती हैं। इससे गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकता है। इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। योजना के तहत अभी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसे दोगुना करने का प्रस्ताव सरकार के पास जा चुका है। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण देश के करीब 17 करोड़ लोगों को कवरेज लिमिट बढ़ाकर बड़ा तोहफा दे सकती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलती है। सरकार का मानना है कि इलाज के बढ़ते खर्चों को देखते हुए इसका कवरेज भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में बजट 2024 में इस कवरेज को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है।

● **विपिन कंधारी**

सरकार में जोश भर सकती है एसबीआई की रिपोर्ट

बजट से पहले देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे केंद्र सरकार में जोश भर सकता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार कई बड़े ऐलान भी बजट सत्र में कर सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पीएसबी) में विनिवेश को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वे अच्छी स्थिति में हैं। रिपोर्ट में मौजूदा सरकारी बैंकों को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तावना टॉपिक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि बैंक अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए सरकार को सरकारी बैंकों के विनिवेश को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के संबंध में कहा गया कि सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बैंक में लगभग 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अक्टूबर, 2022 में खरीदारों से बोलियां आमंत्रित कीं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को जनवरी, 2023 में पेशकश पर आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी के लिए कई रुचि पत्र प्राप्त हुए।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो गर्त में जा रही कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस जीत से राहुल गांधी में गजब का आत्मविश्वास भर गया है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल का अंदाज देखने लायक है। हर मुद्दे पर वह जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वहीं आम जनता से मुलाकात कर उनका दुख-दर्द भी बांट रहे हैं, फिर चाहे वह मणिपुर के पीड़ित हों या हाथरस के। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र और कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं।

राहुल की प्रेशर पॉलिटिक्स

लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बदले-बदले नजर आ रहे हैं। रायबरेली लोकसभा से सांसद चुने जाने के एक महीने में राहुल गांधी दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और उप्र का यह उनका तीसरा दौरा है। रायबरेली में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ बैठक ही नहीं की बल्कि जिले के विकास की हकीकत जानने की कवायद करते नजर आए। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव हैं और एक महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।

कांग्रेस और राहुल गांधी ने उप्र को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की नीति पर काम शुरू कर दिया था। चाहे वह नीट का मसला हो या हाथरस कांड। नीट भले राष्ट्रीय मसला है, लेकिन उप्र को पेपर लीक का केंद्र बताकर कांग्रेस ने यहां अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आंदोलन का रास्ता चुना। पहले कांग्रेस के मुख्य संगठन ने आंदोलन किया। इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। इस बीच हाथरस कांड हुआ तो राहुल गांधी ने लोगों के बीच पहुंचने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके दुख-दर्द बांटने के साथ-साथ सियासी संदेश भी देते नजर आए। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई। इसके फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ितों को दिया गया मुआवजा काफी कम है, जिसे सरकार बढ़ाए और बिना देर लगाए उन्हें समय से दिया जाए। इसके बाद राहुल गांधी अब रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का जायजा लिया और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर उनका हौंसला बढ़ाया। इस तरह राहुल गांधी के एजेंडे में उप्र सबसे प्रमुख रूप से दिख रहा है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है तो उप्र में छह सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उभरने की उम्मीद जगा दी है। कांग्रेस उप्र में साढ़े तीन दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह तक देखना पड़ा था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को अपने पास रखा है ताकि उप्र की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से सियासी संजीवनी मिल सके। राहुल गांधी ने रायबरेली के जरिए उप्र को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

रायबरेली राहुल गांधी की सूची में पहले स्थान पर है। इसका जिक्र वह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर चुके हैं। इसीलिए रायबरेली में खुद को एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी सांसद का चुनाव जीतने के बाद आश्वस्त होने के चलते

विपक्षी को उसके मजबूत गढ़ में उलझाने की रणनीति

भाजपा की सियासत को शीर्ष तक पहुंचाने में जिस राम मंदिर, अयोध्या मुद्दे का बड़ा रोल रहा है। वही अयोध्या जिस फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में है, वह सीट पार्टी हार गई। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के शीर्ष नेता भगवान राम और अयोध्या का जिक्र करने से जहां बच रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे लेकर आक्रामक हैं। विपक्ष को शायद लग रहा है कि पिछले 10 साल से अपने दम पर पूर्ण बहुत के साथ एनडीए सरकार की अगुवाई करती आई भाजपा इस समय उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी 2014 से 2024 के चुनाव तक रही है। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उभार के बाद भाजपा के चुनाव अभियानों में गुजरात और गुजरात मॉडल की बात प्रमुखता से होती रही है। कांग्रेस नेताओं को शायद ये लग रहा है कि पार्टी अगर 2027 के चुनाव में 29 साल लंबे शासन की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में सफल रहती है, भाजपा को हरा देती है तो इसका पूरे देश में अलग संदेश जाएगा।

पांच साल तक नहीं आई हैं। ऐसे में विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि गांधी परिवार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद से क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। राहुल गांधी का एक महीने में रायबरेली का दूसरा दौरा उसी नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश के तौर पर है। राहुल गांधी अब अमेठी जैसी गलती रायबरेली क्षेत्र में नहीं दोहराना चाहते हैं। रायबरेली को वो अपने किसी मैनेजर के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहते हैं बल्कि खुद क्षेत्र का दौरा करके अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला विकास योजना की बैठक में शिरकत की। रायबरेली के बहाने राहुल गांधी उप्र पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सूबे में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और 2024 के नतीजों ने उसे उम्मीद की किरण जगा दी है। राहुल गांधी में यह बड़ा बदलाव आया है। अभी तक वह सिर्फ विकास की बात करते थे, अपने पूर्वजों का अमेठी-रायबरेली के साथ नाते और किए गए कार्यों को बढ़ाने की बात करते रहे हैं। अब वे रायबरेली के साथ अपनापन जताने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव के दौरान और उसके बाद भी इसी पैटर्न पर रायबरेली में नजर आए हैं। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली को परमानेंट सीट बनाए रखना चाहते हैं।

कांग्रेस उप्र में 6 लोकसभा सीटें इस बार जीती है और 5 सीटों पर उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा है। 2024 के चुनाव नतीजे से कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। ऐसे में उप्र के लिए कोशिशों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की राह चुनी है। इसका अक्स लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हाथरस यात्रा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में देखा जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी रायबरेली भी पहुंचे। ऐसे में उप्र को लेकर उनकी सक्रियता एक तरह से भाजपा और उप्र सरकार पर दबाव का काम करेगी। कांग्रेस उप्र में 1989 के बाद से सत्ता का वनवास झेल रही है। साल 2014 में दो जबकि 2019 में केवल एक लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इस बार के चुनाव में महज 17 सीटों पर लड़ने के बाद कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली है। इन छह सीटों में अमेठी, रायबरेली के साथ इलाहाबाद और सहारनपुर की सीट भी है, जहां कांग्रेस 40 साल के बाद जीती है। सपा के साथ गठबंधन और फिर मुस्लिम और दलित वोटरों का कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखाई दिया है, उसके चलते ही कांग्रेस अपने लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा अवसर तलाश रही है। ऐसे में राहुल उप्र में अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए रायबरेली को सियासी हथियार बनाने का दांव चल रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का फोकस गुजरात पर है। राहुल संसद के भीतर और संसद के बाहर लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हम गुजरात में भाजपा को हराएंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी मेडेन स्पीच में राहुल ने कहा कि हम इस बार भाजपा को गुजरात में भी हराने जा रहे हैं। संसद सत्र की समाप्ति के बाद राहुल गुजरात दौरे पर पहुंचे और वहां भी अपनी यही बात दोहराई। राहुल गांधी के इस दावे पर भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है। चिराग ने कहा है कि आगामी चुनाव के परिणाम दिखा देंगे कि एनडीए कितना मजबूत है। इसके बाद उनका घमंड भी टूट जाएगा। राहुल के बयान, चिराग की प्रतिक्रिया के बाद बात गुजरात के चुनावी अतीत और लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी हो रही है। गुजरात में हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज एक सीट जीत सकी। विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो पार्टी को 20 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। ऐसे में अब चर्चा इसे लेकर हो रही है कि क्या राहुल गांधी का ये दावा प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के नारे जैसी ट्रिक है या वाकई इस दावे में दम भी है?

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने अबकी बार, 400 पार का नारा दिया था। चुनाव नतीजों में भाजपा 240 और एनडीए 293 सीटें ही जीत सका। एनडीए की सीटों का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली लेकिन 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुनाव मैदान में उतरी भाजपा दो चुनाव बाद 272 के जादुई आंकड़े से पहले रुक गई। चुनाव नतीजों के बाद संसद के पहले सत्र में ही राहुल गांधी ने गुजरात में भाजपा को हराने के दावे का दांव चल दिया।

राहुल गांधी का ये दांव प्रधानमंत्री मोदी की 400 पार वाली ट्रिक जैसी ही कही जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बहस प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के इस नारे के इर्द-गिर्द ही होती रही। लोकसभा चुनाव के दौरान विमर्श का केंद्र यही रहा कि क्या भाजपा 400 से अधिक सीटें जीत पाएगी या नहीं और क्या कांग्रेस 100 के आंकड़े तक भी पहुंच पाएगी या नहीं। अब राहुल गांधी ने गुजरात में जीत का दावा किया है तो इसके पीछे अभी से ही गुजरात चुनाव के लिए विमर्श के केंद्र में इस बात को लाना हो सकता है कि क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी 1998 से ही सूबे की सत्ता पर काबिज भाजपा को हराकर सरकार बना पाएगी?

● इन्द्र कुमार

अब पश्चिम बंगाल पर फोकस बढ़ाएगी कांग्रेस

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। पार्टी का मानना है कि बंगाल में टीएमसी से लड़ने के बजाय पहले भाजपा से लड़ना जरूरी है। इसके लिए पार्टी जल्द ही पश्चिम बंगाल के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद जून में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल में पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर अपने नेताओं से चर्चा भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं से नए अध्यक्ष के नाम और भविष्य में राज्य में कांग्रेस की राह को लेकर कई दौर की चर्चा की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी अब बिना देर किए बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला ले सकती है।

क्या अजित का साथ छोड़ेंगे भुजबल?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल ने गत दिनों शरद पवार से मुलाकात की, भुजबल और पवार की इस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाईं जा रही हैं। मुंबई में शरद पवार के आवास सिल्वर ओक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई लेकिन अचानक हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या छगन भुजबल एक बार फिर पाला बदलेंगे? क्या भुजबल इस बार अजित पवार की एनसीपी को छोड़कर शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन करेंगे? सूत्रों की मानें तो इसकी संभावना बेहद कम है। सूत्रों का कहना है कि छगन भुजबल एनसीपी अजित गुट में ही बने रहेंगे। गत दिनों एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने शरद पवार पर मराठा आरक्षण को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया था। भुजबल ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है उसके पीछे शरद पवार हैं। छगन भुजबल और शरद पवार की इस मुलाकात का समय पहले से तय नहीं था, अचानक शरद पवार के घर पहुंचे छगन भुजबल को उनसे मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं शरद पवार के आवास से निकलकर भुजबल ने मीडिया से कोई बात नहीं की।

छगन भुजबल ने बताया है कि शरद पवार के साथ उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत की है। भुजबल ने कहा कि शरद पवार राज्य के बड़े नेता हैं। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे इस पर चर्चा हुई है। भुजबल ने कहा है कि शरद पवार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हामी भरी है। भुजबल ने कहा कि मुझे मंत्री पद, विधायकी की कोई जरूरत नहीं है, बस राज्य में शांति बनी रहनी चाहिए, इसीलिए मैं उनसे मिला हूं। भुजबल ने शरद पवार से आरक्षण के मुद्दे पर सत्तापक्ष का साथ देने की अपील की है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करने का भरोसा जताया है। एनसीपी अजित गुट का कहना है कि एमएलए चुनाव में छगन भुजबल ने अजित पवार का ही साथ दिया था, ऐसे में भुजबल पार्टी छोड़ शरद पवार का दामन थामेंगे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। हालांकि छगन भुजबल की गिनती कभी शरद पवार के करीबियों में होती थी। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी दो धड़ों में बंट गई और भुजबल भी बागियों के खेमे में शामिल हो गए। भुजबल का नाम एनसीपी के उन नेताओं में भी था जिन्होंने अजित पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी।

दरअसल बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि छगन भुजबल अजित पवार से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि भुजबल नासिक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन लंबे समय तक जब उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए भी भुजबल खुद को दावेदार मान रहे थे लेकिन पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को इस सीट से नामांकन कराकर छगन भुजबल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा महायुति सरकार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठा नेता मनोज जरांगे एक बार फिर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं। उनकी मांग है कि मराठा आरक्षण के तहत सभी कुनबियों (कृषकों) को ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन इसे लेकर ओबीसी वर्ग के नेता विरोध जता रहे हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद से उनकी छवि को धक्का लग सकता है और चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

छगन भुजबल ने एक दिन पहले शरद पवार पर जमकर निशाना साधा था। बारामती में उन्होंने शरद पवार पर मराठा आरक्षण को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया था लेकिन 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि भुजबल इस मामले में सहयोग की अपील करते हुए शरद पवार के घर जा पहुंचे, वो भी बिना अप्वाइमेंट लिए। अगर शरद पवार से भुजबल की मुलाकात की वजह मराठा आरक्षण का मुद्दा ही था तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भुजबल मुलाकात के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे?

इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में जाहिर है इस मुलाकात के तरह-तरह के मायने निकाले जाएंगे। लेकिन अब से करीब एक साल पहले शरद पवार को धोखा देकर अजित गुट में शामिल होने वाले छगल भुजबल को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी की वो मुलाकात का समय लिए बगैर ही शरद पवार के आवास जा पहुंचे। दरअसल जितनी चर्चा इस मुलाकात के एजेंडे को लेकर हो रही है उतनी ही चर्चा इस बात की हो रही है कि शरद पवार ने छगन भुजबल को करीब डेढ़ घंटे का इंतजार क्यों कराया? हालांकि छगन भुजबल ने अपने बयान में कहा है कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं थी और जिस वक्त वो सिल्वर ओक (शरद पवार के आवास पर) पहुंचे तो पवार सो रहे थे। लेकिन राजनीति में इन बातों को इतनी आसानी से पचाना बहुत मुश्किल होता है।

● **बिन्दु माथुर**

विधानसभा की मौजूदा स्थिति

288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे ज्यादा 103 सीटें भाजपा के पास हैं। दो अलग-अलग खेमों में बटी एनसीपी में अजित गुट के पास 40 तो शरद गुट के पास 12 विधायक हैं। शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 38 तो वहीं कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के विधानसभा में 18 विधायक हैं। बाकी की सीटों पर अन्य व छोटे दलों का कब्जा है। ऐसे में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये मुलाकात बेहत अहम मानी जा रही है। शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात को लेकर बेटी सुप्रिया सुले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर हैरानी जताई। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं अभी पुणे में हूं और मुझे इस मुलाकात की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कौन शामिल होगा यह किसी का निजी फैसला नहीं होगा। पार्टी के सभी लोग साथ बैठकर किसी को वापस पार्टी में लेने पर फैसला करेंगे।

भजनलाल के खिलाफ बगावत!

राजस्थान में छह महीने की भजनलाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और मीणा जाति के कद्दावर नेता डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली के खिलाफ बगावत भी कहा जा रहा है। हालांकि बाबा किरोड़ीलाल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किया है लेकिन बाबा के नजदीकी सूत्रों ने कहा है कि अब चाहे जितनी भी मान मनौव्वल की कोशिश हो मीणा मानने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों वह दो दिन दिल्ली में थे। लेकिन पता चला है कि महामंत्री स्तर के नेता भी मुलाकात का समय नहीं दे पाए। इससे भी वह खिन्न थे। तो दिल्ली में बात बनी नहीं और जयपुर आते ही बाबा ने खुद ही एक टीवी चैनल से कह दिया कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा वह भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक में शरीक नहीं हुए।

बड़ा सवाल उठता है कि जब पहले ही इस्तीफा दे दिया गया था तो विधानसभा सत्र के चलते इसे मीडिया के सामने खुद ही क्यों लाया गया। अगर इस्तीफे के पीछे भजनलाल से नाराजगी नहीं है तो विधानसभा सत्र के बीच में इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री के लिए सियासी सिरदर्द क्यों पैदा किया गया। कांग्रेस वैसे ही राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो रही है। लगातार दो बार सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 11 सीटें हारी है और कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। सवाल उठता है कि जब पांच सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव अगले दो तीन महीनों में होने की संभावना है तो बाबा का इस्तीफा क्या भाजपा आलाकमान को मुश्किल में डालने वाला नहीं है? भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि डॉ. मीणा घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं हैं। अब जब मंत्री पद का प्रोटोकॉल भी नहीं है तो धरना-प्रदर्शन करने के लिए आजाद हैं, जैसा कि वह अशोक गहलोत सरकार के समय किया करते थे। जयपुर में पुराने सरकारी मकान तोड़कर बहुमंजिला मकान बनाने से जुड़े एक मामले में डेढ़ हजार करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए वह अपने ही मुख्यमंत्री से जांच की मांग कर चुके हैं। इसी तरह एक-दो अन्य योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत वह प्रधानमंत्री मोदी से भी कर चुके हैं।

किरोड़ीलाल मीणा के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि वह दौसा लोकसभा सीट में उम्मीदवार के चयन से लेकर कार्यकर्ताओं की खिन्नता से दुखी थे। इसके अलावा उन्हें कम महत्व का मंत्रालय मिलने का भी मलाल था। खासतौर से यह देखते हुए उनसे जूनियर विधायकों को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तक बनाया गया और कुछ अन्य जूनियर विधायकों को ज्यादा बड़े मंत्रालय दिए गए। गौरतलब है कि जब उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया था तब भी उन्होंने तंज कसा था कि 20 साल पहले पहली बार मंत्री बनने पर भी कृषि और 20 साल बाद भी वही कृषि मंत्रालय। इस पर तुर्रा यह कि उनके मंत्रालय से कृषि विपणन विभाग और पंचायती राज विभाग को काट दिया गया यानी वरिष्ठ मीणा नेता के सियासी पर कतरे गए। कहा जाता है कि हाल ही में उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़े कुछ इंजीनियरों का तबादला कर दिया था लेकिन विभाग के सचिव स्तर के एक अधिकारी ने नया पदभार ग्रहण करने पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के दौरान मीणा ने मोदी से पूर्वी राजस्थान और मीणा बहुल कुल 7 सीटों पर जीत का वादा किया था और एक भी सीट हारने पर इस्तीफा देने की बात कही थी। दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली-धौलपुर यानी चार सीटें भाजपा हार गई। कोटा, जयपुर ग्रामीण और भीलवाड़ा सीट ही भाजपा जीत सकी। हैरानी की बात है कि नतीजों के बाद खुद ही मीणा ने मोदी से हुए वायदे का खुलासा भी किया और इस्तीफा देने की बात भी कही थी। पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। तब कहा गया कि दौसा से वह अपने भाई जगमोहन मीणा का टिकट चाहते थे लेकिन आलाकमान नहीं माना। दौसा से भाजपा उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा के लिए वोट मांगने वह निकले तो उनके मीणा समर्थक नहीं माने। नतीजतन सवा दो लाख के भारी अंतर से भाजपा दौसा में हार गई। यही हाल टोंक सवाई माधोपुर सीट का रहा, जहां से कांग्रेस के हरीश मीणा चुनाव जीते, जबकि यहीं से किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा का चुनाव जीते थे। हैरानी की बात है कि डॉ. मीणा पर वादा नहीं निभाने पर इस्तीफा देने के लिए किसी भाजपा नेता ने नहीं कहा। न ही आलाकमान ने ही ऐसे कोई संकेत दिए। न ही मोदी ने भी किसी तरह की नाराजगी जाहिर की। लेकिन फिर भी मीणा प्राण जाई पर वचन न जाई की चौपाई गुनगुनाते रहे। इस्तीफे की खबर सार्वजनिक करने के बाद भी ऐसा ही ट्वीट किया गया और उसके बाद मीणा शंकराचार्य के चरणों में बैठे दिखाई दिए। चेहरे पर परम संतोष के भाव थे मानो बोझ उतर गया हो, लेकिन उनके इस्तीफे से भजनलाल सरकार का बोझ बढ़ गया है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

मीणा का राजनीति में बड़ा कद

किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं और मीणा समुदाय का चेहरा हैं। सूबे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा के बाद किरोड़ीलाल मीणा सबसे पावरफुल मंत्री थे। तीन बार के सांसद और छठी बार विधायक मीणा का अपना सियासी कद है, जिन्हें राजस्थान सरकार में चार मंत्री पद दिए गए थे। इससे ही उनके सियासी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है और गहलोत सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा मोर्चा खोलने वाले भाजपा नेताओं में उनका नाम आता है। किरोड़ीलाल मीणा के सियासी तेवर के चलते ही उन्हें विद्रोही नेता कहा जाता रहा है। भजनलाल सरकार बने अभी छह महीने ही हुए हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के अपने ही कई नेताओं के साथ सियासी टकराव हो चुके हैं। मीणा लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और अब नतीजे के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने विद्रोही रुख से भी अवगत करा दिया है। अगर उनकी भजनलाल से नाराजगी नहीं है तो विधानसभा सत्र के बीच में इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री के लिए टेंशन क्यों खड़ी कर दी है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद से कांग्रेस वैसे ही भजनलाल सरकार पर हमलावर थी और अब मीणा के इस्तीफे से उसे मौका मिल गया है।

अपनों के निशाने पर सीएम योगी

लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली उप्र में हार के बाद से राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लग रहा है कि प्रदेश में अभी भी चुनावी माहौल है। आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी लगातार चल रहे हैं। एक तरफ एनडीए के साथी दल अपना दल और निषाद पार्टी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों पर एसटी-एससी और ओबीसी की भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर रिजेक्ट किया जा रहा है और नौकरी नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही यह भी आरोप है कि आरक्षित सीटों को अनारक्षित करके वहां नौकरी दी जा रही हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि कई साल बाद अचानक इन सहयोगी दलों का जमीर जाग गया है या जानबूझकर किसी रणनीति के तहत सवाल उठाएं जा रहे हैं। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी अचानक उनकी तारीफ करनी शुरू कर दिए हैं। उप्र में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने योगी की तारीफ में जो बातें की हैं उससे जनता में कई तरह के संदेश जा रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ये बात फैलाने की कोशिश की गई थी कि शायद बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद लेकर उन्हें केंद्र में स्थापित किया जाएगा। विशेषकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर बयान भी दिया था कि अगर भाजपा बड़े अंतर से जीतती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छुट्टी तय है। हालांकि चुनाव परिणाम इतने खराब हो गए कि सत्तापक्ष हो या विपक्ष किसी को भी उप्र में भाजपा के इस दुर्गति का अंदाजा नहीं था। चुनाव परिणामों के बाद योगी सरकार की तारीफ करने वाले 2 ऐसे शख्स सामने आए जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कभी सोचा नहीं होगा कि इन लोगों के मुंह से कभी उनको तारीफ सुनने को मिलेगी। जी हां, पहला नाम है गाजीपुर से नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी का और दूसरा नाम है सहारनपुर के नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद का। दोनों नेता इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे महत्वपूर्ण दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद हैं।

पहले चर्चा करते हैं गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की। ये पूरा देश जानता है कि अफजाल अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अंसारी परिवार की तमाम प्रॉपर्टीज और बिजनेस को नेस्तनाबूद करने में मुख्यमंत्री योगी का हाथ रहा है। अंसारी परिवार के साम्राज्य को जिस नेता ने तहस-नहस कर दिया उस नेता की तारीफ अंसारी परिवार अगर कर रहा है तो मामला रहस्यमय तो लगेगा ही। इसी तरह से सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़े। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद अफजाल ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रचार नहीं करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही भाजपा उप्र में 33 सीटें जीत पाई। उन्होंने कहा था कि अगर योगी प्रचार नहीं करते तो भाजपा तीन सीटें ही जीत पाती। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा खत्म हो चुका है। यही कारण है कि भाजपा वाराणसी के आसपास की सभी सीटें हार गई जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ-साथ पड़ोस की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे। सहारनपुर लोकसभा से पहली बार सांसद चुने गए इमरान मसूद ने सूबे की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सहारनपुर में बहुत-बहुत दिन तक लाइट नहीं आती थी। गर्मियों में हर साल ऐसा ही हाल रहता था, लेकिन इस बार इतनी भीषण गर्मी में भी उप्र में बिजली सही तरीके से आई है और बिजली विभाग के कर्मियों ने लगातार काम किया है। इस वजह से सूबे में बहुत ही बेहतर तरीके से बिजली आ रही है।

अब सवाल उठता है कि योगी की तारीफ ये विरोधी दलों के सांसद क्यों कर रहे हैं? इसके लिए तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं इमरान मसूद को क्षेत्र के राजपूत वोटर्स ने वोट दिया था इसलिए वो योगी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि इमरान मसूद और अफजाल अंसारी के खिलाफ तमाम केस हैं जिनके चलते वो योगी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। पर यह विषय का साधारणीकरण है। योगी का सपोर्ट करके ये अपने धुर समर्थकों का अपमान भी तो कर रहे हैं। जिस योगी ने इमरान मसूद को अजहर मसूद का दामाद बताया था या जिस योगी ने अंसारी परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया उसको सपोर्ट करने की बात इतनी सी नहीं हो सकती है। जाहिर है ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को कमजोर करने की साजिश का नाम हो सकता है। विपक्ष जानता है कि जब तक यह जोड़ी आबाद रहेगी उप्र में भाजपा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

सहयोगी दलों ने टारगेट पर लिया

अब सवाल उठता है कि अचानक सहयोगी दलों को क्यों उप्र में मिर्ची लगने लगी है। एनडीए सरकार में पिछले 10 सालों से शामिल अपना दल (एस) की चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को अब लगता है कि उप्र में आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इसके तुरंत बाद एनडीए में ही शामिल निषाद पार्टी के चीफ और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने भी योगी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया कि एसटी-एससी और ओबीसी नियुक्तियों में साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी की जा रही है। उनका आरोप था कि आरक्षित सीटों पर एसटी-एससी और ओबीसी की भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर रिजेक्ट किया जा रहा है और नौकरी नहीं दी जा रही है। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने ये भी आरोप लगाया कि आरक्षित सीटों को इसके बाद अनारक्षित किया जा रहा है और वहां नौकरी दी जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

भ्रष्टाचार के पुल

बरसात आने से पहले ही बिहार में पुलों का गिरना सार्वजनिक निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकेदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते साल जून में भागलपुर में गंगा नदी पर करीब पौने दो हजार करोड़ की लागत से बन रहे पुल के गिरने पर भारी शोर मचा था। लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। पुलों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी है, जो बताता है कि नियम-कानून ताक पर रखकर बेखौफ घटिया सामग्री वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य जारी हैं। जाहिर है ऊपर से नीचे तक की कमीशनखोरी और जनता की कीमत पर मोटा मुनाफा कमाने वाले ठेकेदारों की मनमानी जारी है। तभी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग बेखौफ किया जा रहा है। यदि शासन-प्रशासन का भय होता तो पुल यूं धड़ाधड़ न गिर रहे होते।

सवाल ये उठता है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम देश की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाला तंत्र क्यों विकसित नहीं कर पाए? यह जरूरी है कि सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता का हो और उसका निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। इन योजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाए, जिससे कई पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही वह दुर्घटनामुक्त और जनता की सुविधा बढ़ाने वाला हो। मगर विडंबना देखिए कि बिहार के पुल उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो रहे हैं। स्पष्ट है कि मोटे मुनाफे के लिए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरा निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों का काम निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करना होता है, वे आंखें मूंदे बैठे हैं। जो समाज में मूल्यों के पराभव व आपराधिक तत्वों की निर्माण कार्यों में गहरी दखल को ही दर्शाता है। यही वजह है कि भारी यातायात के दबाव वाले दौर में पुल अपना ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं। यूं तो कभी किसी हादसे की वजह से भी पुल गिर सकते हैं, मगर निरंतर कई पुलों का कुछ ही दिनों में गिरना साफ बताता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसमें भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका है। दरअसल, सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता की यदि समय-समय पर जांच होती रहे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता था। इन हादसों की वजह यह भी है कि राजनेताओं व दबंगों के गठजोड़ से ऐसे लोगों को ठेके मिल जाते हैं, जिनको न तो बड़े निर्माण कार्यों का अनुभव होता है और न ही गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता होती है। निस्संदेह, यह नागरिकों के जीवन से जुड़ा गंभीर मसला है। इसलिए सरकार और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि निर्माण कार्य यूं ही ध्वस्त होते रहे तो इससे सरकारी निर्माण कार्य की लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। सरकारी राजस्व का भी नुकसान होगा। वक्त की मांग है कि सार्वजनिक निर्माण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं।

बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला जारी है। पिछले दो हफ्ते में राज्य के 10 पुल टूट चुके हैं। भारत के बिहार राज्य में पुल टूटने की ताजातरीन घटना सारण जिले में हुई। यहां गंडकी नदी पर बना एक डेढ़ दशक पुराना पुल गिर गया। पिछले 24 घंटे के दौरान सारण में पुल गिरने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 3 जुलाई को सिवान जिले में तीन पुल टूट गए थे। इसी दिन सारण जिले में भी दो और छोटे-छोटे पुल टूटे। ये सभी गंडक नदी की शाखा पर बने थे। बताया जा रहा है कि ये पांचों पुल पानी का तेज बहाव नहीं झेल पाए और ध्वस्त हो गए। इनमें एक ब्रिटिशकाल में बनाया गया पुल था, जिस पर अभी तक आवागमन हो रहा था। पुलों के टूटने की घटना अररिया, पूर्वी चंपारण, सिवान, मधुबनी व किशनगंज जिले में भी हुईं। सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि इनमें तीन निर्माणाधीन थे। इन घटनाओं को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलों के रखरखाव से जुड़ी नीति बनाने का निर्देश दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हुई है, जिसमें कहा गया कि लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण पूरे प्रदेश में पुलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है, खासतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में।

पिछली ऐसी कई घटनाओं की तरह इस बार भी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, आनन-फानन प्रारंभिक कार्रवाई भी हुई और पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इन घटनाओं की वजह क्या है, इस पर सब की अपनी-अपनी परिभाषा है। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ही तरफ के लोग सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। पुराने पुल-पुलिया टूटने पर उनके रखरखाव पर सवालिया निशान लगता है। निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2022 में बेगूसराय जिले में गंडक नदी पर 13.5 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल औपचारिक उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया था।

● **विनोद बक्सरी**

बार-बार डिजाइन पर दोष क्यों

विदित हो कि दिल्ली और हैदराबाद से आई तकनीकी टीम ने जब अररिया में बकरा नदी के ध्वस्त पुल की जांच की, तो पता चला कि खंभे की पाइलिंग 40 मीटर नीचे से की जानी थी, जो महज 20 मीटर नीचे ही की गई थी। 182 मीटर लंबा यह पुल बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 7.79 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार कहते हैं, इस पुल के बारे में अब कहा जा रहा कि इसके डिजाइन में ही दोष था, निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया और बकरा नदी के धारा बदलने के स्वभाव का ध्यान नहीं रखा गया। अगर सच में ऐसा था, तो निर्माण की स्वीकृति क्यों दी गई। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि अगर डिजाइन से जुड़ी दिक्कतें थीं, तो पुल निर्माण से पहले ही धारा में बदलाव को रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग कर नदी को क्यों नहीं बांधा गया। क्या यह देखना भी निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है या विभागीय इंजीनियरों को इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक निर्माण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इससे पहले भी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा ढहने में यह बात कही गई कि डिजाइन में दोष था।

क्या बदलेगी ईरान की सियासत?

ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में बड़ा उलफेटर हुआ है और सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान देश के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं जिन्होंने कट्टरपंथी सईद जलीली को शिकस्त दी है। उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को हिजाब विरोधी माना जाता है। पेजेश्कियान पश्चिम के साथ बेहतर संबंधों, परमाणु समझौते की वापसी और हिजाब कानून में सुधार की वकालत करते हैं। ईरान में 28 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इतिहास में सबसे कम मतदान हुआ था, जिसके बाद पेजेश्कियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली के 13.5 मिलियन वोटों के मुकाबले 16.3 मिलियन वोट हासिल कर दूसरे चरण के चुनाव में जीत हासिल की। अब पेजेशकियन को वर्षों से चली आ रही आर्थिक पीड़ा और खूनी दमन से नाराज जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अपने वादे के मुताबिक बदलाव ला सकते हैं।

2022 में जब महसा अमिनी की मौत हुई थी, ईरानी सांसद मसूद पेजेश्कियान ने लिखा कि इस्लामिक गणराज्य में किसी लड़की को उसके हिजाब के लिए गिरफ्तार करना और फिर उसके शव को उसके परिवार को सौंपना अस्वीकार्य है। कुछ दिनों बाद, जब देशभर में विरोध प्रदर्शन और सभी असहमति पर जानलेवा एक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग सुप्रीम लीडर का अपमान कर रहे हैं, वे समाज में लंबे समय तक चलने वाले क्रोध और घृणा के अलावा कुछ नहीं पैदा करेंगे। पेजेश्कियान का जन्म 29 सितंबर, 1954 को उत्तर-पश्चिमी ईरान के महाबाद में एक अजेरी पिता और एक कुर्दिश मां के घर हुआ था। वह अजेरी भाषा बोलते हैं और लंबे समय से ईरान के विशाल अल्पसंख्यक जातीय समूहों के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। उन्होंने ईरान-इराक युद्ध के दौरान युद्धक्षेत्र में भी कार्य किया और युद्ध के मैदान में चिकित्सा दल भेजे। वे एक हार्ट सर्जन हैं जिन्होंने तबरीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। 1994 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी, फतेमेह मजीदी और एक बेटी की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपने बचे हुए दो बेटों और एक बेटी का अकेले ही पालन-पोषण किया।

राजनीति में आने के बाद सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के शासनकाल के दौरान वह देश के उप स्वास्थ्य मंत्री बने। साल 2009 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो देश में हिंसा भड़क गई और कई लोगों की जान भी गई। इस दौरान पेजेश्कियान ने प्रदर्शनकारियों के साथ हो रहे बर्ताव की कड़ी आलोचना की जिसकी वजह से वह कट्टरपंथी नेताओं की आलोचना का भी शिकार बने। 2011 में, पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दर्ज किया था लेकिन बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। पेजेश्कियान ने 2021 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए भी पर्चा भरा था लेकिन उनकी उम्मीदवारी को गार्डियन काउंसिल के द्वारा खारिज कर दिया गया था। पेजेश्कियान ही वो नेता थे जिन्होंने ईरान में महिलाओं के लिए कड़े ड्रेस कोड लागू करने वाली मोरैलिटी पुलिस की कार्रवाई को अनैतिक बताया था। तब पेजेश्कियान ने कहा था, अगर किसी खास तरीके से या कोई कपड़ा पहनना अपराध है तो महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसे बर्ताव करना 100 गुना अधिक बड़ा अपराध है। धर्म में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि किसी को उसके कपड़े के लिए सजा दी जाए। जलीली के साथ अपनी अंतिम टेलीविजन बहस के दौरान पेजेश्कियान ने कहा, मेरे और उनके बीच सभी शोरगुल वाली बहसों के बावजूद, केवल 40 प्रतिशत (पात्र मतदाताओं में से) ने ही मतदान किया। 60 प्रतिशत लोग हमें स्वीकार नहीं करते क्योंकि लोगों को हमसे परेशानी है।

ईरान की दोहरी शासन व्यवस्था, जिसमें धर्म और गणतंत्र दोनों का शासन शामिल है, के तहत ईरान के राष्ट्रपति परमाणु कार्यक्रम या मध्य पूर्व में मिलिशिया समूहों के समर्थन पर कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं कर सकते हैं। सरकार से जुड़े सभी शीर्ष मामलों में देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ही फैसले लेते हैं। हालांकि, ईरान के राष्ट्रपति नीति की कठोरता या फिर इसके लागू होने के तौर-तरीकों को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (85 वर्षीय) के उत्तराधिकारी के चयन में शामिल होंगे और उनकी भूमिका काफी अहम होगी। अयातुल्ला खामेनेई देश के सभी मामलों में आखिरी मध्यस्थ कहे जाते हैं। ऐसे में पेजेश्कियान के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जहां सुप्रीम लीडर की फॉरेन पॉलिसी अमेरिकी नेतृत्व के खिलाफ रही हैं। नए राष्ट्रपति के लिए इजरायल-हमास जंग, मिडिल ईस्ट के तनाव और लेबनान से लेकर यमन तक में उसके हिज्बुल्ला-हूती जैसे मिलिशिया समूहों के सामने टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ईरान चुनाव के रनऑफ में पेजेश्कियान और जलीली के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

सुधारवादी नेता की रही पहचान

ईरान के 69 वर्षीय नेता पेजेश्कियान ईरान के शिया धर्मतंत्र के भीतर एक सुधारवादी राजनेता होने के द्वंद्व को उजागर करते हैं जो हमेशा बदलाव के लिए जोर देते हैं लेकिन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई द्वारा देखरेख की जाने वाली व्यवस्था को कभी भी मौलिक रूप से चुनौती नहीं देते हैं। वह खुद को रूहानी और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी जैसे सुधारवादी लोगों और 2009 के ग्रीन मूवमेंट विरोध का नेतृत्व करने वालों के साथ जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। पेजेश्कियान ने गत दिनों एक टेलीविजन बहस के दौरान कहा, हमारा चाल-चलन, लड़कियों के साथ हमारे व्यवहार और इंटरनेट पर सेंसरशिप के कारण हम समाज में अपना समर्थन खो रहे हैं। हमारे व्यवहार के कारण लोग हमसे असंतुष्ट हैं। पेजेश्कियान ने दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जगह लेने के अपने अभियान के दौरान खुद को अन्य उदारवादी और सुधारवादी हस्तियों के साथ जोड़ लिया है। उनके मुख्य समर्थक पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ रहे हैं, जिन्होंने वैश्विक शक्तियों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते पर सहमति जताई थी, जिसके बदले में परमाणु कार्यक्रम में भारी कटौती की गई थी।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

ब्रिटेन के आम चुनाव में भारत का प्रभाव...

ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 650 सदस्यीय संसद में 403 सीटें जीतीं और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई वाली कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल के शासन को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन की जनसंख्या 6 करोड़ 70 लाख है, जिसमें 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक शामिल हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश-हिंदू समुदाय, ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह, अपनी राजनीतिक आवाज को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से उठा रहा है और यहां तक कि उसने एक हिंदू घोषणापत्र भी जारी कर अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे थे।

निवर्तमान ब्रिटेन की संसद में, 15 भारतीय मूल के सांसद थे- लेबर से 8 और कंजर्वेटिव पार्टी से 7 जो 65 गैर-श्वेत सांसदों में शामिल थे, यानि 10 प्रतिशत जो ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास में जातीय रूप से उसे सबसे विविध सदन बनाता था। लगभग तीन प्रतिशत की आबादी वाली पर आर्थिक रूप से संपन्न ब्रिटिश हिंदू समाज को लुभाने के लिए ब्रिटेन के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने अधिकतम संख्या में भारतीय मूल के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इस दौड़ में 107 ब्रिटिश-भारतीय शामिल थे। अब प्रमुख विजेताओं में ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सुएला ब्रेवरमैन, शिवानी राजा, गगन मोहिंद्राबब और प्रीति पटेल शामिल हैं।

लेबर पार्टी के कुछ सदस्य जिन्हें लेबर सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, वे हैं लिसा नंदी, जिनका संबंध बंगाल से है, नवेंदु मिश्रा, गोरखपुर के मूल निवासी, कनिष्क नारायण, प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह ढेसी जो ब्रिटिश संसद के पहले पगड़ीधारी सिख सांसद होंगे। राजनीतिक प्रबंधकों को ब्रिटिश हिंदू मतदाताओं के मतदान के रूझान का पता लगाने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इस चुनाव में उन्होंने लेबर पार्टी का साथ दिया है। इंग्लैंड का चुनाव मुख्यत: दो मुख्य मुद्दों पर लड़ा गया था, 2016 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था जिसका दुष्प्रभाव रोजगार, मुद्रास्फीति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पर पड़ा और दूसरा, कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल जिसने अपने पांच प्रधानमंत्रियों को बहुत ही काम समय में बदल दिया।

ब्रिटेन की लेबर पार्टी के साथ भारत की स्वतंत्रता भी जुड़ी हुई है। 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर, लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के वादे के साथ विंस्टन चर्चिल को करारी हार देकर चुनाव जीता और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को उसी वर्ष रिहा भी कर दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई और स्वतंत्र भारत की रूपरेखा पर विचार भी होने लगा। विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। वह एक रूढ़िवादी राजनेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रबल विरोधी थे। जुलाई 1945 में, ब्रिटेन के नए चुने गए लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति दे स्वतंत्रता की मुहर लगाई थी। वे 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1945 से 1951 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हाल के वर्षों में ब्रिटिश भारतीयों के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, खासकर लेबर पार्टी के साथ उनके संबंधों में। उनके पिछले नेता जेरेमी कॉर्बिन के कार्यकाल के दौरान, लेबर पार्टी ने भारतीय समुदाय से समर्थन में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया, जिसका मुख्य कारण कश्मीर पर कॉर्बिन का विवादास्पद रुख और कथित भारत विरोधी पूर्वाग्रह था। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव दल के लिए चुनाव प्रचार में भारत की भाजपा के बढ़ते प्रभाव ने ब्रिटिश भारतीयों के बीच लेबर के पारंपरिक समर्थन आधार को और भी कम कर दिया था। वर्तमान लेबर पार्टी के नेता कीर स्ट्रामर ने भारत पर अपना रुख नरम कर लिया और कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए अपना आव्हान छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भारत विरोधी चरमपंथी विचारों पर लगाम लगा दिया। कीर स्ट्रामर ने पार्टी के घोषणापत्र में भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता शामिल की। यह प्रतिबद्धता प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके इरादे को उजागर करती है, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना है। इसके आलावा कीर स्ट्रामर के नेतृत्व में लेबर पार्टी अपने 10 वादों, अपनी वामपंथी विचारधारा और श्रमिक वर्ग की परंपराओं से दूर चली गई है। वर्तमान इजराइल-हमास संघर्ष पर, उनकी पार्टी ने इजराइल का पक्ष लिया, जो एक बार फिर से उनकी नीतियों से हटकर था।

● **कुमार विनोद**

भारत से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने पर जोर

कीर स्ट्रामर ने पार्टी के घोषणापत्र में भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दो साल से अधिक समय तक मुक्त व्यापार समझौते की बात कही है। प्रस्ताव में चिकित्सा उपकरणों, शराब, कपड़े और कारों जैसे सामानों की श्रृंखला पर आपसी टैरिफ छूट की परिकल्पना की गई है। अब, आशंका है कि लेबर पार्टी की जीत इस वार्ता के समयसीमा को बदल सकती है और काफी कड़ा मोल भाव भी करे। वीजा के मुद्दे पर विशेष रूप से सेवा कर्मचारियों और भारतीय छात्रों के लिए अस्थायी कार्य वीजा एक प्रमुख मुद्दा रहा है, यह भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भी जुड़ा है। भारत को ब्रिटेन में उनकी अत्यधिक विकसित सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश से लाभ होने वाला था, जिस पर अब लेबर पार्टी कड़े रूख से बातचीत करेगी। भारत ने कार्बन टैक्स में ढील देने की मांग की है, जिसे अगर लागू किया जाता है तो एफटभ्ए के लाभों का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इनके अलावा ब्रिटेन में रह रहे भारतीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण, रक्षा में सहयोगिता और संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का दाखिला जैसे मुद्दों पर भी आपसी संबंध और वार्ता शामिल रहेगा। अब जब ऋषि सुनक का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो भारत सरकार को चाहिए ऋषि सुनक को यथोचित सम्मान देकर विदेशों में रह रहे अन्य लोगों को भी इस तरह आकाशीय पद को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

स्नेह-संस्कारों की घुट्टी...

हमें नारीशक्ति का उद्धारक नहीं, वरन् उनका सहायक बनना है। भारतीय महिलाएं भी संसार की अन्य महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएं; उनका वस्तुकरण करने की बजाय उन्हें मनुष्य समझा जाए। बेहतरीन कवयित्री अनामिका ने स्त्रियों को गहराई से समझने की गुजारिश करते हुए लिखा है-

सुनो, हमें अनहद की तरह
और समझो जैसे समझी जाती है
नई-नई सीखी हुई भाषा।

खीझना, उलझना, चीखना-चिल्लाना, दूसरों पर धौंस जमाना, आक्रामकता, आत्मघात की चेष्टा, अपराधीकरण में संलिप्तता; ये सब मानसिक-बौद्धिक अस्वस्थता के सूचक नहीं तो और क्या हैं? रुग्णता के ये कीटाणु इसलिए जीवन में प्रवेश कर पाए क्योंकि बाल्यकाल में स्नेह व संस्कारों की वह घुट्टी दी ही नहीं गई जो अबोध अवस्था की नींव को भावनात्मक स्तर पर परिपक्त एवं सशक्त बना पाती। प्रेम के अभाव में पले बच्चे से संवेदनशील, परमार्थी अथवा सहृदय होने की अपेक्षा रखना अतार्किक है। भावनाओं का सुकोमल पौधा वहीं पुष्पित, पल्लवित एवं संवर्द्धित होता है, जहां उसे नियमित सिंचन सहित अपेक्षित पोषण भी मिले। जड़ों का माटी से लगाव जितना गहरा होगा, भविष्य का वटवृक्ष उतना ही फलेगा।

बचपन की बात चले और ननिहाल का जिक्र न आए, हो ही नहीं सकता। मां की मां के रूप में बरबस ही उभरती है एक ममतामयी छवि, जिसके स्नेह की छांव तले ग्रीष्म की प्रखरता भी शीतल जान पड़ती है। नानी के घर जाएंगे, मोटे हो के आएंगे, साधारण सी प्रतीत होने वाली इस पंक्ति में जहां जीवन की जीवंतता से लेकर अपनेपन के अहसास में पूरे हक से अल्हड़ मौजमस्ती भरे दिन गुजारने की उम्मीदें कायम हैं, वहीं नाती-नातिन के खान-पान को लेकर विशेष रूप से सजग होने का भाव भी बराबर आभासित होता है। लाड़-मनुहार की प्रेमपगी रसधारा में कथा-कहानियों की अमूल्य समझाइश का टॉनिक शामिल करना भी बिल्कुल नहीं भूलतीं नानी। जानती हैं, यही सबक आज के बाल्यकाल को आते कल का विलक्षण व्यक्तित्व बनाएगा।

बचपन को सुदृढ़ आधारशिला प्रदान करने में बड़े-बुजुर्गों का सदैव ही अपरिहार्य योगदान रहा है। इस संदर्भ में हुआ एक शोध दादा-दादी, नाना-नानी का प्यार पाने वाले बच्चे के भावनात्मक स्तर पर अधिक सशक्त होते की पुष्टि करता है। नानी के स्नेह की भूमिका इसमें सर्वोत्तम आंकी गई। शोध के अनुसार, नानी का स्नेहिल सानिध्य जहां बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, वहीं मानसिक रूप से भी उसे परिपक्व एवं सुदृढ़ बनाता है। शोध प्रमाणित करता है, भावनात्मक अथवा व्यावहारिक समस्याओं से जूझ रहे बच्चों को नानी का स्नेह मिले तो वे सहजतापूर्वक इनसे उबर पाते हैं। प्रेम का संबल बचपन के किसी गहरे सदमे से भी जल्द निजात पाने में सहायक बनता है।

साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, दादा-दादी, नाना-नानी के प्यार एवं साथ का बच्चों के सम्पूर्ण विकास में विशेष महत्व है। इस बात से कोई खास अंतर नहीं पड़ता कि दादा-दादी अथवा नाना-नानी में से कौन अधिक बार तथा अधिक समय तक बच्चे से मिलता है। बचपन में नानी-दादी का प्यार पाने वाले बच्चों के अपने साथियों से भी संबंध आत्मीय एवं मैत्रीपूर्ण होते हैं। बातचीत में अधिक सक्रिय रहने के साथ ही वे दूसरों के प्रति फिक्रमंद भी होते हैं। स्वभावत: वे दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं।

आज के यथार्थ का संज्ञान लें तो भागते वक्त के दरम्यान रिश्तों में पनपती दूरियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एकल परिवार व्यवस्था ने गूढ़ रक्त संबंधों को अलग-थलग कर छोड़ा है। सिमटती पारिवारिक इकाई में अति व्यस्त अभिभावकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अपना मनोरंजन तलाशने वाले बच्चे जीवन की उस सरलता-सरसता-सहजता से भला कैसे परिचित होंगे, जो बड़े-बुजुर्गों के सानिध्य से ही मिलनी संभव है? आंकिक प्रतिस्पर्धा ने बच्चों को उस बेलगाम दौड़ में शामिल कर डाला है, जहां उन्हें भौतिकतावाद के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। दादी-नानी की सुनाई कहानियों-पहेलियों पर मंथन करना, उनके दिलचस्प अनुभवों को खुलकर जीना मानो उनके लिए महज समय की बर्बादी है। संक्षेप में, आज का बचपन समाज तथा सामाजिक रिश्ते सिरे से नकारता हुआ कम्प्यूटर, मोबाइल, गैजेट्स आदि को ही सर्वेसर्वा मानने लगा है। बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताना तो दूर की बात, अपेक्षाओं के अंधाधुंध लादे गए बोझ ने तो अभिभावकों तक से उनका संपर्क सीमित कर डाला है। छुट्टियों का अधिकांश अंश गृहकार्य निपटाने में गुजर जाता है। बाकी बचा समय, सुविधाजनक माहौल में पले-बढ़े बच्चे ननिहाल अथवा ददिहाल में बिताने की अपेक्षा हिल स्टेशन पर गुजारना अधिक पसंद करते हैं। आधुनिक परिवेश में कितने प्रतिशत बच्चे पूर्व की भांति वास्तविक अर्थों में खुशहाल बचपन जीते होंगे, गणना संभवत: उंगलियों के पोरों पर हो जाएगी।

● **ज्योत्सना**

सत्ता व न्यायालयों में महिलाओं की भागीदारी

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समय में महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, और न केवल संभाल रही हैं बल्कि कुशल संचालन कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, मायावती को देखा जा सकता है। लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार देखें तो राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। भारतीय संसद में केवल 14 फीसदी महिलाएं हैं, जबकि संसद में महिलाओं की वैश्विक औसत भागीदारी 25 फीसदी से ज्यादा है। इसके अलावा, ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी चुनाव तो महिला जीतती है लेकिन सत्ता से संबंधित सभी निर्णय उसके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं। वहीं, न्यायालय में भी महिलाओं की संख्या संतोषजनक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएं हैं।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

मर्यादा

विदेश से बेटा जब घर पहुंचा, तो उसके साथ उसकी नवविवाहिता पत्नी भी थी। बेटे ने जब पिता बताया कि उसने शादी कर ली है, तो पिता अवाक रह गया। फिर भी बेटे ने पिता से कहा- पापा हमें आशीर्वाद दीजिए। तब उसकी बहन बिखर पड़ी। बेशर्मी की हद है। आप बड़े हैं, पुरुष हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि मां-बाप की मर्यादा को रौंदने का आपको अधिकार मिल गया। अच्छा है चुपचाप चले जाइए, अपनी पत्नी को लेकर। वरना इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि मैं भी किसी को लेकर भाग जाऊंगी। फिर मत कहना कि मैंने घर परिवार की मर्यादा का खून कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। भाई तैश में आ गया। तो बहन ने भी तैश में ही जवाब दिया- क्यों नहीं कर सकती? कौन रोकेगा मुझे, तुम! जिसे अपने बाप की मर्यादा का ख्याल नहीं रहा। तुम इस घर के वारिस हो, लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो। मुझे तो वैसे भी दूसरे के घर जाना है। अगर तुम्हें कुछ भी करने की छूट है, तो मुझे भी इतना अधिकार है। अब फैसला तुम्हें करना है। बेटी का यह रूप देख पिता ने कहा- तू ठीक कह रही है बेटी। तू जो करना चाहे कर लेना। बस मेरी चिता को आग भी तू ही देना। मैं अपने बेटे को उसके सारे अधिकार से मुक्त करता हूं। विवश बेटा अपनी पत्नी के साथ बिना किसी प्रतिरोध के वापस चला गया। शायद उसे मर्यादा का मतलब समझ में आ गया था।

- सुधीर श्रीवास्तव

चेहरे की चमक...

आज शालू अभी तक नहीं आई थी। मैं एक बार दरवाजे की तरफ देखती तो दूसरी बार घड़ी की तरफ, पर वो है कि पहुंच ही नहीं रही है। आज मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग है। बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं, देर से पहुंचा तो बॉस सबके सामने जरूर मेरी इंसल्ट कर देंगे। मेरा मन बार-बार कह रहा था शालू आ भी जा। जैसे-तैसे हांफते शालू आई, बहुत उदास भी लग रही थी। मैं उससे देरी का कारण पूछकर समय खराब नहीं करना चाहती थी।

पर शालू बोली पड़ी दीदी, मैं तो आज आने वाली नहीं थी, मेरी मां की तबियत बहुत खराब है उसको देखने वाला कोई नहीं है, पैसे की जरूरत थी इसलिए आना पड़ा। कुछ पैसे भी दे दो उसके इलाज के लिए... मेरी तनख्वाह से काट लेना, और भी पैसे उसने एडवांस ले रखा है, पर ये सब कहने का समय मेरे पास था ही नहीं। मैंने उसे पांच सौ रुपए का नोट पकड़ा दिया। उसका चेहरा चमक उठा। उसे देख मैं निश्चिंत हो गई। मैं आईने के सामने बाल संवारने लगी, तो देखा मेरे चेहरे पर भी चमक आ गई थी। पैसे की जरूरत ने दोनों का चेहरा चमका दिया था।

- अमृता जोशी

क्या फायदा

सबसे बढ़कर लगे स्वार्थ अपना महज
औरों का दुख कभी भी न आए समझ
तब ये बातें बनाने का क्या फायदा
आदमी तब कहाने का क्या फायदा

ज्यादा औरों का हो भी तो कम मानते
खुद को बढ़कर सभी से परम मानते
अपने मद में जो लगते हैं छोटे सभी
खुद के आगे जो लगते हों खोटे सभी
तब ये धुनी रमाने का क्या फायदा

करना जो था सही कर सके वो नहीं
कर्ज जो था कभी का भर सके वो नहीं
मन में मानवता का कोई भाव न हो
करूणा का कोई जब प्रभाव न हो

करना जो था सही कर सके वो नहीं
कर्ज जो था कभी का भर सके वो नहीं
मोल कर्तव्यों का खुद न मालूम हो जब
खुद को ही न पता था क्या करना था कब
औरों को तब बताने का क्या फायदा
आदमी तब कहाने का क्या फायदा

औरों की भी सुनो खुद न बोलो फकत
अब भी चेतो जरा अब भी है पूरा वक्त
इतने से भी अगर ज्ञान लेते नहीं
कुछ न हो पाएगा गर जो चेते नहीं
फिर यूं जीवन बिताने का क्या फायदा
आदमी तब कहाने का क्या फायदा

- विक्रम कुमार

किसको मिलेगी हिटमैन और किंग की भूमिका?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने एक ओर जहां आगामी चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में ही रहने की घोषणा की है तो वहीं दूसरी तरफ टी-20 फॉर्मेट से विराट और रोहित दो दिग्गजों का दौर अब खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन इनकी भरपाई करेगा? क्या मौजूदा समय में जिम्बाब्वे दौरे पर अपने करियर के दूसरे ही मैच में विस्फोटक शतकवीर अभिषेक शर्मा ने यह साबित कर दिया कि वह रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ऐसे कई खिलाड़ियों के नाम विराट और रोहित की जगह लेने के लिए इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चाओं में हैं।

खेल समीक्षकों का कहना है कि भारतीय क्रिकेट की देख-रेख करने वालों पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आगामी टी20 विश्वकप 2026 की है। टीम को अब रोहित और विराट के बिना ही इस फॉर्मेट में खेलना है। अगला विश्वकप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है। भारतीय टीम मेजबानी के साथ-साथ डिफेंडिंग चैंपियन भी होगी। ऐसे में विश्वकप को घर में रखने के लिए एक मजबूत टीम तैयार करनी होगी। टीम प्रबंधन और भविष्य के कप्तान को उसी शैली के खिलाड़ियों की जरूरत है। इसके लिए बीसीसीआई और चयन समिति को कई युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाना होगा। अभी अगर बेंच स्ट्रेंथ देखी जाए तो रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे कई दावेदार हैं तो विराट की जगह ऋतुराज गायकवाड़ ही सबसे बड़े दावेदार हैं। क्योंकि गायकवाड़ जरूरत के हिसाब से कोहली की तरह अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिला सकते हैं। हालांकि इस दौड़ में कई खिलाड़ी हैं।

यशस्वी जायसवालः हाल ही में टी-20 विश्वकप विजेता टीम का हिस्सा रहे 22 साल के जायसवाल भारत के लिए अब तक 17 टी-20 खेल चुके हैं। उन्होंने एक सेंचुरी के साथ 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। ये पारी की शुरुआत में रोहित की ही तरह विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए रोहित की भरपाई के विकल्प के तौर पर चयनकर्ता विचार कर सकते हैं।

ईशान किशनः बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान 32 टी-20 खेल चुके हैं। 2021 में वह टी-20 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी खेले। बीसीसीआई उन्हें लगातार मौके दे रही है, अगर यशस्वी फ्लॉप हुए तो ईशान ही अगले दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं।

अभिषेक शर्माः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी छाप छोड़ने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पिछले टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 204.22 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए और अपनी टीम एसआरएच को फाइनल तक पहुंचाया। अभिषेक बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। फिलहाल जिम्बाब्वे में उन्होंने बतौर भारतीय टीम में अपने करियर के दूसरे ही टी-20 मैच में महज 46 गेंदों में विस्फोटक शतक लगाकर अपनी काबिलियत दिखा दी है।

पृथ्वी शॉः वर्ष 2018 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले पृथ्वी शॉ से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें थीं लेकिन वह उम्मीद पर खरे नहीं उतर सके। हालांकि, पिछले एक साल में उन्होंने सुधार करते हुए घरेलू क्रिकेट में रन बनाना शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में पृथ्वी का कोई तोड़ नहीं, अगर वह अपनी फिटनेस और फॉर्म में बदलाव कर सके तो टी-20 टीम में जगह बना सकते हैं।

केएल राहुलः भारत के लिए टी-20 फॉर्मेट में दो शतक लगा चुके राहुल अब इस फॉर्मेट में धीमी बल्लेबाजी करने लगे हैं। इसी कारण 2021 और 2022 में लगातार 2 वर्ल्ड कप खेलने के बाद उन्हें 2024 में टीम से बाहर रखा गया। अगर राहुल फिर से तेज तर्रार पारी खेलना शुरू कर देते हैं तो रोहित की जगह टीम को उनसे बेहतर ओपनर मिल ही नहीं सकता। इसके अलावा संजू सैमसन, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, टी-20 में ओपनिंग करने की काबिलियत रखते हैं जो वो आईपीएल में दिखा चुके हैं।

शुभमन गिलः कोहली जैसी बल्लेबाजी की बराबरी इस समय अगर कोई कर सकता है तो वह शुभमन हैं। 24 साल के गिल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं। टी-20 में तो उनके नाम एक शतक भी है और हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम को लीड किया और जिताया भी। ऐसे में वे विराट की जगह दावेदार की सूची में शामिल हैं।

ऋतुराज गायकवाडः कोहली के नाम के साथ जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। यह काम गायकवाड पिछले कुछ सालों से आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग के लिए कर चुके हैं। उनकी ही कप्तानी में भारत ने पिछले साल एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। गायकवाड भी भारत के लिए टी-20 शतक लगा चुके हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उन्होंने नंबर 3 पर खेलते हुए जिस अंदाज में नाबाद 77 रनों की पारी खेली उससे कहा जा सकता है कि वे विराट की भरपाई कर सकते हैं।

श्रेयस अय्यरः कोहली की तरह अय्यर मध्यक्रम में भरोसेमंद बल्लेबाजी करते हैं और पिछले आईपीएल सीजन 2024 में कोलकाता को खिताब जिताने वाले कप्तान भी बने। टीम इंडिया वैसे तो श्रेयस को अब टी-20 टीम से बाहर कर चुकी है, लेकिन कोहली जितना अनुभव और भरोसा चाहिए तो श्रेयस का विकल्प भी अच्छा है। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम टी-20 विश्वकप जीतने के बाद घर वापसी कर चुकी है। बीते 29 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला जीतकर भारत के 3 दिग्गजों रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने टी-20 क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। ऐसे में अब इनकी जगह कौन लेगा उसका सभी क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है।

● **आशीष नेमा**

जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म... जिसने 1984 में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

धरा रह गया था राजेश खन्ना-धर्मेंद्र-अमिताभ का स्टारडम

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का 80 के दशक में एक अलग ही जलवा था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में कमाई के कई रिकॉर्ड दर्ज कर दिया करती थीं। उनके अभिनय के भी लोग दीवाने थे और उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी किया करते थे। साल 1984 में आई एक फिल्म ने तो उन्हें बॉक्स ऑफिस का बादशाह ही बना दिया था।

ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने का काम करती थीं। हिंदी सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने वाले इन अभिनेताओं के होते हुए भी जितेंद्र की इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया था। फिल्म की कमाई से मेकर्स भी मालामाल हो गए थे। लव ट्रायंगल वाली इस फिल्म में जयाप्रदा और श्रीदेवी भी अहम भूमिका में नजर आई थीं।

साल 1984 में श्रीदेवी, जयाप्रदा और जितेंद्र स्टारर वो फिल्म तोहफा थी। तोहफा की ना सिर्फ कहानी बल्कि इसके गाने भी काफी हिट हुए थे। दो बहनों वाली इस फिल्म की कहानी में दोनों ही बहने एक ही शख्स से प्यार करने लगती हैं। जितेंद्र की ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। तोहफा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।

अक्षय कुमार ने क्यों बदला था अपना असली नाम? सालों बाद किया सच का खुलासा

नाम बदलने की बताई असली वजह

अक्षय कुमार पिछले कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म आज से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मूवी में उन्होंने सिर्फ कैमियो किया था और हीरो थे कुमार गौरव। यही वो फिल्म थी, जिसकी शूटिंग के दौरान एक्टर को अपना नाम राजीव से बदलकर अक्षय करने का ख्याल आया था।

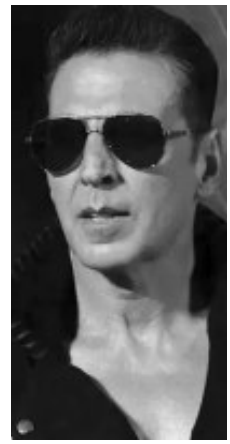

एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि फिल्म (आज) में कुमार गौरव का नाम क्या था? अक्षय। इस तरह मुझे मेरा नाम मिला। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। मेरा असली नाम राजीव है और शूटिंग के दौरान मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि फिल्म में हीरो का नाम क्या है, उन्होंने कहा- अक्षय। मैंने उनसे कहा कि मैं भी अपना नाम अक्षय रखना चाहता हूं।

2012 की सुपरहिट, डेब्यू करते ही एक्टर रातोंरात बना सुपरस्टार

फिल्म के आगे कल्कि से लेकर पठान-जवान तक हैं फेल...

साल 2012 में बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। अपने करियर की पहली ही फिल्म से वह ऑडियंस के चहीते बन गए थे। नया नवेला एक्टर एक ही फिल्म से एक रोल निभाकर एक झटके में एक्टर से रातोंरात सुपरस्टार बन गया था।

आयुष्मान खुराना की ये फिल्म बहुत कम बजट में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि मेकर्स भी मालामाल हो गए थे। आज भी इस फिल्म के आगे प्रोफिट के लिहाज से पठान, जवान से लेकर कल्कि तक फेल है। बॉलीवुड एक्टर

आयुष्मान खुराना ने फिल्म विक्की डोनर से इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्टर की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। विक्की डोनर में आयुष्मान के साथ यामी गौतम लीड रोल में नजर आईं थीं।

विक्की डोनर फिल्म की सफलता ने स्पर्म डोनेशन को लेकर समाज में फैले स्टिग्मा को भी दूर किया था। शूजित सरकार की इस फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बेहद पसंद किया गया। यूं तो रोमांस, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्मों को ही सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन इस फिल्म ने गंभीर विषय को हल्के-फुलके ढंग से जिस खूबसूरती से दर्शकों के सामने पेश किया गया, उसके लिए फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी खूब सराहना की गई थी।

आदमी रिपेयर सेंटर

हमारा मोबाइल महीनेभर से रिपेयरिंग के लिए मोबाइल अस्पताल में भर्ती है। पानी चला जाने के चलते उसकी चार्जिंग होना बंद हो गया था। अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है मोबाइल। रिपेयरिंग सेंटर वालों ने बताया कि चार्जिंग होने लगी, रोशनी भी आ गई लेकिन आवाज अभी नदारद है। मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा।

हमने कहा- बदल दो। बताया गया कि रिपेयरिंग के पहले आधे पैसे जमा करवाने होंगे। हमें लगा कि मोबाइल न हुआ आईसीयू में भर्ती आदमी हो गया। आपरेशन तभी होगा जब एडवांस पैसा जमा करोगे। अस्पताल का डर होता होगा कि आदमी ठीक होकर फूट लिया तो पैसे डूब जाएंगे। लेकिन मोबाइल के तो पैर नहीं हैं। रिपेयरिंग चार्ज से कई गुने ज्यादा का मोबाइल जमा है लेकिन आधा पैसा एडवांस में चाहिए।

खैर, गए। मोबाइल देखा। कमर में कागज बंधा था, पट्टी की तरह। ऑन किया तो सब डाटा, फोटो दिखे। लेकिन आवाज गोल। मोबाइल बेचारा न बोल पा रहा था न सुन पा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था, कहा रहा हो- हमें यहां से ले चलो। हमने उसको प्यार से सहलाते हुए दिलासा दिया- ले चलेंगे बेटा, बस जरा ठीक हो जाओ। ये तो हुई मोबाइल की बात। जो पार्ट खराब हुआ बदल दिया गया। फिर से टनाटन चलने लगेगा। बड़ी बात नहीं कल को आदमी की रिपेयरिंग भी इसी तरह होने लगे। आदमियों के भी रिपेयर सेंटर खुल जाएं।

आदमी रिपेयर सेंटर में हर अंग को बदलने की सुविधा होगी। आदमी मोटा हो गया लेकिन टांगें पतली हैं तो टांगें बदल जाएंगी। सांस की तकलीफ है, फेफड़े नए डाल देंगे। नजर कमजोर है, नई आंख लगवा लो। चेहरे पर दाग हैं, स्किन बदलवा लो। कोई महिला अपने बच्चे को ले जाएगी और कहेगी- भाई साहब बेटे को चीजें जल्दी याद नहीं होती। इसकी मेमोरी चिप बदल दो।

पिता लोग अपनी बेटियों को जमा कराएंगे- इसके दिमाग से प्यार का भूत इरेज कर दो। खानदान की इज्जत का सवाल है। मुकदमों में फंसे लोग अपने खिलाफ गवाह की मेमोरी चिप में अपने हिसाब से यादें ठेल देंगे। बच जाएंगे।

कोई आदमी अपनी औरत के चेहरे की स्किन चमकदार करवाने के भर्ती कराएगा और बाद में फोन करके उसकी आवाज भी थोड़ा धीमे कर देना। चिल्लाती बहुत है। पैसे की चिंता न करो। मैं दे दूंगा।

कोई औरत अपने आदमी को लेकर आएगी- इनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही। फेफड़े बदल दो। अलग से कहेगी- भाई साहब इनकी मेमोरी फाइल से इनकी प्रेमिका का नाम डिलीट कर दो। जब देखो तब उसी को पढ़ते रहते हैं। कोई नेता सैकडों लोगों को लिए आएगा और कहेगा- इनके दिमाग में हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारे नेता की जयकार फीड कर दो। चुनाव आने वाले हैं। फिर तो स्कीम भी चलेंगी। पुराना आदमी लाओ, नया ले जाओ। ऑफर सीमित। भुगतान किस्तों में।

> *आदमी रिपेयर सेंटर में हर अंग को बदलने की सुविधा होगी। आदमी मोटा हो गया लेकिन टांगें पतली हैं तो टांगें बदल जाएंगी। सांस की तकलीफ है, फेफड़े नए डाल देंगे। नजर कमजोर है, नई आंख लगवा लो। चेहरे पर दाग हैं, स्किन बदलवा लो।*

एक्सीडेंट में बहुत टूट-फूट हो गई तो नया शरीर मिल जाएगा अस्पताल में। आदमियों की कास्टिंग, फोरजिंग मौजूद होंगे अस्पतालों में। आदमी के हिसाब से शरीर की मशीनिंग हो जाएगी। मेमोरी और दीगर चीजें चिप में कॉपी करके फिट कर दी जाएंगी। पता चला रिपेयर होने के बाद आदमी के स्वभाव में कोई बदलाव आया तो परिवार वाले कहेंगे- जब से रिपेयर होकर आए हैं तबसे चिड़चिड़े हो गए हैं। पहले शांत रहते थे! या फिर यह कि- रिपेयर होने के बाद सुधर गए हैं। सारे खुराफाती वायरस निकल गए!

कभी-कभी कुछ बवाल भी हो शायद। पता चला कि डॉक्टर ने तमाम हिंदू आदमियों के दिमाग में कुरान डाउनलोड कर दी। मुसलमान लोगों के दिमाग में गीता के श्लोक जमा हो गए। पता चला कोई मार्क्सवादी आदमी रिपेयर होकर आया तो उसके दिमाग से दास कैपिटल गायब है और उसकी जगह एक के बदले चार फ्री तथा ऑफर सीमित, जल्दी करें की तमाम स्कीमें भरी हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था के हिमायती के दिमाग में लाइसेंसी जमाने की योजनाएं कब्जा किए हैं।

सरकारों को भी सुविधा होगी। नई सरकार के आने पर राज्यपाल बदलने नहीं पड़ेंगे। केवल पुरानी पार्टी की चिप निकालकर अपनी पार्टी की चिप लगवा देंगे। अफसरों के तबादलों की जगह उनकी चिपों के तबादले होंगे। सब लोग नई सरकार के मसौदे के हिसाब से काम करने लगेंगे। सरकारों को सहूलियत होगी कि वे मीडिया और बुद्धिजीवियों के दिमाग में अपने हिसाब से चिपें फिट करवा लेंगे। देश चाहे बर्बाद हो रहा हो लेकिन वे देश को बताते रहेंगे- देश का विकास हो रहा है। सबके अच्छे दिन आ रहे हैं।

हम भी क्या-क्या फालतू सोचने लगे हैं आजकल। लगता है दिमाग खराब हो रहा है। रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी।

● **अनूप शुक्ल**

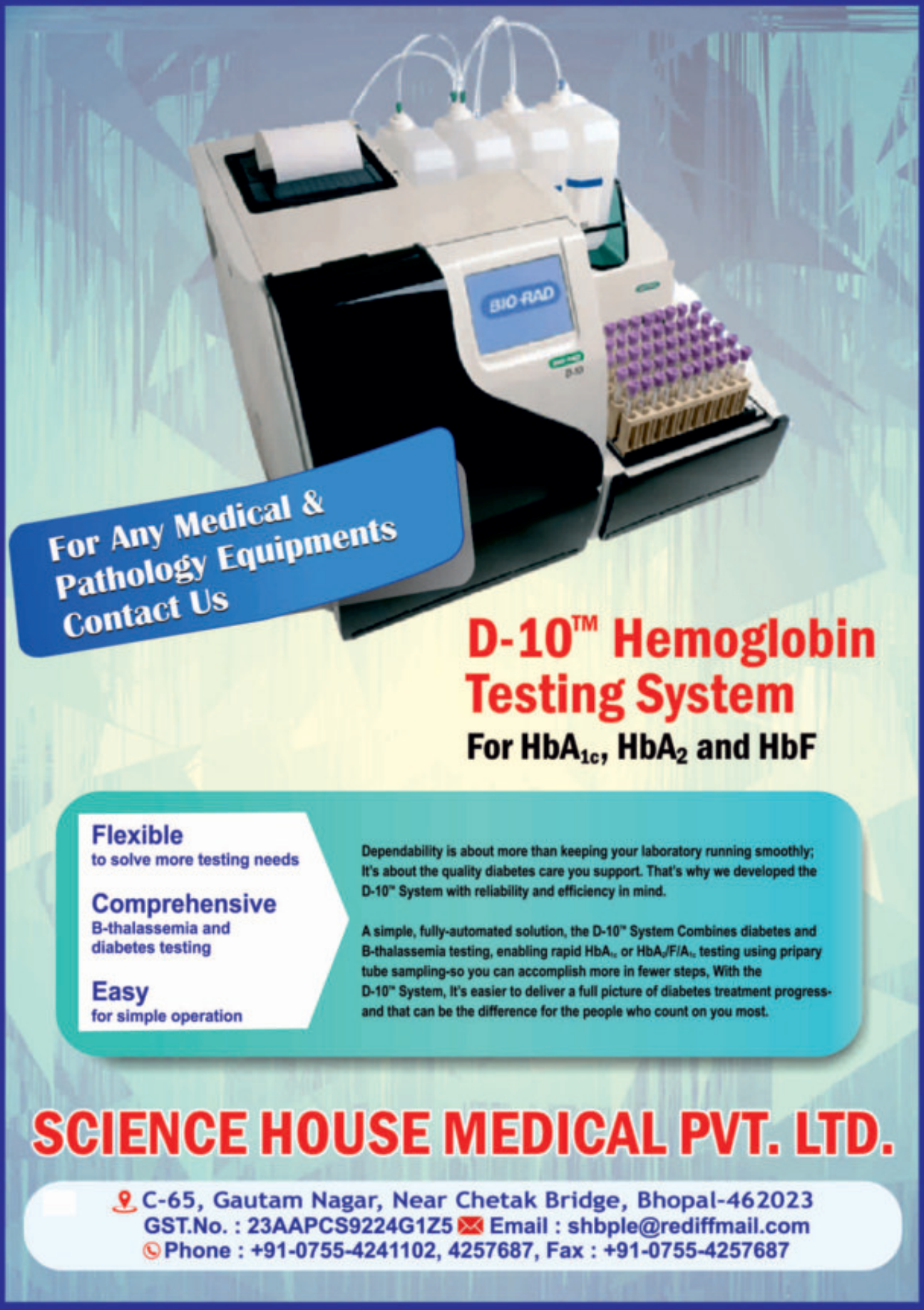

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अब मिलेगी समय पर सहायता...

सड़क, औद्योगिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नि:शुल्क वायु परिवहन सेवा

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा

संचालन प्रारंभ

“ हमारी सरकार प्रदेश की जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ मध्यप्रदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। अब प्रदेश में गंभीर रोगियों को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए उचित समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा ”

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 9111777858

सशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, सम्पर्क करें : 0755-4092530

- आयुष्मान कार्ड धारक को प्रदेश व देश में कहीं भी इलाज हेतु शासकीय और आयुष्मान सम्बद्ध अस्पताल में नि:शुल्क सुविधा
- आयुष्मान कार्ड धारक न होने पर प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क परिवहन सुविधा जबकि प्रदेश के बाहर निर्धारित शुल्क पर परिवहन सुविधा
- सड़कों या औद्योगिक स्थलों पर होने वाली दुर्घटना, हृदय रोगी या जहर से प्रभावित व्यक्ति को अब मिल सकेगा अच्छे चिकित्सा संस्थानों में समय पर इलाज
- अस्पताल द्वारा मरीज की स्थिति की गंभीरता की जांच के उपरांत मिल सकेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा

एयर एम्बुलेंस सेवा की अनुमति

- दुर्घटना प्रकरण में संभाग के अंदर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा
- दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में संभाग के बाहर परिवहन हेतु स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा
- दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य गंभीर प्रकरणों में प्रदेश के अंदर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त द्वारा
- प्रदेश के बाहर गंभीर रोगी या दुर्घटना पीड़ित आयुष्मान कार्डधारी होने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा
- सशुल्क परिवहन हेतु एन.एच.एम. कार्यालय स्तर पर अनुमति मिलेगी

- रोगी/पीड़ित को एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए संजीवनी 108 एम्बुलेंस होगी उपलब्ध
- एयर एम्बुलेंस सेवा में हृदय रोग, श्वास और तंत्रिका संबंधी बीमारियों, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण तथा आपदा की स्थिति को संभालने के लिये प्रशिक्षित चिकित्सक और पेरा मेडिकल स्टाफ रहेगा मौजूद
- हवाई परिवहन के दौरान रोगी/पीड़ित के लिए ₹ 50 लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान

मध्यप्रदेश शासन